हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुक्रवार, 14 मार्च, 1980

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(10)1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	(10)24
अतारांकित प्र न एवं उतर	(10)29
रूल्ज कमेटी की रिपोर्ट पे ा करना	(10)36
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव	(10)36
नेमिंग आफ मैम्बर	(10)37
वैयक्तिक स्पश्टीकरणः—	
1. श्री हीरा नन्द आर्य द्वारा	(10)39
2. मूख्य संसदीय सचिव द्वारा	(10)41
वर्श 1980—81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)42
वैयक्तिंक स्पश्टीकरणः—	
डा. मंगल सैन द्वारा	(10)63
वर्श 1980—81 के बजट पर आम चर्चा (पनुरारम्भ)	(10)64
उपाध्यक्ष द्वारा रूलिंगः—	
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव सम्बन्धी	(10)86

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 14 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सवाल नम्बर 1641 बाबू मूल चन्द जैन जी का है जो इस समय हाउस में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने मुझे यह सवाल पूछने के लिए जबानी कह रखा है लेकिन मेरे पास रिटन अथोरिटी तो नहीं है। अग आप इजाजत दें तो हम यह सवाल पूछ लें ?

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, यह सवाल बहुत जरूरी है इसलिए आप कृपा करके यह सवाल पूछने की इजाजत हमें दे दें ?

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, रूल्ज के अनुसार अगर कोई मैम्बर किसी दूसरे मैम्बर का सवाल पूछना चाहे तो जिस मैम्बर के नाम से सवाल होता है, उसको लिख करके देना पड़ता है। चूंकि बाबू जी को चोट लगी हुई है इसलिए मेरी तरफ से तो इजाजत है, अगर मुख्य मंत्री जी सहमत हों तो जवाब दे दें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): ठीक है जी, यह सवाल पूछ सकते हैं।

Downgrading of Schools

***1641. Sh. Mool Chand Jain:** Will the Chief Minister be pleased to state whether some of the schools upgraded during the period when Ch. Devi Lal was the Chief Minister in the State have been downgraded; if so, the names thereof and the reasons therefor?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमति भाान्ति देवी): जी हां, 29 स्कूलों का स्तर घटाया गया था। ऐसे स्कूलों के नामों की सूची हाउस के टेबल पर रखी जाती है।

श्रीमति भाान्ति देवीः

कारणः स्कूलों के स्तर बढ़ाने के मामले पर पुनः विचार करने पर यह ज्ञात हुआ कि पछिली सरकार ने स्कूलों का स्तर बढ़ाते समय निर्धारित नार्म को दृश्टिगत नहीं रखा। इस त्रुटि ने

कई असंगतियां पैदा कर दी थीं और यह भी पाया गया था कि कई विधान सभा क्षेत्रों के साथ बेइन्साफी की गई थी।

सूची

List of Schools downgraded during 1979&80

Sr.No.	Name of District	Name of School downgraded
		Middle to Primary
1	Bhiwani	1. G.M.S. Sahar 2. G.M.S. Sidhanwa 3. G.M.S. Shampura 4. G.M.S. Kalod (Gudha) 5. G.M.S. Pathrawa 6. G.M.S. Harodi 7. G.M.S. Shashwala 8. G.M.S. Riwasa 9. G.M.S. Alakhpura 10. G.M.S. Jarwa 11. G.M.S. Jhajjara Sheoran

		12. G.M.S. Karu 13. G.M.S. Chandari 14. G.M.S. Miran (Dhani)
2	Hissar	15. G.M.S. Khairmpur 16. G.M.S. Kumahrian 17. G.M.S. Dhabi Kalan
3	Sirsa	18. G.M.S. Bajekan 19. G.M.S. Rupwas 20. G.M.S. Baruwali 21. G.M.S. Jamal 22. G.M.S. Gosainwala 23. G.M.S. Karanwali
High to Middle		
1	Bhiwani	24. G.M.S. Digawa 25. G.M.S. Gopalwas 26. G.M.S. Nandha 27. G.M.S. Chira (to Pry) 28. G.M.S. Behal
2	Hissar	29. G.M.S. Kirdhan

Latest position as it stands on 11th March, 1980.

(a) The downgrading of Schools at Sr. Nos. 1 to 7, 18, 19, 24 to 27 (total 13) was stayed by the High Court till the end of the current academic session.

(b) the downgrading of schools at Sr. Nos. 8 to 10, 15, 16, 20, 28, 29 was stayed/again upgraded by the State Government.

(c) the schools at Sr. Nos. 11 to 14, 17, 21, 22, 23 (total-8) stand downgraded.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, अभी सी.पी.एस. महोदया ने बताया है कि इनमें कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनके लिए हाई कोर्ट में रिट हुई थी और रिट होने के बाद उन स्कूलों में आज भी क्लासिज जारी है क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे दे दी थी, तो क्या सी.पी.एस. महोदया बतायेंगी कि उन स्कूलों को आगे भी जारी रखा जाएगा ?

श्रीमति भाांति देवीः स्पीकर साहब, यह हाई कोर्ट का मामला है। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, 29 स्कूलों को डाउन ग्रेड किया गया। इनमें से 13 स्कूलों को डाउन ग्रेड करने के खिलाफ पंचायतों ने हाई कोर्ट में रिट की थी कि ये अप–ग्रेडिड रहने चाहिएं। हाई कोर्ट ने 30 तारीख तक स्टे दे दी और उन स्कूलों में क्लासिज जारी रही। मैं सी.पी.एस. महोदया से

पूछना चाहता हूं कि जो स्कूल डाउन ग्रेड किए गए थे क्या उनको 30 तारीख के बाद भी अप–ग्रेडिड जारी रखा जाएगा ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसमें ऐसा है कि पहली सरकार में जब श्री हीरा नन्द जी एजूके ान मिनिस्टर थे, जिस दिन इनकी सरकार जाने लगी तो ये जाते–जाते अपने हल्के में 14 स्कूल अप ग्रेड कर गये थे। अध्यक्ष महोदय, यह फैसला हुआ था कि एक एम.एल.ए. के हल्के में, चाहे वह अपोजी ान का हो, चाहे रूलिंग पार्टी का हो, दो–दो स्कूल अप–ग्रेड होंगे। उसके बावजूद भी हमने उनमें से जो स्कूल नार्मज पूरी करते थे या जहां पर उनकी आव यकता थी, वे स्कूल डाउन ग्रेड नहीं किये। इनके हल्के में ऐसे चार स्कूमल हमने रखे। उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट ने उनको सटे दे दी। इसलिए वे स्कूल जारी रखने पड़े। मैं माननीय सदस्यों को फिर भी वि वास दिलाना चाहता हूं कि जो स्कूल बिल्डिंग के हिसाब से या स्टूडैंट्स के हिसाब से कंडी ान पूरी करते हैं उनको जारी रखने की कोि ा ा की जाएगी और हम किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहते हैं।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस निर्धारित नार्मज के अनुसार ये स्कूल अप ग्रेड किये जाने चाहिएं थे, वे निर्धारित नार्मज क्या–क्या हैं ?

श्री अध्यक्षः डा. साहब, ये नार्मज तो अवेलेबल हैं। मैं भी एजूकै ान मिनिस्टर रहा हूं। उन नार्मज की बहुत पब्लिसिटी की गई थी, जैसे कि इतनी एकड़ जमीन होनी चाहिए और इनते स्टूडैंट्स होने चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जो स्कूल डाउन ग्रेड किये गये थे वे नार्मज पूरी नहीं करते थे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उसके बाद जो स्कूल अप–ग्रेड किये गये हैं क्या वे सभी उन नार्मज को पूरी करते हैं ? इसके बाद एक बात उन्होंने यह कही कि मैंने अपने हल्के में अधिक स्कूल अप–ग्रेड कर दिए थे। एक इलाके में तो 15–15 कालेज हों और दूसरे इलाके में एक भी स्कूल न हो तो क्या वहां पर स्कूलों को अप ग्रेड करना इन्साफ के तौर पर जरूरी नहीं थी ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मर्यादा के अनुसार तो इनको हय सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। जो आदमी जाते–जाते अपने ही हल्के में 14 स्कूल अप–ग्रेड कर जाए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है ? क्या इन्होंने दूसरे हल्कों में भी इतने स्कूल अप–ग्रेड किये हैं ? इन्होंने यह भी पूछा कि क्या दूसरे स्कूल नार्मज पूरी करते है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी कोि ा ा यह होती है कि जो कंडी ान्ज पूरी करता हो उसको हम अप–ग्रेड करते हैं लेकिन अगर कहीं

कोई खास जरूरत हो तो ऐसी जगह पर हम कंडी ान में छूट देने की कोि ा ा करते हैं।

(इस समय श्री मूल चन्द जैन सदन में उपस्थित हुए)

Mr. Speaker: Babu Ji, with the permission of the House, I had allowed your question.

Sh. Mool Chand Jain: Thank you, Sir.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सी.पी.एस. महोदया ने सवाल के उतर में एक अनैक ाचर लगाया है जिसके पार्ट (बी) में लिखा गया हैः— "The downgrading of Schools at Sr. Nos. 8 to 10, 15, 16, 20, 28, 29 was stayed/again upgraded by the State Government." उन्होंने यह फरमाया कि स्कूल डाउन ग्रेड इसलिए किये गये क्योंकि वे नार्मज के मुताबिक नहीं थे और बाकायदा रिव्यू करके उनको डाउन ग्रेड किया गया है। फिर इन्होंने (बी) भाग में ही 8—10 स्कूल फिर अप—ग्रेड किए। क्या इसका मतलब यह तो नहीं है कि पहले विन्डिक्टिवनैस दिखाई गई और फिर बाद में किसी पोलिटिकल एप्रोच के कारण उनको दोबारा अप—ग्रेड कर दिया गया ?

Mr. Speaker: It is possible that in the mean while the norms might have been fulfilled.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इसका मतलब तो यह है कि पहले विन्डिक्टिवनैस के कारण डाउन ग्रेड किए गए और बाद में पोलिटिकल ग्राउन्ड पर फिर अप ग्रेड किए गए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि डाउन ग्रेड किए गए स्कूलों में से कुछेक के लिए हमारे पास पंचायतें डैपूटे ान लेकर आई और उन्होंने कहा कि ये–ये स्कूल कंडी ांज पूरी करते हैं और हमारे यहां लड़के भी ज्यादा है इसलिए मेहरबानी करके हमारे स्कूल जारी रखें जायें। इसलिए उन स्कूलों में से जो नार्मज पूरी करते थे और जिनमें लड़कों की संख्या ज्यादा थी उनको हमने जारी रखा है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब न अभी बताया कि जो स्कूल डाउन ग्रेड किए गये हैं वे श्री हीरा नन्द जी ने जाते–जाते अप ग्रेड कर दिए थे और वे नार्मज पूरी नहीं करते थे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि सीरियल नम्बर 14 पर जो मीरान (ढ़ाणी) का स्कूल है, इसको आर्य जी ने अप–ग्रेड नहीं किया था, यह स्कूल मेरी कांस्टीच्युएंसी का है। इसके अलावा 2–3 स्कूल और भी मेरी नालेज में है जो सभी नार्मज पूरी करते हैं लेकिन ज्यों ही सरकार बदली, उन स्कूलों को डाउनग्रेड कर दिया गया। क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह आ वासन देंगे कि जिन स्कूलों के नार्मज पूरें है उनको फिर अप ग्रेड किया जाएगा ?

Mr. Speaker: The Hon'ble Chief Minister has already answered और इन्होंने आ वासन दिया है कि जो पंचायतें नार्मज पूरा करेंगी उनके स्कूल्ज को अपग्रेड करेंगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी सुरेन्द्र सिंह ने जो सवाल पूछा है, उसके जवाब में उन्हें आ वासन देना चाहता हूं कि जिन स्कूलों में नार्मज पूरा होगा, बिल्डिंग्ज ठीक तरह बनी हुई होंगी, उनको अप–ग्रेड करने के लिए जरूर कंसिडर करेंगे। इम्तिहान खत्म होने के बाद जो अगला सै ा भाुरू होगा उस वक्त अपग्रेड करते समय ऐसे स्कूलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः मैं चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिबा से पूछना चाहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से जो यह रसम चली आ रही है कि गांवों में तब स्कूल अपग्रेड होंगे जब गांव वाले जमीन और बिल्डिंग बनाकर देंगे, बिल्डिंग में इतने कमरे बनाकर देंगे तब अपग्रेड करेंगे। लेकिन गांवों के मुकाबले में भाहरों पर इस किस्म की कोई कंडी ान नहीं है और यह गांवों के साथ भेदभाव है। क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिबा इस भेदभाव को खत्म करने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्षः वैसे तो इस सप्लीमैंटरी क्वै चन का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विशय है, इसलिए इस पर रो ानी डाली जाए।

श्रीमति भाांति देवीः यद्यपि सरकार के लिए बड़ा कठिन है कि वे स्कूलों की बिल्डिंग बनाकर दें। तथापि हम भेदभाव को खत्म करने के लिए यह डिसीजन लेने जा रहे है कि गांवों में

पंचायतें तो बिल्डिंग बनाकर देंगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ भाहर वाले भी अपने पैसे से बिल्डिंग्ज बना कर दें।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, जहां तक पहली सरकार और इस सरकार द्वारा स्कूल अपग्रेड करने का सवाल है, इन दोनों सरकारों ने मेरे हल्के मे केवल दो स्कूल अपग्रेड किए हैं लेकिन दूसरे इलाकों मे कहीं पर पांच, कहीं पर छः स्कूल अपग्रेड .....

श्री अध्यक्षः इसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है, आप अपने हल्के के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री भले रामः मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं, उनमें से अपोजी ान के हल्कों में कितने हैं ?

श्री अध्यक्षः केवल इस सवाल से सम्बन्धित सवाल पूछें। (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं आन ए प्वांयट आफ पर्सनल एक्सप्लेने ान पर बोलना चाहता हूं।

Mr. Speaker: No personal explanation is allowed during the question hour. I will give you time for personal explanation after question hour.

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि जो स्कूल नार्म्ज पूरे कर लेंगे उनको अपग्रेड

कर देंगे। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस लिस्ट पर जो स्कूल दर्ज है, इनमें से जो नार्म्ज पूरा कर लेंगे उन्हीं को अपग्रेड करेंगे या इस लिस्ट के इलावा बाहर के स्कूल जो नार्मज पूरा करेंगे उनको भी कंसिडर किया जाएगा ?

चौधरी भजन लालः सारी स्टेट में जो जो स्कूल्ज नार्म्ज पूरा कर लेंगे, उनको कंसिडर किया जाएगा। जिस एरिए में, जिस एम.एल.ए. के हल्के में पहले से स्कूल कम हैं या किसी एरिए के साथ ज्यादती हुई हो, उसको इन्साफ देंगे और सब के साथ यकसां बर्ताव किया जाएगा।

Repairs of Government Primary, Middle, High and Higher Secondary Schools

***1487@Ch. Ram Lal Wadhwa, Ch. Ude Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the tehsil-wise total number if any, of Government Primary, Middle, High and Higher Secondary School buildings which have not so far been handed over by the Education Department to the P.W.D. (B&R) for repair and maintenance in the State; and

(b) the tehsil-wise total number of schools as referred to in para(a) above being run in private buildings together with the steps taken or proposed to be taken by the Government for their repairs?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमति भाान्ति देवी):

(क) सूची विधान सभा के पटल पर रखी जाती है। (अनुबन्ध–1)

(ख) किराये की प्राईवेट बिल्डिगों में चलाये जा रहे स्कूलों की संख्या की सूची विधान सभा के पटल पर रखी जाती है। (अनुबन्ध–2) यह मुख्यतः भाहरी इलाकों में हैं और क्रमांक (क) पर अंकित स्कूलों की सूची में भाामिल हैं। इन स्कूलों को छठी पंचवर्शीय योजना में सरकार के नियंत्रण में लेने के लिए निर्णय लिया है। इन स्कूलों के भवनों की मुरम्मत आदि का कार्य इन स्कूलों के भवनों को सरकार के नियंत्रण में लिये जाने के प चात् ही राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

अनुबन्ध–1

उन स्कूलों की सूची जिन्हें अभी तक लोक निर्माण विभाग की पुस्तकों पर नहीं लिया गया है।

जिले का नाम	तहसील का नाम	स्कूलों की संख्या			
		प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	उच्चतर माध्यमिक

अम्बाला	अम्बाला	263	44	19	
	जगाधरी	232	5	7	
	नारायणगढ़	171	24	13	
भिवानी	भिवानी खेड़ा	28	6	11	
	भिवानी	92	18	12	
	दादरी	107	23	29	1
	लोहारू	99	16	20	
फरीदाबाद	बलबगढ़	138	7	6	5
	पलवल	146	10	9	
गुड़गांव	गुड़गांव	213	11	3	
	फिरोजपुर झिरका	146	4	7	
	नूंह	103	7	3	
हिसार	फतेहाबाद	129	30	23	
	हांसी	66	25	36	
	हिसार	98	46	25	

जीन्द	जीन्द	118	18	20	
	नरवाना	107	19	29	
	सफीदों	52	9	12	
करनाल	करनाल	347	42	24	
	पानीपत	134	15	19	
कुरूक्षेत्र	कैथल	256	29	33	
	कुरूक्षेत्र	321	19	10	
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	154	20	20	
	नारनौल	193	25	26	
	रिवाड़ी	230	10	6	
रोहतक	बहादुरगढ़	32	9	8	
	झज्जर	175	23	37	
	रोहतक	78	14	28	
सिरसा	डबवाली	282	11	12	
	सिरसा	180	32	15	

सोनीपत	गोहाना	49	23	11	
	सोनीपत	150	10	3	
जोड़		**4689**	**604**	**535**	**1—5829**
अनुबन्ध—2					
उन स्कूलों की सूची जो प्राईवेट भवनों में चल रहे हैं।					
अम्बाला	अम्बाला	8			
	कालका	1			
	जगाधरी	6			
	नारायणगढ़	1			
फरीदाबाद	फरीदाबाद	2			
	पलवल	6			
	बल्लभगढ़	1			
भिवानी	भिवानी	12			
	भिवानी खेडा				
	दादरी				

	लोहारू				
गुड़गांव	गुड़गांव	1	1		
	फिरोजपुर झिरका				
	नूंह				
हिसार	फतेहाबाद				
	हांसी	4			
	हिसार	4	1		
जीन्द	जीन्द		1		
	नरवाना	1			
	सफीदों				
करनाल	करनाल	11	1		
	पानीपत	5			
कुरूक्षेत्र	कैथल	1			
	थानेसर	4		1	
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़				

	नारनौल	1			
	रिवाड़ी	3			
रोहतक	बहादुरगढ़				
	झज्जर	1			
	रोहतक	4			
सिरसा	डबवाली				
	सिरसा	3		1 (4 कमरे)	
सोनीपत	गोहाना				
	सोनीपत	1		1	
जोड़		**81**	**4**	**3**	**2—90**

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी साहिबा से जानना चाहता हूं कि जिन प्राईवेट स्कूलों को सरकार टेक ओवर करेंगी, क्या इसके लिए अब तक कोई कार्यवाही की है, अगर की है तो अब तक कितने स्कूल लिए हैं और कितने बाकी रहते हैं और जो बाकी रहते हैं उनको कब तक ले लिया जाएगा ?

श्रीमति भ्रांति देवीः मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बता देना चाहती हूं कि लैंड एक्विजी ान एक्ट 1894 के सैक ान 4 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। 12 स्कूल भिवानी जिले के ले लिए गए हैं और 16 स्कूल जिला करनाल के लिए जाने विचाराधीन हैं।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने अपने जवाब में बताया है कि इन स्कूलों को छठी पंचवर्शीय योजना में सरकार के नियंत्रण में लेने का निर्णय किया गया है। क्या आप बतायेंगी कि 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 में किन–किन भाहरों और गांवों में कितने कितने स्कूलों की बिल्डिग्ज की रिपेयर की गई है ?

श्रीमति भ्रांति देवीः इस बारे में इस वक्त मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिबा बतायेंगी कि भिवानी जिले में कितने स्कूलों को बिल्डिग्ज बनाने के लिए टेक–ओवर किया गया है ?

श्रीमति भ्रांति देवीः इन स्कूलों के नाम मेरे पास इस वक्त नहीं है। अगर मैम्बर साहब नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफ्त पूछना चाहूंगा कि वैसे तो सारे स्कूल सरकारी हैं लेकिन

कई मिडल स्कूल या हाई स्कूल सरकारी कागजात में लिखे हुए नहीं हैं। इन मिडल और हाई स्कूलों की बिल्डिंग्ज, किसी टैक्नीकल प्वांयट के बेसिज पर पी.डब्ल्यु.डी. (बी.एंड.आर.) को नहीं दी गई हैं। क्या सरकार ऐसे स्कूलों को जो हरियाणा में हैं, पी. डब्ल्यू.डी. के अंडर लाने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों की बिल्डिंग्ज को टेकओवर करने का ताल्लुक है, सबसे पहले तो गांव वालों को प्राईमरी या मिडल स्कूल की बिल्डिंग बना कर पूरी करनी पड़ती हैं। अब तक तो यह प्रथा है कि गांव वालों को भवन बनाकर देना पड़ेगा लेकिन जिन हाई स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता है, उनको टेक–ओवर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर गांव वाले मिडल स्कूल की बिल्डिंग बनाने की हिम्मत करते हैं तो बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन बाद में उसकी मैन्टेनेंस करना उनके लिए बड़ा मुि कल होता है, खास तौर पर उस वक्त मुि कल होता है जब हाई स्कूल बन जाता है।

चौधरी भजन लाल: अगर गांव वालों की हालत खस्ता है तो वहां सरकार ही बिल्डिंग ठीक करवायेगी।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हाई स्कूल्ज पूरी कंडी ान्ज फुलफिल करते हैं, भवन बन गए हैं और सरकार

ने अपग्रेड करके उनको मिडल से हाई स्कूल भी बना दिया है, क्या ऐसे हाई स्कूलों की बिल्डिंग्ज को पी.डब्ल्यू.डी. के अंडर लाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्षः इन्होंने कहा है हाई स्कूल्ज की बिल्डिंग्ज को जल्दी ही टेकओवर करेंगे।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, रोहतक जिले में साम्पला हाई स्कूल है और इस स्कूल के बारे में चौधरी मेहर सिंह राठी को भी मालूम हैं। गांव वालों ने इस स्कूल की बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई हुई है लेकिन इसकी छत टूट रही है। क्या चीफ पार्लियामैटरी सैक्रेटरी साहिबा आ वासन देंगी कि इस स्कूल की बिल्डिंग को पी.डब्ल्यू.डी. के तहत कर दिया जाएगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस स्कूल के बारे में अभी बताया कि उसकी हालत खराब है, छत गिर चुकी है, उसे सरकार जरूर टेक ओवर कर लेगी।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैंटेनेन्स के लिए एक बिल्डिंग फंड होता है लेकिन गवर्नमैंट ने उसे कामन पूल में ले लिया है जबकि होना यह चाहिए कि जिस स्कूल के लिए वह बिल्डिंग फंड है उसी की मैंटेनैंस उससे होनी चाहिए। क्या सरकार इस मसले पर दोबारा विचार करेगी ?

श्रीमति भाांति देवीः स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमने पूरा पैसा नहीं लिया है। केवल 60

परसैंट पैसा लिया है। 40 परसैंट पैसा अब भी स्कूलों के पास है। उससे भी छोटी मोटी रिपेयर का काम वे करवा सकते हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सी.पी.एस. महोदया ने जो लिस्ट (अनैक्सचर–1) सदन की मेज पर रखी है उससे पता चलता है कि 90 परसैंट प्राईमरी स्कूल, 70 से 80 परसैंट तक मिडल स्कूल और कम से कम 50 परसैंट हाई स्कूल पी.डब्ल्यु.डी. (बी.एण्ड.आर.) को हैन्ड ओवर नहीं हुये हैं। स्पीकर साहब, जिन गांवों मे सेम हैं और लोगों ने बहुत पैसा लगाकर बिल्डिंग तैयार की है वहां तो बिल्डिंग अगले पांच सला तक ठीक हालत में नहीं रहेगी। क्या सी.पी.एस. महोदया बताएंगी कि वे कब तक इन स्कूलों को हैन्ड ओवर करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमति भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, 25–7–79 को हमने यह निर्णय लिया था कि जिन स्कूलों की बिल्डिंग्ज डैमेज्ड हैं बाढ़ के कारण या अन्य किसी कारण से, उनकी भीघ्राति ीघ्र मुरम्मत कराई जाएगी। इस काम के लिए 45 लाख रूपये की रा ि ा नि ि चत की गई थी। इसमें से 20 लाख रूपये की मंजूरी हम दे चुके हैं और 25 लाख रूपया अभी बाकी पड़ा है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो यह था कि बाकी स्कूलों को कब तक हैन्ड ओवर करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमति भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सत्य है कि इस कार्य में अभी तक हम वि ोश रूचि नहीं ले पाए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि यदि हम अधिक कमरे न बनवा सकें तो कम से कम बिल्डिंग्ज की रिपेयर तो होनी ही चाहिए। हम जल्दी से जल्दी और अधिक बिल्डिंग्ज की मुरम्मत करवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि जिन गांवों की हालत खस्ता है उनके मिडल स्कूलों की बिल्डिंग्ज को टेक ओवर कर लिया जाएगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, 90 परसैंट गांव ऐसे है जिनकी हालत खस्ता है। क्या वे बताएंगे कि ऐसे सब गांवों की मिडल स्कूलों की बिल्डिंग्ज को टेक आवेर करने का सरकार का इरादा है ?

श्रीमति भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताऊंगी कि इतनी जल्दी यह समस्या हल होने वाली नहीं है। फिर भी हम कोि ा ा करेंगे कि अधिक से अधिक कदम इस ओर उठाए जाएं।

डा. मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने फरमाया कि स्कूल बिल्डिंगज की मुरम्मत के लिए उन्होंने 45 लाख रूपया मख्सूस किया है और साढ़े ग्यारह महीने में 20 लाख रूपया उसमें से खर्च किया है। आज मार्च की 14 तारीख है और फाईनैन्- ाल इयर क्लोज होने

को है, केवल 16 दिन बाकी रहते हैं। तो मैं आपकी मारफत चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रटरी साहिबा से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन 16 दिनों में 25 लाख रूपया खर्च कर लेंगी ?

श्रीमति भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यह बजट लैप्स नहीं होता। हम अगले साल में भी इसे खर्च कर सकते हैं। (विघ्न)

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, सी0पी0एस0 महोदया ने बताया कि बिल्डिंग फंड का 40 परसैंट पैसा स्कूलों में रहता है। क्या वे बताने की कृपा करेंगी कि इस 40 परसैंट पैसे का खर्च करने की हैडमास्टर को पावर होती है या उसे डी.ई.ओ. की परमि ान लेनी पड़ती है ?

श्रीमति भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, वह डी.ई.ओ. से परमि ान लेकर खर्च कर सकता है।

श्री ओम प्रका ाः क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिबा बताएंगी कि स्कूलों की रिपेयर करवाने के मामले में क्या लड़कियो ंके स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्रीमति भाांति देवीः अव य प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री गुलजार सिंहः क्या सी.पी.एस. साहिबा बताएंगी कि जिन गांवों में स्कूलों की बिल्डिंग्ज कम्पलीट हो चुकी है ओर गांव वाले स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए साल भर का खर्चा गवर्नमैंट

को ऐडवांस में देने को तैयार हैं क्या वहां के स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा ?

श्रीमति भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर ऐसा कोई केस बताएंगे जहां ग्राम पंचायत वाले पूरी रा ि। देने को तैयार हैं तो पहली अप्रैल से हम ऐसे स्कूल्ज को अपग्रेड करने के लिए तैयार है।

चौधरी उदय सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मसूदपुर ऐसा गांव हैं जहां स्कूल की बिल्डिंग तैयार हैं ओर पंचायत वाले पैसा देने के लिए भी तैयार हैं।

श्रीमति भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए बता देना चाहती हूं कि प्राईमरी से मिडल स्कूल अपग्रेड कराने के लिए ग्राम पंचायत को 51690 रूपये और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड कराने के लिए 69612 रूपये जमा करवाने पड़ेगे।

Supply of Diesel to Industrial Units

***1504. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) whether any arrangement for the supply of diesel to those industrial units which have installed diesel engines

has been made; if so, the number of such industrial units in Faridabad; and

(b) if reply to part(a) above be in the affirmative, whether any complaint of malpractices in the distribution of diesel to the industrial units referred to in part (a) has been received; if so, the details thereof together with the action taken thereon?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(ए) हां। फरीदाबाद मे कुल 278 औद्योगिक ईकाईयां डीजल प्राप्त कर रहीं है।

(बी) नहीं।

डा. मंगल सैन: क्या मंत्री जी बताएंगे कि 278 इकाईयों को कितनी मिकदार में डीजल मिल रहा है ?

Ch. Gajraj Bahadur Nagar: Sir, it varies from factory to factory. For example, in the month of January, 1980 the number of units to whom H.S.D. was issued, was 198. The quantity issued to performance, out of available stocks of 10%. The total quantity issued was 42600 litres. Similarly, in February, 1980, the number of units to whom H.S.D. was issued, was 261. The quantity issued to each unit varies from 200 to 1400 litres per unit, keeping in view their performance, out of available stock of 10%. The total quantity issued was 72200 litres.

डा. मंगल सैनः क्या मंत्री जी बताएंगे कि प्रदे ा भर में इसी प्रकार डीजल दैने की नीति हैं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः यह नीति सारे हरियाणा में लागू हैं। (विघ्न) यह नीति सारे प्रदे ा के लिए हैं किसी एक जगह के लिए नहीं।

श्री अध्यक्षः यह सवाल पर्टिकुलरली फरीदाबाद के बारे मतें पूछा गया है।

डा. मंगल सैनः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रदे ा में जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं क्या सबके लिए डीजल की परसैन्टेज फिक्सड है ?

चौधरी गजराज बाहदुर नागरः जी हां। पांच परसैन्ट सारे प्रदे ा के लिए और दस परसैन्ट अकेले फरीदाबाद के लिए।

श्री अध्यक्षः इनका पूछने का मतलब यह है कि इन्डस्ट्रियल यूनिट्स को कितने परसैन्ट देते हो। I think 5% diesel is reserved for the Industrial Units.

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में 60 परसैन्ट डीजल ब्लैक में क्यों बेचा जा रहा हैं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इस सप्लीमैन्टरी का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, सम्बन्ध है। हरियाणा में 60 परसैन्ट डीजल ब्लैक में बि रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः क्या कोई ऐसी ऐजन्सी है जिससे यह पता लग सके कि इतने परसैन्ट डीजल ब्लैक में बिक रहा है ?

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, ...

चौधरी गजराज बहादुर नागरः यह बिल्कुल गलत कह रहे है।

श्री अध्यक्षः इन्होंने जो सवाल पूछा है यह सारा एक्सपंज कर दिया जाये।

श्रीमति डा. कमला वर्माः मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि 10 परसैन्ट डीजल फरीदाबाद को दे रहे हैं और 5 परसैन्ट सारी स्टेट को दे रहे हैं। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहती हूं कि यह अन्तर क्यों किया जा रहा है जबकि यमुनानगर और जगाधरी भी इन्डस्ट्रियल काम्पलैक्स हैं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, इस सवाल की तरफ मैं सारे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां पर जनरेटिंग सैट्स नहीं लगे हुए हैं वहां पर डीजल नहीं दिया जाता। फरीदाबाद में 104 जनरेटिंग सैट्स लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा फैक्टरियां लगी हुई हैं इसलिए वहां ज्यादा डीजल दिया जा रहा है। डीजल हिस्टोरिकल

परफारमैन्स के बेसिज पर देते हैं। फरीदाबाद में कुछ फैक्टरीज डायरेक्ट गवर्नमैंट आफ इंडिया से भी डीजल ले रही हैं। जैसे गुड ईयर इंडिया लिमिटिड, आई ार ट्रैक्टर और हैदराबाद एसबैस्टोज आदि। वे हिस्टोरिकल परफारमैन्स के बेसिज पर ही ले रही हैं। हिस्टोरिकल परफारमैन्स के बेसिज पर पिछले साल से ही सैन्टर से तेल की सप्लाई हो रही है। जहां तक जगाधरी और यमुनानगर का सवाल है, वहां पर कुल 11 जनरेंटिंग सैट्स हैं जबकि फरीदाबाद में 104 हैं। हिस्टोरिकल परफारमैन्स के मुताबिक 8 लाख 28 हजार लिटर जगाधरी यमुनानगर को और तीस लाख लिटर फरीदाबाद को दिया जा रहा है। फरीदाबाद में 104 जनरेंटिंग सैट्स हैं और सबसे बड़ा इन्डस्ट्रियल काम्पलैक्स है इसलिए अधिक डीजल दिया जा रहा है।

श्रीमति डा. कमला वर्माः स्पीकर साहब, यमुनानगर में एस.डी.ओ. के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला हुआ था कि केवल चार घन्टे इन्जन चलाने के लिए तेल दिया जायेगा। इस तरह से तो महीने में बहुत कम समय इंजन चलेगा जिसके कारण उनकी प्रोडक ान बहुत कम होगी। क्या मंत्री जी उनको अधिक डीजल देने की कृपा करेंगे।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीजल की कमी है। हिस्टोरिकल परफारमैन्स के बेसिज पर डीजल दिया जा रहा है और डी.सी. लैवल पर बाकायदा कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी में डी.एफ.ओ. डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज

आफिसर तथा एक इन्डस्ट्रीज एसोसिए ान का नुमाइन्दा होता है, तब डीजल की डिस्ट्रीब्यू ान की जाती है।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्षः यह सारा सवाल एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, सोनीपत में केवल पांच परसैन्ट डीजल दिया जा रहा है जबकि वहां पर काफी फैक्टरियां हैं। अभी मंत्री महोदय ने भी बताया है कि डी.सी. लैवल पर एक कमेटी बनी हुई है वह डीजल की डिस्ट्रीब्यू ान करती है लेकिन सोनीपत में अकेला डी.एफ.ओ. ही डीजल बांट देता है। मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि जहां पर जनरेटिंग सैट्स लगे हुए हैं क्या वहां पर अकेला डी.एफ.ओ. ही डीजल बांटता है या कोई कमेटी बनी हुई है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि डी.सी. लैवल पर बाकायदा कमेटी बनी हुई है। डीजल डिस्ट्रीब्यू ान के बारे में डी.सी. जिम्मेवार है। सरकार की तरफ से डी.सी. को डायरेक्टिव गया हुआ है कि वह एक कमेटी बनाये और वह कमेटी ही डीजल की एलोके ान करें।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि फरीदाबाद में कुल 278 यूनिटस डीजल प्राप्त कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब से उन्होंने इस पोर्टफोलियों को सम्भाला है तब से आज तक कितनी और

इकाईयां (यूनिटस) बढ़ायी हैं ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सिकी इंडस्ट्रियल यूनिट को डीजल देने का क्या कोई क्राइटेरिया या पालिसी बनाई हुई है या मिनिस्टर महोदय की अपनी डिस्कि ान पर हैं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डीजल की एलोके ान मैं नही करता इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पालिसी के बारे में डी.सीज. को इन्स्ट्रक ांज जारी की हुई हैं। डी.सी. कमेटी कांस्टीयूट करता है, वह कमेटी परफारमैन्स के बेसिज पर जजमेंट करती है कि किस को कितना डीजल एलोकेट करना है।

श्री मांगे राम गुप्ताः मंत्री जी का जवाब आया है कि फरीदाबाद में 278 यूनिटस को डीजल एलोकेट किया जाता है। डीजल अलाट करने की नीति भी बतायी है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करैंगे कि भूतपूर्व इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर की सिफारि ा के कारण उनको यह डीजल ता नहीं दिया जा रहा हैं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, जो भी इन्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट की डिमांड होती है, उस डिमान्ड के मुताबिक परफारमेन्स देखते हैं। दूसरे हम यह भी देखते हैं कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट की कितनी आव यकता है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट ने हम

से जो मांग की उसको कंसिडर करने के बाद ही पालिसी बनायी गई है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि जनरेटिंग सैटस के मुताबिक डीजल दिया जाता है और इन्होंने अभी यहां यह भी बताया है कि हर डी.सी. को डीजल डिस्ट्रीब्यू ूान की पालिसी बना कर भेज दी है। मैं मंत्री महोदय से यह पालिसी जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास जनरेटिंग सैट्स हैं और बराबर डीजल मिलता है क्या उन फैक्ट्रीज की प्रोडक ान या रैवेन्यू के हिसाब को भी देखा जाता है या नहीं ? Speaker Sahib, performance does not include all the criteria. (Interruptions)

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, सुरेन्द्र सिंह जी ने जो सवाल पूछा है वह यह है कि जिनको डीजल अलाट किया जाता है उनकी परफारमेन्स को भी चैक किया जाता है या नहीं। वे जितना डीजल लेते हैं उसके हिसाब से प्रोडक ान भी करते हैं या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि डीजल देने के बाद उसकी प्रोडक ान को भी चैक किया जाता है या नहीं कि वे कितनी प्रोडक ान करते हैं और कितना रैवेन्यू सरकार को आता है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से जो डायरैक्टिव आया है उसके हिसाब से

डीजल की अलाटमैंट की जाती है उस डायरैक्टिव को मैं सदन के सामने पढ़ देता हूं। डीजल अलाट करने के 3 क्राइटेरिया हैं:—

(i) Keeping in view the local conditions, the Deputy Commissioners may at their discretion earmark some quantity of diesel for supply to the Industrial Sector. This should in no case exceed 5% of the allocation of the district concerned except in the case of Faridabad district where a large numbr of units are located and the allocation may go upto 10%. गवर्नमैंट आफ इण्डिया की तरफ से स्पेसिफिकली इन्स्ट्रक ान आई हुई हैं कि फरीदाबाद वालों को डीजल ज्यादा से ज्यादा सप्लाई किया जाये।

(ii) The export oriented industrial units set up for the last 2-3 years which export more than 10% of their production should be accorded proiority in the matter of supply of H.S.D.

(iii) The continuous processing industrial units which are engaged in the manufacturing of essential commodities of daily consumer needs should also be accommodated to the extent possible to avoid loss of production and rise in prices.

These were the main criteria.

श्री मूल चन्द जैनः भाई सुरेन्द्र सिंह जी ने जो सवाल पूछा है वह यह है कि जिए फैक्ट्री को डीजल का कोटा दिया जाता है, क्या उस फैक्ट्री की प्रोडक ान की इवैल्यूऐ ान की

जाती है या वैसे ही कोटा दे दिया जाता है ? क्या वह फैक्ट्री उस डीजल को ब्लैक में तो नहीं बेचती है ? क्या सरकार इसको चैक करती है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः हमारे नोटिस में अभी तक तो कोई ऐसी ि ाकायत नहीं आई है कि किसी फैक्ट्री वाले ने डीजल ब्लैक में बेचा हो।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मंत्री महोदय ने बताया कि फरीदाबाद में कुल 104 जनरेटिंग सैट्स हैं और 278 इन्डस्ट्रियल यूनिटस को जो डीजल दिया जा रहा है, क्या वह पिछले इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर की सिफारि ा पर दिया जा रहा है ?

Ch. Gajraj Bahadur Nagar: The Director of Industries also assesses the annual requirement of diesel according to the capacity of generating sets. Total annual capacity workds out to about 41000 K.L. Out of this, 30000 K.L. is for Faridabad district alone. This does not include the generating sets with large and medium scale industries. This was the demand and recommendation of the Director of Industries.

डा. बृज मोहन गुप्ताः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जगाधरी और यमुनानगर के बारे में जो यूनिटस की तादाद बताई है, क्या यह इन्फर्मे ान इनके पास पुरानी है या नयी हैं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, मेरे पास यह लेटैस्ट इन्फर्मे ान है। अगर किसी ने 2–4 या 10 दिन में कोई नया यूनिट लगार लिया हो और उसने डीजल की मांग न की हो तो मुझे उसका पता नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, अधिक इन्डस्ट्रीज के जिहाज से फरीदाबाद के बाद सोनीपत जिले का नम्बर आता है। मैं आपके जरिए मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि सोनीपत में कितना डीजल दिया जाता है और वहां पर कितने जनरेटर सैटस हैं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, सोनीपत में 73 जनरेटिंग सैटस हैं और उनको 3290400 लीटर डीजल दिया जा रहा है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हिस्टोरिकल परफोरमेन्स के बेसिज पर डीजल अलाट करते हैं। फरीदाबाद के अन्दर जनरेटिंग सैटस का नम्बर ज्यादा है इसलिए वहां पर ज्यादा डीजल दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर सारी स्टेट में हिस्टोरिकल परफोरमेन्स के आधार पर डीजल देते हैं तो फरीदाबाद में 10 परसैन्ट कोटा ज्यादा देने का क्या कारण है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, डा. साहब ने मेरा जवाब ध्यान से नहीं सुना। मैंने जवाब में साफ तौर पर

कहा था कि जिन लोगों को सैन्टर से डायरैक्ट डीजल मिल रहा है उनका हमारे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। हम उनके लिए न डीजल लाते हैं और न ही पहुंचाते हैं। वहां सैन्टर की तरफ से उन्हें परफोरमैन्स बेसिज पर डीजल मिल रहा है।

श्री अध्यक्षः आपने जो कुल कोटा बताया है, क्या उसमें डायरैक्ट आने वाला डीजल भी इनकलूडिड है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः जी हां।

Residential Houses

***1605. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state:-

(a) the number of houses built in the State for the Officers, Class-III and Class-IV employees, separately; and

(b) the category-wise amount spent on the construction of aforesaid buildings, separately?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(ए) अधिकारियों के लिए 175 भवन, तृतीय श्रेणी के लिए 249 एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए 135 भवन, 1—11—1966 से लेकर वर्तमान तिथि तक बनाए गए हैं। उक्त रिहाय ी भवन हरियाणा राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिला स्तर

पर एल.आई.जी एवं एम.आई.जी. योजना के अधीन निर्माण किये गये हैं।

(बी) 1–11–1966 से वर्तमान तिथि तक 52.57 लाख रूपए की रा ि ा अधिकारियों के रिहाय ी भवनों के निर्माण के लिए, 36.86 लाख रूपय तृतीय श्रेणी एवं 14.82 लाख रूपये की रा ि ा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिहाय ी भवनों के निर्माण हेतु खर्च की गई है।

कामरेड भांकर लालः मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि काफी सालों से सरकार ने अपने कर्मचारियों से यह वायदा किया हुआ है कि वह उनको मकान बना कर देगी और इस बात के लिए उनसे पैसे भी काट रहें हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने सालों के अन्दर–अन्दर तमाम कर्मचारियों को, जिनको रिहाय ी प्लाट दिये गये हैं, उन्हें भी मकान बनाकर दिये जा सकेंगे जिन्हें वे अपना कह सकें ?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, इस सवाल का मुझसे सम्बन्ध नहीं है। प्लाट्स देने और उनको मकान बनाकर देने का काम अलग है। मकान बनाकर देने के लिए एक हाउसिंग कापोर्रे ान बनी हुई है। पी.डब्ल्यू.डी. यह काम नहीं करता।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अधिकारियों के लिए 175 मकान, 249 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एवं 135 मकान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचरियों

के लिए अब तक बनाए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन मकानों से कितने प्रति ात एम्पलाईज को मकान मिल रहे हैं ?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, मकान अलाट करने का काम जनरल एडमिनिस्ट्रे ान करता है। यह जो मकान मैंने बताए हैं, इनकी अलाटमैंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक कमेटी बनी हुई होती है जो अलाट करती है। मकान बनाना पी.डब्ल्यू.डी. का काम है लेकिन उसको आगे अलाट करना डी.सी. का काम है।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन मकानों से कितने प्रति ात एम्पलाईज को मकान मिल पाते हैं ?

कंवर राम पाल सिंहः हमारा काम तो सिर्फ बनाना है, जितनी रकम अलाट होगी, हम उसी हिसाब से मकान बना देंगे।

श्री अध्यक्षः इनका काम तो सिर्फ कन्स्ट्रक्ट करना है। बाकी काम तो दूसरे डिपार्टमैंट का है।

श्री जय नारायण वर्माः मैं मंत्री महोदय का ध्यान उनके द्वारा दी गयी सूचना की ओर दिलाना चाहता हूं। अधिकारियों के लिए 175, तृतीय श्रेणी के लिए 249 और चौथी श्रेणी के लिए 135 मकान बनाए गए हैं। एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम छोटे और पिछड़े हुए वर्ग की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर चौथी श्रेणी के लिए सबसे कम मकान यानी केवल 135 मकान

बनाए गए हैं। इसी तरह से 52.57 लाख रूपये अधिकारियों के रिहारय ाी भवनों के लिए, 36.86 लाख रूपये तृतीय श्रेणी के लिए और केवल 14.82 लाख रूपए की रा ि ा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिहाय ाी भवनों के निर्माण हेतू खर्च की गयी है। क्या यह बात उनकी घोशित नीति के विरूद्ध नहीं जाती है ?

(इस प्र न का उतर नहीं दिया गया।)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने 1–11–1966 से 1980 तक केवल 135 रिहाय ाी मकान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बनाए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एल.आई.जी. और एम.आई.जी. स्कीम्ज के तहत क्लास फारे के लिए रा ि ा बढ़वाने की को ि ा ा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मकान क्लास फोर एम्पलाईज के लिए बनाए जा सकें ?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, हमने 559 मकान इन स्कीमों के तहत पिछले सालों में, 1 करोड़ 4 लाख रूप्ये की लागत से बनाए हैं। अब जो हम मकान बना रहे हैं उनके लिए हमने 2 करोड़ रूपये की रा ि ा निर्धारित की हुई है। हम आलरेडी इस बात की को ि ा ा कर रहे है कि ज्यादा से ज्यादा मकान बनाकर एम्पलाईज को दिये जायें

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि आजकल कुछ मकान एम्पलाईज के लिए बना रहे है। मै

उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जीन्द और नरवाना सब–डिवीजन के अन्दर भी कोई मकान बना हो या नही?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, जो हम आजकल मकान बना रहे है, उनमें से हम जीन्द में नही बना रहे है क्योंकि वहां पर हम पहले ही काफी बना चुके है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, उससे यह साफ जाहिर है कि क्लास थ्री या फोर एम्पलाईज के लिए अफसरों की बनिस्बत बहुत कम मकान बनाए गए है.....

श्री अध्यक्षः यह तो 1966 से अब तक की इन्फर्मे ान है।

श्री मूल चन्द जैनः मै अकेली इनकी सरकार को ही दोश नही देता, यह तो तमाम सरकारों के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। क्या मंत्री महोदय इस बात का यकीन दिलायेगे कि भविश्य में क्लास फोर और थ्री के लिये ज्यादा मकान बनाये जायेगे?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, मै तो पी०डब्ल्यू०डी० का इन्चार्ज हूं। मेरे पास तो नक ाा बन कर आ जाता है कि इस तरह का मकान बनाना है और मै बनाव देता हूं।

श्री मूल चन्द जैनः अगर आप बनाओगे नही तो उनकों मिलेगा कैसे? इसलिए मै यह पूछना चाहता हूं। कि यह जो गैप है, इसकों पूरा करने की कोि ा ा करेगे?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): हम इस गैप को पूरा करने की कोि ा ा करेगे।

श्री मूल चन्द जैनः इसका मतलब यह है कि आप उनके लिये ज्यादा मकान बनवायेगे।

चौधरी भजन लालः जरूर बनवायेगे।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि कोई कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी हुई है जो मकानों की अलाटमैंट करती है। कुछेक अफसरों के लिये तो वही मकान तय होते है यानी जब कोई अफसर ट्रान्सफर होकर जाता है तो उसकी जगह जो नया अफसर वहां पर आता है, उसकों वही मकान अलाट कर दिया जाता है। क्या बाकी के क्लास एक और क्लास दो अफसरों के लिए इस प्रकार का कोई सिद्धांत या पालिसी तय की हुई है? जो कर्मचारी जिले में सबसे ज्यादा लम्बे अर्से से वहां पर बैठे हुए है, उनकों किस आधार पर मकान अलाट किये जायेगे? मेरा कहना यह है कि जुडि ायरों के अफसरों को वहां पर रहते रहते अर्सा बीत जाता है, लेकिन उनकों कोई मकान अलाट नही किया जाता?.....(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः अलाटमैंट का काम तो पी०डब्ल्यू०डी० नही करता पी०डब्ल्यू०डी० तो केवल कंस्ट्रक ान का काम करता है।

कंवर राम पाल सिंहः जो डिस्ट्रिक्ट लैवल प अलाटमैंट कमेटी बनी हुई है वही अलाटमैंट करती है। (व्यवधान व भाोर)

Sh. Surrender Singh: There is no such Committee. (Interruptions).

श्री लहरी सिंह मेहराः अभी मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अफसरों के लिए 175, क्लास थ्री के लिए 249 और क्लास फोर के लिए 135 मकान बनाए गए है। मै इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मकान हर डिस्ट्रिक्ट और सब–डिवीजनल हैडक्वार्टर पर बने हुए है, अगर हां तो यह किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर बनाए गए है?

कंवर राम पाल सिंहः क्राइटेरिया तो यही है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सार डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रे ान होती है, वहां पर जो एम्पलाईज काम करते है, उनकों फैसिलिटी देने के लिए यह बनाए जाते है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मै आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई केस उनके नोटिस में है जिसमें किसी अफसर को मकान अलाट हुआ हो, वह उसमं जाने की बजाये अपने ही मकान में बैठा हो और जो मकान

उसकों अलाट किया गया, वह उसने आगे किराए पर दे दिया हो? (व्यवधान व भाोर)

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया।)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Matching Grants

***1642 Sh. Gulzar Singh, Ch. Ude Singh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) Whether any scheme of giving matching grants for development works in the villages has been formulated in the state; if so, the details thereof;

(b) If reply to part (a) be in the affirmative the district-wise names of villages which deposited their part of contribution under te scheme referred to in part (a) above togetherwit the amount depoited by each of them since the inception of this scheme to-date; and

(c) Whether all the villages referred to in part (b) above were given matching grants; if not, the district-wise names thereof togetherwith the reasons therefor?

Interim Reply

"**RAM NARAIN** Development & Panchayat,

Minister,

Haryana

Subject: Starred Assembly Question No. 1642.

My dear Col. Ram Singh,

The Starred Assembly question No. 1642, asked by Sh. Gulzar Singh M.L.A., and Sh. Ude Singh, M.L.A. has been fixed for answer on 14the March, 1980. Notice for this question was received on 7th March, 1980. The reply to Assembly Question is not ready as the required information is awaited from the Deputy Commissioners.

I Shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question under rule 46(ii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. This question may be included in the list of question may be included in the list of questions for any date after 15 days.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Ram Narain)

Col. Ram Singh,

Speakder,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Matching Grants for Village Dhanur

***1525 Sh. Bhangi Ram:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state wheter the matching grant sanctioned by the Government to village Dhanur of District Sirsa when Ch. Devi Lal was the Chief Minister has been released to the said village; if not, the reasons therefor?

विकास मंत्री (राव राम नारायण): पंचायत धनूर ने स्कूल भवन निर्माण हेतु 40,501 रूपये की अं ादान की रा ि ा वापिस ले ली है। अतः गांव धनूर को मैचिग ग्रांट देने का प्र उत्पन्न नही होता।

Subsidy on "Pucca" Water courses

***1502 Sh. Kanwal Singh:** Will the Minister for Irrigation & Poweer be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give 50% subside for the construction of 'Pucca' water courses in the state; if so, the time by which it is likely to be implemented?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): खाले पक्की किये जाने के फलस्वरूप लाभ उठाने वालों को इस पर किये खर्चे की 50 प्रति ात अनुपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार के विचारधीन है। इस मामले को वि व बैंक और ए०आर०डी०सी० से पूछ–ताछ करके निपटाया जा रहा है।

इस मामले का निपटान हो जाने तक लाभ उठाने वालों से खाले पक्का किये जाने पर आए 50 प्रति ात खर्चे की वसूली रोक दी गई है। इसी प्रकार लाभ उठाने वालों में जिनकी जमीन 2.5 एकड़ तक है, कोई वसूली नही की जा रही है।

Misqppropriation in the Haryana Roadways Depot Hissar

***1520 Ch. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) Whether there has been any case of misappropriation of funds in the store of Haryana Roadways Depot at Hissar during the year 1977, if so, the amount involved therein; and

(b) If the reply to part (a) be in the affirmative, the action taken against the persons held responsible therefor?

परिवहन मंत्री (श्री जगन्नाथ)

(ए) जी नही।

(बी) भाग 'ए' से पूर्ण हो जाता है।

Construction of link roads in Yamunagar Constituency

***1576 Shmati Dr. Kamla Verma:** Will the minister for public work (B&R) be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the government to consttuction link roads of

the villages Tapukarmalpur and Gadhauli Majri in the Yamunagar constituency; and

(b) If so, the time by which the link roads referred to in part (a) above are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) हां, टापुकमालपुर पहले ही कुरूक्षेत्र सहारनपुर सड़क से पक्की सड़क से मिला हुआ है। लिंक गांव के उत्तर प्रदे ा सीमा तक विचारीन है। गांव गधौली एक नान डयरैक्टरी गांव है। फिर भी गांव तक एक लिंक रोड़ सरकार के विचारधीन है।

(ख) यदि सरकार इन सड़कों में से किसी भी सड़क के निर्माण का फैसला करती है तो धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सड़क के पूर्ण करने में एक साल का समय लगेगा।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Operation Division at Tohana

***1498 Ch. Karam Singh:** Will the Minister for Irrigation and power to pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to create a full fledged

operation Division of Haryana State Electricit Board at Tohana; and

(b) If so, the time by which the proposal as referred to in part (a) above is likely to materialise?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधी मेहर सिंह राठी):

(क) तथा (ख) भिन्न भिन्न किस्म के कनैक ानों वे सेवाओ की बढ़ौत्तरी के आधार पर अधिक भार वाले मण्डल या उप–मण्डलों जिसमें टोहाना भी है। उसके विभाजन का प्र न हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के विचारधीन है। इस प्रस्ताव के बारें में जल्दी ही निर्णय के लिया जायेगा।

Fund allocated to Haryana State Central Social Welfare Advisory board

***1531. Sh. Preet Singh:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) The total amout of grants given by the Haryana Stte Central Social welfare Advisory Board Sector-17, Chandigarh during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80, separately, to the various welfare organisation of Haryana State;

(b) The total amount of buget allocted to the Haryana State Central Social Welfare Advisory Board referred to in part (a) by the Cental Soociat welfare Board, Parliament Street, New Delhi during the period mentioned in part (a) above;

(c) Whether the budget allocated during the years mentioned in part (a) above to Haryana Stter Central Social Welfare Advisory Board has been fully utilized; if not, the amount lapsed during the same period togeterhwitht he reasons therefor and the officer; if any, held responsible for the same; and

(d) The year wise total amount, if any, allocated by the Haryana Government to the Haryana State Central Social Welfare Advisory Board, Chandigarh, during the years mentioned in part (a) above separately?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

Years	**Amounts of grants released**
(a) 1977-78	5,69,612.84
1978-79	3,01,696.25
1979-80	3,97,785.00
(b) 1977-78	4,58,812.00*Includes allocation for the grant
1978-79	4,55,925.00*to be released by the state board
1979-80	3,70,225.00in the susequent years for continued programmes
(c) Full	

Utilized	
(d) 1977-78	4,00,000.00
1978-79	9,59,200.00
1979-80	6,00,000.00 (up to 31-1-80)

Cut made in the Haburi Sub-Brnach of Jakhauli Cannal System

***1596 Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for irrigation and power be pleased to state—

(a) The total number of cuts; if any, made in the Haburi Sub-Branch of Jakhauli Canal system during the year 1979-80 (upto 31-1-80); and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to stop making cuts in the Haburi Sub-Branch of Jakhauli Canal System as mentioned in part (a) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) वर्श 1979–80 के दौरान (31–1–80) हाबडी उप भााखा पर कुल 2 (दो) कर्तन तथा जाखौली डिस्ट्रीब्यूटरी पर कुल 6 (छः) कर्तन हुए।

(ख) जी हां– निकट भविश्य में हाबड़ी उप भााखा तथा जाखौली डिस्ट्रीब्यूटरी समेत राज्य में सभी नहरों को पक्की करना

सरकार के विचाराधीन है और ऐसा करने से नहरों को किसानों द्वारा बार–बार काटने से रोका जा सकेगा। फिर भी नहरों पर 'कट' (कर्तन) बन्द करने के लिए विभागीय ग त को तेज करने, पुलिस व विभागीय अधिकारियों द्वारा मिलकर अचानक निरीक्षण व छापे मारने, पुलिस व सिविल अधिकारियों की सहायता से रात में ग त लगाने व तावान की अधिकतम सीमा को पानी के साधारण दर के 6 (छः) गुणा से बढ़ा कर 20 गुणा कर देने जैसे सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ताकि भारारती लोगों को नहरें काटने से रोका जा सके।

अतारांकित प्र न एवं उतर

Haryana Roadways Depots in the Stat

343. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the districtwise name of Haryana Roadways Depots together with their strength of buses and number of work shops in each depot in the State, separately; and

(b) the year wise and depot wise profit earned/loss suffered during the period from 1968-69 to 1979-80 (to-date) separately?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a)&(b) Statements I and II containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT I

(a) The District wise names of Haryana Roadway Depots together with their prsent strength of buses and number of workshops in each depot in the State separately.

Sr. No.	Name of Depot	Distt. in which Depot is located	Present strength of buses (as on 31-1-80)	No. of workshops in each depot (including sub-depot)
Haryana Roadways				
1	Ambala	Ambala	171	1
2	Chandigarh	U.T. Chandigarh	205	2
3	Karnal	Karnal	202	2
4	Jind	Jind	159	2
5	Kaithal	Kurukshetra	197	3
6	Sonepat	Sonepat	83	2
7	Yamuna Nagar	Ambala	125	2

8	Gurgaon	Gurgaon	273	4
9	Rohtak	Rohtak	183	2
10	Hissar	Hissar	214	3
11	Rewari	Mohindergarh	169	2
12	Bhiwani	Bhiwani	167	3
13	Sirsa	Sirsa	112	2
		TOTAL	**2260**	**30**

STATEMENT II

(b) Statement showing year-wise and depot-wise profit earned/loss suffered during the period from 1968-69 to 1979-80 (to-date).

	Ambala	Gurgaon	Chand.	Rohtak	Karnal	Hisar	Rewari	Jind	Bhiwani	Kaithal	Sirsa	Sonepta	Yamuna Nagar	T
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
	32.37	25.32	12.84	27.31										1
	30.46	14.05	13.22	17.47	11.32	4.85								9
	22.74	29.53	4.95	25.95	52.53	31.13								1
	35.66	33.22	14.60	56.31	61.00	38.88								2
	16.28	23.26	17.11	58.89	63.09	35.35	-3.82	-2.51						2

	-4.23	-1.39	4.48	4.32	32.63	8.43	0.07	-5.35	-5.42					3
	-15.02	-27.21	8.01	-12.83	24.12	-2.86	-5.11	-4.73	-10.13	-10.67				-
	-0.61	-18.72	10.29	-23.46	20.49	-9.24	-5.92	-3.35	-7.24	-11.94				-
	8.21	9.44	3.89	-10.99	33.09	18.58	-6.29	-9.26	-2.10	3.61				4
	11.39	9.55	13.75	-9.69	31.10	16.81	-17.59	-6.27	-13.31	8.79				4
	13.83	18.73	18.73	6.00	17.02	24.06	3.83	-29.82	-9.40	-15.00	4.58			5
l, n.	13.07	35.32	24.85	24.70	22.49	32.06	18.09	-11.55	0.40	2.50	4.84	0.40	-4.10	1

Approximate production of Electricity from Thermal Plants

344. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideratino of the Government to increase the production capacity of the Thermal Plants at Panipat and Faridabad during the years 1980-81 and 1981-82; if so, the estimated number of units of electricity likely to be produced during the same period; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up more Thermal Plants during the period referred to in part (a); if so, the number thereof together with their present number in the State?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) 1980–81 व 1981–82 में पानीपत ताप बिजली घर की इनस्टालड कैपेसटी बढ़ाई नहीं जायेगी।

फरीदाबाद ताप बिजली घर परियोजना में तीसरा 60 मैगावाट यूनिट लगाया जा रहा है और अगस्त, 1980 में चालू कर दिया जायेगा। यह यूनिट 1980–81 (7 माह) में लगभग 300 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा और 1981–82 में 3000 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। कथन संगत है कि ताप बिजली घर को चालू करने के उपरान्त भ्रारू के कुछ महीनों में बिजली का

उत्पादन तुलनात्मक तौर पर कम होता है क्योंकि प्लांट स्थिर नहीं होता और इसको प्रायः 5 या 6 महीने लग जाते हैं।

(ख) पानीपत ताप बिजली घर परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण का कार्य जो कि प्रत्येक 110 मैगावाट के 2 यूनिट, 1980–81 और 1981–82 में चालू रहेगा। एक अन्य 800 मैगावाट (4x220 मैगावाट) क्षमता का ताप बिजली घर यमुनानगर में लगाने का प्रस्ताव है, जिसका कार्य इसी समय के दौरान हाथ में ले लिया जायेगा।

इस समय राज्य में केवल 2 ताप बिजली घर है। एक फरीदाबाद में 15 मैगावाट का यूनिट और दो 60 मैगावाट के यूनिट और दूसरा पानीपत में 110 मैगावाट के दो यूनिट हैं।

Political Sufferers in the State

345. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state the district wise total number of political sufferers in the State who are getting aid in any shape from the State Government together with the details of the said aid, separately?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) At present State Government is giving Financial Assistance to 1187 Freedom Fighters out of which 226 are Satyagrahi Freedom Fighters and 961 Ex-I.N.A. personnel. The district-wise detail is given in Annexure-I.

(b) The minimum and the maximum rates of State Financial Assistance to Freedom Fighters is Rs. 25/- p.m. and 200/- p.m. respectively. The district-wise details are in Annexure II & III.

ANNEXURE-I

District-wise detail of Freedom Fighters and Ex-I.N.A. Personnel

District	Freedom Fighters General	Ex-I.N.A. Personnel
Ambala	34	24
Bhiwani	2	143
Gurgaon/Faridabad	6	130
Hissar	13	164
Jind	10	42
Karnal	43	14
Kurukshetra	15	20
Mohindergarh	8	125
Rohtak	58	249
Sonepat	30	31

Sirsa	7	19
Total	**226**	**961**
Grand Total 226+961 = 1187		

ANNEXURE-II

District-wise detail of Financial Assistance to Freedom Fighters.

Name of District	Rates of Financial Assistance per month							Total
	Rs. 25/- P.M.	Rs. 30/- P.M.	Rs. 50/- P.M.	Rs. 75/- P.M.	Rs. 100/- P.M.	Rs. 150/- P.M.	Rs. 200/- P.M.	
Ambala	19	7	4	2	2			34
Bhiwani	1	1						2
Gurgaon/Faridabad	4		1				1	6
Hissar	9	4						13
Jind	5		5					10
Karnal	22	13	3	1	3	1		43
Kurukshetra	10	5						15
Mohindergarh	5		1		1		1	8

Rohtak	48	5	4		1			58
Sonepat	25	2	2			1		30
Sirsa	7							7
Total	**155**	**37**	**20**	**3**	**7**	**2**	**2**	**226**

ANNEXURE-III

District-wise detail of Financial Assistance to Ex-I.N.A. Personnel

Name of District	Rates of Financial Assistance per month							Total
	Rs. 25/- P.M.	Rs. 30/- P.M.	Rs. 50/- P.M.	Rs. 75/- P.M.	Rs. 100/- P.M.	Rs. 150/- P.M.	Rs. 200/- P.M.	
Ambala	23	1						24
Bhiwani	129	13	1					143
Gurgaon/Faridabad	119	11						130
Hissar	148	11	5					164
Jind	36	5	1					42
Karnal	10	3	1					14
Kurukshetra	19	1						20

Mohindergarh	118	5	2					125
Rohtak	229	17	3					249
Sonepat	30	1						31
Sirsa	17	2						19
Total	**878**	**70**	**13**					**961**

Old Age Pensioners in the State

346. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the district wise total number of old age pensioners in the State togetherwith the amount of pension given per pensioner, separately; and

(b) the criteria and procedure adopted for the grant of pension to pensioners as referred to in part(a) above?

Transport Minister (Sh. Jaga Nath):

(a) The District wise total no. of Old Age Pensioners as on 31-1-80 in the State is as under:

`

Sr.No.	Name of District	Number of Pensioners
1	Ambala	2108

2	Karnal	1209
3	Kurukshetra	403
4	Gurgaon	1232
5	Faridabad	1030
6	Rohtak	1623
7	Hissar	933
8	Sirsa	320
9	Bhiwani	379
10	Sonepat	699
11	Mohindergarh	747
12	Jind	360
	Total	**10146**

A sum of Rs. 50/- is the amount of pension given per pensioner per month.

(b) the criteria and procedure adopted is as underL

(i) persons who are of the age of 65 or above in the case of men and 60 or above in the case of women and have no menas of subsistence and none in a position to support them, provided that in either case they are domiciled and have resided in the Haryana State for more than 3 years at the time of making an application and provided further that a person

shall be termed as destitute if all the relatives, i.e. son, son's son, husband/wife are not in a position to support them;

(ii) where both wife and husband are destitute according to the definition, each one of them shall be eligible for assistance;

(iii) Professional beggars and medicants shall not be considered to be destitute but persons who are not acutally beggars but get occasional assistance from some other people may be allowed pension, if they, otherwise, are eligible and the sanctioning authority is satisfied that they are really destitute.

Note: Persons who have adult son/son's son(s) shall be termed as destitute fro this purpose if the monthly income of such earning hands falls within the following limits:-

(a) an unmarried person having a monthly income not exceeding Rs. 50;

(b) a married person with no child having a monthl income not exceeding Rs. 90;

(c) a further allowances of Rs. 25/- per mensem per child being allowed subject ot a maximum income of Rs. 150/- per mensem per family;

(d) the case of the persons who have monthly income exceeding Rs. 150/- per mensem but who have to shoulder responsibilities of higher education of their own dependents shall be decided on merit of each case with Minister-in-charge.

Note-(ii) a widow shall be deemed a destitute even if she has an earning brother;

(iii) step son(s) shall not be considered a son for the purpose of grant of this pension;

(iv) applicants having an income not exceeding Rs. 15/- per mensem from any source including income from the property owned by them shall also be termed as destitute for the purpose of grant of this pension.

4. Applications for Old Age Pension shall be submitted by intending applicants to the Deputy Commissioner, or the Sub-Divisional Officer (Civil) or the Tehsildar, or the Block Development and Panchayat Office or the District Welfare Officer of the area in which the applicant resides. The requisite application forms shall be obtainable free of charge from any of the afore-mentioned authorities or the office of the Director Social Welfare in the Old Age Pension Branch.

5. (i) It shall be the duty of the authorities mentioned in para 4 above to carry out detailed enquiries into the financial position of the applicant and into other particulars given in the application form, as defined in para 2 above and the age of the applicant shall be checked with great care. In cases where the age of any applicant is near the border line, it shall be the responsibility of the recommending authority to obtain a report from a medical officer not below the rank of an Assistant Surgeon so as to ensure that no one below the prescribed age is recommended for this benefit. In cases where a particular applicant owns peoperty, i.e. house

or land, area of the land owned and size of the house and probable income derived therefrom shall also be checked more closely and indicated while forwarding the applications to the sanctioning authority for final orders.

(ii) In the cases of disabled persons, relaxation in age my be permitted to the extent of 10 years than the prescribed age limit. But it shall be obligatory of obtain considered medical opinion from an officer not below the rank of Assistant Surgeon who shall clearly indicate the nature of disability and whether the same is of permanned nature or temporary. Relaxation in age shall be admissible in the case of permanent disability only.

रूल्ज कमेटी की रिपोर्ट पे ा करना

10.00 बजे

Mr. Speaker: Hon. members, now I lay on the Table of the House the Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, as required under Rule 234 ibid.

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब मुझे बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि एन्टायर अपोजी ान ने आपके खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव दे रखा है। मेरी आपसे प्रार्थना हे कि पहले उसके बारे में तय कर लिया जाए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, अभी वह प्रस्ताव मेरे सामने नही आया है। जब मेरे सामने वह प्रस्ताव आयेगा तो में तय कर लिया जाए। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, वह आपके सैक्रटरी साहब को दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में जो रूल 11 में लिखा है, वह मै आपको पढ़कर सुना देता हूं–

"11. (1) As soon as may be after the receipt of notice of a resultion to remove the speaker or the Deputy Speaker from his office under Article 179(c) of the Constitution, the speaker shall read the notice to the Assembly and shall then request members who are in favour of leave being granted to omove the resolution to rise in their places and if not less than 223 members rise accordingly, the Speaker shall allow the resolution to be moved....."

Mr. Speaker: I have already said that it has not come up before me. As soon as it comes before me, I will examine it.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आपके सामन ही है जी.....(ाोर)

Mr. Speaker: Should I control the question hour first or take the decision on the subject? Moreover, there is no out-break of war. As soon as, it comes up before me, I will take a decision on it.

डा० मंगल सैनः ठीक है जी। (ाोर एवं व्यवधान)

नेमिग आफ मैम्बर

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मै आपकी इजाजत से एक बड़ी दर्दनाम घटना यहां पर बताना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी, आप इसके लिये पहले नोटिस दीजिये।

चौधरी गंगा रामः * * * *

*

Mr. Speaker: Without notice, I will not entertain it. Nothing will be recorded. (Interruptions)

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, I have given a Call Attention notice today (Interruptions)

Mr. Speaker: It has not come to me. (Interruptions) At what time did you give the Call Attention notice?

Dr. Mangal Sein: About 8-30 A.M., Sir. (Interruption)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, इसलिए मै यहां हाउस में बताना चाहता हूं.....(ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप किस विशय पर बोल रहे है?

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मै बताना चाहात हूं कि सारे हरियाणा में ही इस प्रकारका अत्याचार हो रहे है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप पहले इसके लिये नोटिस दीजिए, फिर बोलिये।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, यह बड़ा इम्पाटैंट मैटर है कि

* * * * *

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये। (व्यवधान)

सरदार लछमन सिंहः स्पीकर साहब, अब यहां पर जो रूल्ज कमेटी की रिपोर्ट सर्कुलेट हुई हे, उसमें राव बीरेन्द्र सिंह का नाम दिया हुआ है। इस हाउस के तो राव बीरेन्द्र सिंह मैम्बर ही नही है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः सरदार साहब, अगर आप नोट पढ़ने का कश्ट करेगे तो आपकों पता चल जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात को लेकर जो यहां पर हंगामा किया कि पुलिस के सिपाही ने रोहतक में एक विधवा हरिजन महिला से बलात्कार किया। कोई भी आदमी अगर रूल्ज की उल्लंघना करता है और फिर सरकार अगर उसे खिलाफ कोई कार्यवाही नही करती तो सरकार की आलाचना की जा सकती है। उस सिपाही के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पुलिस अधिकारी उसकी इंकवायरी भी कर रहे है। मैं सदन को वि वास दिलाता हूं कि दोशी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गल्त कह रहे है, मै आपकों बताना चाहता हूं कि

आवाजेः स्पीकर साहब, यह हाउस का टाइम जाया कर रहे है, इनकां हाउस से बाहर निकाला जाए। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, सारे हरियाणा के साथ ही अत्याचार हो रहा है।

श्री अध्यक्षः चौधरी संत कंवर आप बैठिये।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, यह सीरियस बात है। आप हमारी बात तो सुनें.....

Mr. Speaker: I name Sh. Ganga Ram. (Interruptions) He may please withdraw from the House.

(At this state Ch. Ganga Ram, a member form the opposition withdraw from the House.

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, I had submitted a Call Attention notice today.....(Interruption).

Mr. Speaker: It is under examination (Interruption). Do you expect me to conduct the Question Hour and also to take a decision on a matter which is submitted at 8-30 A.M. today simultaneously?

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, जब आप हाउस में बैठे है * * *

* * *

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये। (व्यवधान)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

(1) श्री हीरा नन्द आर्य द्वारा–

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, आपने मुझे पर्सनल एक्सप्लेने ान देने के लिये टाइम देने का आ वासन दिया था, इसलिये मुझे इजाजत दी जाए ताकि मै अपनी स्थिति क्लीयर कर सकूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, अभी एक सवाल के जवाब में यहां पर चर्चा आया कि मैने अपन हलके मं सबसे अधिक स्कूल्ज अपग्रेड किये है। मै इसके बारें में यहा कहना चाहता हूं कि पालिसी के मुताबिक हर हलका में दो–दो, तीन तीन स्कूल्ज आप–ग्रेड किये जाने थे। सरकार ने इम्बैलेन्स को दूर करने के लिये, एवरेज के हिसाब से स्कूलों को अप–ग्रेड किया था। किसी एक हल्के की बात नही थी कि अपने हल्के में ज्यादा कर दिये और दूसरे के हल्के में कम कर दिये। इस बात का हाउस के अन्दर आ वासन भी दिया गया था कि जहां जहां जैसे–जैसे जरूरत समझी जाएगी वहां पर उस जरूरत के हिसाब से स्कूल्ज को अप–ग्रेड किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः आपका मतलब यह है कि इम्बैलेन्स को दूर करने के लिये आपने अपने हल्के में ज्यादा स्कूल अप–ग्रेड किये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, आप देखेगे कि जहां पर भी जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक ही स्कूलों को अप–ग्रेड किया गया। उदाहरण के तौर पर आप रोहतक को ही ल लीजिये, वहां पर सात आठ कालेज भी है और 8–10 स्कूल्ज भी है। तो आप ही बताएं कि ऐसी जगह पर स्कूल्ज अप–ग्रेड कैसे किये जा सकते है जहां पर कि आगे ही ऐजुके ान का इतना बड़ा सैन्टर हो? हमने इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, एवरेज को देखते हुए जहां–जहां पर जरूरत थी वहां पर स्कूल्ज अप–ग्रेड

करने के लिए प्रिआरिटी दी थी। भिवानी, तो ाम व लोहारू में स्कूल्ज अप–ग्रेड किये गये। लोहारू की तो यह हालत थी कि वहां कालेज तो क्या स्कूल्ज नही नही ि। इस तरह से ऐसी जगहों पर अगर स्कूल्ज अप–ग्रेड कर दिये गये है तो कोई बुरी बात नही की गई थी। हमने तो तो ााम में स्कूल्ज अप–ग्रेड किये थे पर इन्होने डी–ग्रेड कर दिये, इसमें हमारा क्या दोश?

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, तो ााम में कितने स्कूल्ज अप–ग्रेड किये थे?

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, वहां पर 8–9 स्कूल्ज अप–ग्रेड किये गये थे।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, बिल्कुल गल्त कर रहे है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मै यहां सारे सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं और ये यही बात को सुनना नही चाहते। तो ााम के अन्दर कई स्कूल्ज अप–ग्रेड किये गये है और यह कह रहे है कि बिल्कुल गल्त है। मै आपकों उन जगहों का नाम भी बता सकता जहां पर स्कूल्ज अप–ग्रेड किये गये है। मेरे पास लिस्ट है। मै बता देता हूं। कैरू, रिवासा, मेरानडानी और अलखपुरा वगैरह में स्कूल्ज को अप–ग्रेड किया गया और ये कहते है कि कही भी नही किये गये।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयअ आफ आर्डर है। अभी जीरों आवर में स्कूलों के बारें में कहां गया। मै सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि सारे स्कूल अप–ग्रेड कर दिये जाएं चाहे वे लोहारू में हो या तो ाम मे हो।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, इन्होने कुल 29 स्कूल डाउन ग्रेड किये। क्या वे सभी हल्के में ही अप–ग्रेड हुए थे। चीफ मिनिस्टर साहब जब अपने हल्के में गये तो इन्होने वहां पर कालेज, हस्पताल और वाटर सप्लाई की स्कीमें मंजूर की तथा और भी सब कुछ कर दिया। यह इन्होने इसीलिये किया होगा कि वहां इन चीजों की जरूरत होगी। इसी प्रकार से मैने भी जो स्कूल अप–ग्रेड किये थे, वे जरूरत के मुताबिक ही किये थे। मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन स्कूलों को दोबारा अप–ग्रेड किया जाए ताकि इन्साफ किया जाए।

(2) मुख्य संसदीय सचिव द्वारा

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भाान्ति देवी): अध्यक्ष महोदय, मै भी पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहती हूं। एक बड़ी दर्द भरी कहानी है.....

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मै आपकी रूलिंग चाहता हूं कि अगर कोई मैबर अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान दे रहा हो तो क्या कोई ऐसा रूल है कि कोई मिनिस्टर उसके बीच में बोले?

श्री अध्यक्षः आर्य जी अपनी बात कह चुके है, अब ये भी अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान दे रही है।

श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय, मै आपकों थोड़ा सा पीछे ले चलती हूं। मै चौधरी देवी लाल जी की सरकार के टाइम की बात करती हूं। उस वक्त आप के पास ि ाक्षा विभाग था। आपने हाउस के अन्दर बताया था हर एक विधायक का एक–एक स्कूल अपग्रेड किया जाएगा और आपने ऐसा किया भी। लेकिन जब आर्य जी के पास यह विभाग आया तो उस समय यह फैसला हुआ था कि हर विधायक के हल्के के दो–दो स्कूल अपग्रेड किये जाएंगे यह रिकार्ड की बात है.....(ाोर)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। जो स्कूल डाउन ग्रेड किये गये है उनकी जस्टीफिके ान तो ये दे सकती है लेकिन इन्होने तो सारी कहानी भाुरू कर दी।

श्री अध्यक्षः राठी जी आप रैलेवेंट प्वांयट पर ही बोले।

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, ऐसा निर्णय हुआ था कि सभी हल्कों में 90 स्कूल प्राइमरी से मिडल और 90 मिडल से हाई बनाये जाएंगे। यह बात पिछली कार्यवाही में मौजूद हैं आप निकलवा कर देख सकते हैं उस टाइम हम आवस्त रहे कि कर्नल साहब की तरह से हमें न्याय मिलेगा और सभी हल्कों के दो–दो स्कूल अपग्रेड कर दिये जाएंगे। लेकिन आर्य साहब ने 16

स्कूल अपने हल्के के अन्दर अपग्रेड कर दिये, 12 रण सिंह मान के, 16 चौधरी देवी लाल के और 8 श्री जगदी ा कुमार बैनीवाल के हल्के के कर दिये। हमारे हल्के में दो–दो स्कूल भी नही यिे। इस तरह से हमारे साथ अन्याया किया गया। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, उस वक्त ये भारत द र्ान पर गई थी। (ाोर)

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब वर्श 1980–81 के बजट पर फिर से जनरल डिस्क ान भ्ारू होगी। उस दिन श्री बीरेन्द्र सिंह अपने पैरों थे वे कृपया दो–तीन मिनट में अपनी स्पीच वाइंड–अप करे।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मै आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे साथी श्री गंगा जी ने जीरों आवर में हगामा किया कि रोहतक के अन्दर सात तारीख को..... .....(ाोर)

Mr. Speaker: Nothing more on this subject. This subject is closed. Please sit down.

श्री टेक रामः स्पीकर साहब, सुन्दर ब्रांच के बारें में मैने एक काल अटैन्ा ान मो ान का नोटिस दिया था मै उसके बारें में जानना चाहता हूं कि उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः यह डिस–अलाउ हो गया है भ्ाायद आपके पास सूचना पहुंच गई होगी।

वर्श 1980–81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः अब वर्श 1980–81 के बजट पर जनरल डिस्क ान फिर से भाुरू होगी। Ch. Birinder Singh was on his legs when the 'House adjourned last. He may please resume his speech and try to windi up in 2/3 minutes.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब सदन स्थगित हुआ तो मै कह रहा था कि पे–कमी ान की रिपोर्ट गवर्नमैंट के विचारधीनहै। पहले इतनी ज्यादा कैटेगरीज थी उनकों अब घआ कर 30 के करीब कर दिया गया है, यह बात बहुत अच्दी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा यह भी कहूंगा कि सैक्रेटेरियल स्टाफ के जो व्यक्ति उस रिपोर्ट को बनाने वाले सदस्यों की मदद कर रहे थे, अगर अच्दी तरह से देखा जाए तो उस स्टाफ को इस रिपोर्ट से बहुत फायदा हुआ है। लेकिन इस राज्यम ें जो इंजीनियरिग ट्रेडज है, टैक्नोक्रेट्स और दूसरी कुछ और कैअेग्रीजहै जिनके पे–स्केल पहले ज्यादो, इस रिपोर्ट के आने से अनके स्केल्ज कम हो रहे हैं इन बातों को ध्यान मे ंरखते हुए वित्त मंत्री महोदय सारे कर्मचारियों और अफसरों को न्याया दिलएंगे, ऐसी मुझे आ ाा है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को, जैसे मैने पहले भी कहा था कि काग्रेस की नीतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गयाहै। इसमें यह बात बहुत ही प्र ांसनीय है कि ि ाड्यूल्ड कास्टस के भाई जिनकों पहले वीजफे के तौर पर 8 रूपया या 30 रूपये मिलते थे, उसकों बढ़ा करसरकार ने 8 रूपये

की जगह 16 रूपये और 30 रूपये से बढ़ाकर 70 रूपये कर दिया है। इसके साथ–साथ मै यह भी कहूंगा कि हरियाणाका वह गीरब आदमी, जिसके पास रोजगार का साधन नही है, उसके लिये मै सरकार से यह सिफारि ा करूंगा कि इस समय जिन औरतों को 60 साल की उमर के बाद और मरदों को 65 साल की उमर के बाद ओल्ड एज पैं ान मिलती है। इन दोनों केंसों में 5–5 साल की अवधि घटा दी जाए। आप जानते है कि इन लोगों की सारी उमर गरीबी में कटती है। ये लोग डेली वेजिज पर लेबर का काम करते है और इनकी आमदनी बहुत थोड़ी होती है कठिन काम करने से मार्टेलिटी भी कम होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मै सरकार से सिफारि ा करूंगा कि इनकी एज लिमितट पांच–पांच साल घआ दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मै आपनी बात एक मिनट में कह कर अपना स्थान लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट पे ा किया गयाहै इसमे नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के बारें में विचार रखे गये है। ये कहते है कि आठ साल के समय में यह कम्पलीट हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सरकारसे सिफारि ा करता हूं कि नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट एक हाइडल प्रोजैक्ट है और इसमें हरियाणा का भविश्य निहित है। अगले 50 साल तक हरियाणा को बिजली का कोई संकट नही रहेगा अगर यह प्रोजैक्ट पूरा हो जाात है। अभी अखबारों में यह खबर थी कि हिमाचल सरकार इस फैसले को रिव्यू कर रही हैं जैसे एस०वाइ०एल० प्रोजैक्ट पर अढ़ाई साल तक जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नही किया, कही ऐसा ही न हो। एस०वाई०एल०

प्रोजैक्ट हरियाणा की लाइफ लाइन है जिसमें किसानों को जीवन निहित है लेकिन उसका फैसला नही हुआ। तो अगर हिमाचल सरकार कोई ऐसी बात कर रही है तो मै अपने मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे फौरन इस मामले को टेक–अप करे। इस प्रोजौक्ट पर जल्द से जल्द काम चालू किया जाए ताकि 8 साल के म्याद से पहले ही यह काम पूरा हो सके।

स्पीकर साहब, एक बात कह कर में अपना स्थान लेता हूं। स्पीकर साहब, मेरे कई विरोधी पक्ष के साथियों ने बजअ पर चर्चा करते हुए कहा कि इस सरकार नके कुछ स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया और साथ ही उन्होने यह भी कहा कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, मै तो इस सरकार से यह सिफारि ा करत हूं कि जो स्कूल हरियाणा के अन्दर एक खास जमात द्वारा चलाए जा रहे है और हरियाणाकी जनता के अन्दर साम्प्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा कदेते है, उन स्कूलों को एड देने की तो बात ही क्या, ऐसी स्कूलों को बिल्कुल बंद कर दिया जाये (घंटी) स्पीकर साहब, आखिर में एक बात ही कह कर मै अपना स्थान लेता हू। सदन में हर माननीय सदस्य ने कहा कि मिट्टी के तेल, चीनी और डीज की बहुत किल्लत है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारें में मैं यह कहना चाहता हूं कि 20 प्वायंट प्रोग्राम, जो इस दे ा को श्रीमती इन्दिा गांधी जी की कांग्रेस ने दिया था, उसमें यह लिखा हुआ है कि दे ा के अन्दर गरीब लोगों की जरूरियात की चीजे मुहैया की जाएं.....(ाोर)

श्री हरफूल सिंहः पहले आप 20 प्वायंट प्रोग्रम पढ़ करके तो सुना दे.....(ाोर एवं विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिहः अगर मै 20 प्वांयट प्रोग्राम पढ करके सुना दे तो क्या आप इस्तीफा देने के लिए तैयार है (ाोर) * * * * अगर आप इस्तीफा देने के लिए तैयाहै तो मै 20 प्वायंट प्रोग्राम पढ़ कर सुना देता हूं। (ाोर एवं विघ्न)

Sh. Verender Singh: This is an aspersion on the Member and it should be exqunged, Sir.

Mr. Speaker: If there is any such remark this will eb expunged. (Interruptions)

चौधरी बीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, मै यह आखिरी बात कह कर अपना स्थान लोता हूं। यहां हाउस में हर माननीय सदस्य कहता हे कि चीनी का भाव बढ़ रहा है और डीजल और मिट्टी के तेल को प्रदे ा में बहुत किल्लत है। इसके बारमें में मै यह कहूंगा जैसा कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम में पहले ही लिखा हुआ है कि इस दे ा के गरीब आदमी को जरूरियात की चीजे मुहैया होनी चाहिए। इसके लिए मै सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों कीा डिस्ट्रीव्यू ान सिस्टेमैटिकली की जाए और जो लोग मिट्टी के तल, चीनी, डीजल की ब्लैक करते है और होडिग करते है उनकों सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन भाब्दों के साथ माननीय फाईनैंस मिनिस्टर द्वारा पे ा किए गए बजट का समर्थन

करता हू। मै यह भी कहता हूं कि हामरे फाईनैस मिनिस्अर साहब सही कांग्रेस (आई) की नीतियों के प्रतीक है इन्होने बजट बनाते वक्त 20 प्वांयट प्रोग्राम को ध्यान में रखा। इन भाब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझें बोलने के लिए समय दिया।

श्री रण सिंह मान (बाढड़ा): स्पीकर साहब, इससे पहले कि मै बजट पर अपने विचार रखूं, आपसे एक निवदेन करना चाहता हूं। इस बजट मे ंएक मद है समाज कल्याण और इसी विशय पर मैने कल एक प्रस्ताव भी दियाथा जो किन्ही कारणों की वजह से यहां हाउस में डिस्कस नही हो सका। इसलिये मै आपकी इजाजत से थोड़ा बहुत इस बजट पर बोलते हुए समाज कल्याण के बारें में कुछ कहना चाहूंगा, यदि आप मुझ 5 मिनट फालतू बोलने की इजाजत दे।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप 5 मिनट फालतू बोल सकते है।

श्री रण सिंह भानः अध्यक्ष महोदय, आपने मझ जो 5 मिनट फालतू बोलने के लिए इजाजत दी, उसे लिए धन्यवाद। अध्यख महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट हाउस मे ंपे ा किया है। ये बहुत ही सयाने और अनुभवी व्यक्ति है, इनसे यह आ ाा की जाती थी कि ये एक ऐसा बजट पे ा करेगे, जो हरियाणा के समाज की आव यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उसके

समन्वित विकास का रास्ता भी बनायेगा लेकिन दुर्भाग्य है इस बजट में ऐसा कुछ नही है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो घाआ दिखाया गया है और अभी हाल ही में जो केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट में घाटा दिखाया है, इन दोनों घाटों के बजट का परिणाम आखिर में यह होना है कि ये बजट एक तरह से अघोशित टैक्सों के रूप में लागों के सामने आएंगे। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) जो इतने घाटे का बजट होता है वह बड़ा खतरनक होता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में यह इ ाारा भी किया है कि आव यकता पड़ने पर कर लगाए जा सकते हैं डिप्टी स्पीकर साहब, कितना अच्छा होता कि यह जो घाटा केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार के बजट में दिखाया गया है, इसको पूरार करने के लिए जो टैक्स लगाने थे, वे पहले ही लगा दिये जाते ताकि इस घाटे का असर कीमतों पर न पड़ता और जो कीमते बढ़नी थी वे एक बार ही बढ़ जाती। उसे बाद लोग नि चत हो कर साल भीर उसके अनुसार, अपने विकास कार्यो में सहयोग देते। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होने एक मद इस बजट में समाज कल्याण के बारे में दी हैं उस मद में बेसहरा लोगों के लिए 60 लाख रूपये की तजवीज दी है। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले कि मै बेसहारा लोगों के बारें में कुछ कहूं, मै एक अर्ज करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पैन ान देती है। पैन ान क्यो देती है? इसलिए क्योंकि इन लोगों ने हरियाणा के समाज के लिए और सरकार के लिए भाासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाथ बंटाया है औा इन

लोागों ने समाज के लिए उपयोगी कार्य किए है तााि जब ये अपनी सेवाएं पूरी करके वापिस घर लोटे तो कम से कम उनका भविश्य तो आरम से बीते। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा पैन ान के बारमें में एक औल्ड एज पैन ान स्कीम सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट चलाता है जोकि बूढे और बेसहारा लोगों को पैन ान देता है ताकि वे अपनी जिन्दगी आराम से बसर कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, आज की बदती हुए परिस्थितियों और मंहगई के कारण हामर प्रदेश मे ंऐस भी लोग है जिनकी हालत बहुत ही खस्ता, दयनीय और करूणादायक है। उन लोगों ने बे ाक इस दे ा की नौकरियों में या राजनीतिक सेवाओं में हिस्सा नही बंटाया पर जिन्होने अपनी जवीन खेतों ं और खलिहानों में दिन–रात मेहनत करके गुजारा दिया है, जिन लोगों ने सड़कों पर टोकरियों उठाई है, जंगलात में पेड–पौधे लगाये है, जिन लोगो ने हमरे लिए औजार बनाए है, जिन लोगों ने किसानों के लिए औजार है, मिट्टी के बर्तन बनाए है और वे लोग आज 60 साल से ऊपर की आयु के है, उनकों ओल्ड एज पैन ान जरूर देनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके पास अपनी जिन्दगी बसर करने क ंलिए साधन नही है है, उनकां अव य ही इस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। गांव में अकसर पढ़े लिखे लोग ऐसे बूढ़ो को कोसत रहते है कि ये मर क्यो नही जाते? डिप्टी स्पीकर साहब,ये ऐसे लोग है जिन्होने अपनी सारी जिन्दगी दे ा की भलाई के लिए कई तरह के काम किए हैं खेतों में खलिहानों में काम करते–करते उन लोागें ने अपनी जिन्दगी गुजार दी है और आज

जब वे बूढे हो गये है तो उनका कोई साहारा नही है। अगर यह सरकार संविधान के अनुसार वास्वत में कल्याणकारी सरकार है तो इसका पहला फर्ज यह बनता है कि बूढे किसानों, खेतीहर मजदूरों व कारीगरों के लिए पै ानका प्रबन्ध करे। बूढे लोगों की संख्या लगभग 5 लाख81 हजार के करीब है, इनके लिए कम सके कम 100 रूपये प्रति बूढ़ा पैन् ान दी जाए। वित्त मंत्री महोदय गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति है, अतः मै इनसे अपील करूंगा कि इस और वि ोश ध्यान दें। आज का समाज 50 साल पुराना समाज नही जिसमें आसानी से निर्वाह हो जाता था। आज एक लड़का मु ाकल से पढ़–लिख पाता है लेकिन इसके लिए रोजगार नही है क्योंकि रोजगार पर कुछ खास व्यक्तियों ने राजनैतिक प्रभाव डाल लिया है वैसे तो रोजगार आज सेचुरे ान प्वांयट पर पहुंच गया है। एक बेरोजगार नौजवान बूढ़ै मां–बाप की सेवा कैसे कर सकता हे? अगर छोटी मोटी नौकरी पर लग भी जाता है तो इस मंहगाई के जमाने में बूढ़े मा–बाप का भार ढोना उसके लिए मु ाकल है। इसलिए मै हाउस के सम मैम्बरान से अपील करूंगा कि इस मसले को हल करने की और वि ो ा ध्यान दे। डिप्टी स्पीकर साहब, खेद की बात है कि रूलिग पार्टी के साथियों ने हाउस में बहुत सी बातें कही लेकिन बूढ़ों को पैन् ान देने के मामले में एक बात नही कही। यह उन्होने दल बदल कर बहुत बड़ा पाप किया है। मै इनसे अपील करूंगा कि इस मामतले में बूढ़ो की मदद करें, उनके लिए यह मदद, यह पैन् ान,

गंगा, त्रिवेणी व सरस्वती बनकर सब पाप धो देगी। राज्य सरकार जो मदद देगी, उसी के ऊपर इनका भविश्य निर्भर करता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, आज एग्रीकल्चर प्राइस कमी ान की रिपोर्ट आई है अतः एग्रीकल्चर पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। इस बजट स्पीच के अन्दर खेती की मद के नीचे केवल 17.46 करोड़ रूपये का प्रावधान खेती के लिए किया गया है ताकि एग्रीकल्चर सैक्टर में उत्पान बढ़े। इरीगे ान पर्पजिज के लिए, बिजली बढ़ाने के लिए जो पैसा बजट में रखा गया है, इसकों मै एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए इन्कलूड नही करसकतौ। 1978 में इरीगे ान और इलैथ्कट्रसिटी के लिए 400 करोड़ था 1978 में राज्य की कुल कृशि आय 1027 करोडद्य रूप्ये थी। अतः आज के बजट में 17.46 करोड़ रूपया जो सरकार ने दख है यह बहुत कम हैं कई करोड़ रूपया खर्च करने के बाद जो पैदावार दे ा में हुई है, उसके बारमें में मै आपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि उस प्रोडक ान का मूल्य क्या है? डिप्टी स्पीकर साहब, एक जमाना थ जब खेती की पैदावार बढ़ाई नही जा सकती थी क्योंकि सब जगह नहरें नही थी, बिजली नकी फैसिलीटीज नही थी, सब जगह टयूबवैल्ज नही थे। आज कुएं खुद गए, टयूबवैल्ज लग गये नहरों के जरिये से पानी बढ़ गया, हर प्रकारी की इरीगे शन फैसिलटी मिल गई और पैदावार बढ़ गई लेकिन कारखानों में जो माल पैदा होता है। वे जिस रफ्तार से कारखानों के माल की कीमत बढ़ रही है, किसान

की पैदावार की कीमत में बढ़ौत्तरी उससे बहुत कम हैं कारखानेदारों ने कीमत बढ़ा कर अपने आपकों कम्पैसेट कर लिया लेकिन किसान वैसे के वैसे ही रहे। खास कर इतनी छोटी रकम से, जो सरकान ने 17.46 करोड़ का प्रावधान किया है, इससे खेती की पैदावार ज्यादा नही बढ़ सकती और लाभकारी मूल्य का सवाल तो और अगो है। जिस रफ्तार से कारखाने के माल की कीमत बढ़ रही है उस रफ्तार से खेती की पैदावार की कीमत नही बढ़ रही। वितत मंत्री महोदय ने माना है कि प्राईस इंडैक्स 17 परसैट बढ़ गया है लेकिन सरकार ने इसके मुकाबले में जमींदारके अनाज की कीमत सिर्फ 2 रूपये क्विटल बढ़ाई है। एग्रीकल्चर प्राइस कमी ान ने केवल दो रूपये की बढ़ौत्तरी की है, क्या यह यसरकार कह सकती है कि वह किसान के हित की बात है? सरकार के लिए यह लज्जाजनक बात है। एंगीकल्चर प्राइस कमी ान के सामने यह सारा मसमला रखना चाहिए, स्पश्ट बात करनी चाहिए कि कारखानों में पैदा होने वाले माल की कीमत और खेतों में पैदा होने वाले माल की कीमत में बड़ा भारी अन्तर है, इनकी रे ाों फिक्स होनी चाहिए। अगर रे ाों फिक्स नही हुई तो इसका नतीजा यह होंगा कि खेती बिल्कुल अलाभकारी हो जाएगी और इस पालिसी से दिन पर दिल अलाभकारी होती भी जा रही है नतीजे के तौर पर लोग खेती करना छोड़ जाएंगे और मजदूरी करने लगें। आज बेकारों की वि ोशकर खेतीहार मजदूरों के रूप में उनकी संख्या बढ़ रही है, एक एक समय आएगा जब विस्फोटक पोजी ान हो जाएगी। मै वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इस इम्बैल्स

को खत्म करने की कोि ा ा करें। बिजली तथ सिंचाई मंत्री जी ने जो ब्यान आज दियाहै, वास्तविकता में उसमें बड़ा अन्तर है। उन्होने हाउस में तजवीज रखी कि बीस हजार टयूबवैल्ज के कनैक ान दिए जाएंगे। इन्होने यह भी बताया कि लो–वोल्टे है, इसकेां मेन्टेन करने की कही है इसमें बड़ा अन्तर विरोध है। इन्होने बिजली के स्टे ान व सब स्टे ान बनाने के लिए पैसा भी बजट में नही रखा है, इस बात का जिक्र भी नही किया अै अगर ऐसा है तो नये कनैक ान कहां से देगे, बिजली कहां से ले जाएंगे। बिजली न मिलने के कारण आज लोगों की हालत बड़ी खराब हो चुकी है और दूसरी तरफ बीस हजार टयूबवैल्ज लगाने जा रहे है, इसका क्या मतलब है? हाउस में केवल आंकड़े दिखाकर काम चलने वाली नही हैं केवल आंकडऋे दिखाकर कहना कि सरकार बहुत कछ करने जा रही है। इससे मसला हल होने वाला नही है, कोई न कोई समन्वित विकास का रास्ता अपनाना चाहिए। मै वित्त मंत्री महोदय से हना चाहूंगा कि केवल भााबासी लेने के लिए यह कहना कि बीस हजार टयूबवैल्ज लगायेगे, ठीक नही है। आप समन्वित विकास के रास्ते पर चलें। डिप्टी स्पीकर साहब, श्रम विभाग भी इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर के पास है। वे बीसवी सदी के आठवे द ाक के मंत्री है। लेकिन वे 16वपी सदी के व्यक्ति की तरह बात करते है, लोगों में इस बात की बड़ी चर्चा है। इनकों मालू3महोना चाहिए कि राज्य में खेती का उत्पादन बहुत होता है, इसके बावजूद भी ये बड़े–बड़े कारखानेदारों को ही प्रोत्साहन देने की कोि ा ा करते है।

हरियाणा में 323 करखाने ऐसे है जो अपना माल हरियाण में तैयार करते है लेकिन ये बड़े कारखानेदार अपना माल दिल्ली में जाकर बेचते है। इन्होने अपने हैड आफिसिज दिल्ली में बना रखे है।, माल हरियाणा में तैयार होता है और माल हैड असिफसिज के जरिए दिल्ली में बेचा जाता है जिससे हरियाणा को करोड़ो रूपये का घाआ हो रहा है। इसके बावजूद भी यह सरकार इन्ही कारखानेदारों को राहत दैने की कोि ा ा करती हैं रहात सरकार ऐसे लोगों को देजो उसका ठीक तरह से उपयोग कर सकें। सरकार उचित लोगों की रहात देने में असफल रही है कयोंकि सकरान ने अपनी रवैया प्रो–कैपिटलिस्ट बना रखा है। इस मद में सरकार ने 41.84 लाख रूपया रखाहै जिसका उचित उपयोग नही हो सकेगा। इतनी रफ डीलिग से हम दूसरी स्टेटों से आग्र नही बढ़ सकते, आपको कुछ सुधार करना चाहिए, तभी दूसरी स्टेटों को मुकाबला कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, हांसी के स्पीनिग मिल में एक मैनजमैट हैं डमोक्रेसी में यूनियन बनान एक हैल्दी प्रोसीजर है, आपस में मिलकर मैनेजमैट करना अच्छा ढंग है। कुछ सियानी मैनेजमैंट है जो डैमोक्रेटिग नार्म्ज को मानती हैं। इन मैनेजमैट में जो यूनियन्ज है उनकों बाकायदा सम्मान दिया जाता है, इनके प्रतिनिध्यिों को सम्मान दिया जाता है और इनसे समझौता कर लिया जाता है और काम सुचारू रूप से चल जाताहै इसके विपरीत हांसी में मैनेजमैट ने गंडे भर्ती कर लिए है और जो वहां का वैधानिक युनियन है उसको तोड़ने की कोि ा ा की जा रही । आज बीसवी सदी के आठवे द ाक में, लोगों पर डण्डै के

सहारे राज करना, इस मुल्के लिए सम्भव नही हैं हांसी के अन्दर मैनजमैट में लोकल और पूरबयाका सवाल उठा कर बड़ी भारी गड़बड़ पैदा कर दी है। मै हाउस से अपील करना चाहता हूं कि लोकल औ पूरबिया का मसला उठकर यही पर खत नही हो जाएगा, बल्कि कल को पंजाबी औ हरियाणी का सवाल भी आ सकता है, परसों यू०पी० के दूसरो लोग भी सवाल उठा सकत है क्योंकि वहां पर यहां के लोग भी काम करते है। ये सवाल इस लिए उठ रहे है क्योंकि सरकार लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है, बेसहारा लोगों के लिए कल्याणकारी स्कीमें चालू करने में असमर्थ है आर्थिक समस्या हल करने में असमर्थ है। इसलिए इस तरह से ध्यान हटाने के लिए जातिवाद व क्षेत्रवाद का सवाल लाना चाहती है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि सरकार को ऐसे मामलो में, जहां आपसी सम्बन्ध बिगड़ने का खतरा हो, आव यक कदम उठाने चाहिए। यहां तो नोकरियों में ज्यादातर लोग गैरहरियाणवी है। कल के इस तरह का कोई और सवाल खड़ा हो सकता है। सरकार को ते आगे की बात को ध्यान में रखना चाहिए लेकिन बड़े खेद की बात है कि सरकार इस ओर ध्यान नही दे रही है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद में ि ाक्षा के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। बहिन राइी जी इस वक्त तो बैइी नही है लेकिन मै उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है जो उन्होने उन जी०बी०टी० टीचर्ज, जिन्होने अपनी

क्वालिफिके ान बढ़ाली है, हायर ग्रेड दे दिया है लेकिन पता नही उन्होने दूसरे ऐसे टीचर्ज को हायर ग्रेड क्यों नही दिया? क्लासिकल वरनैकुलर टीचर्ज, जिन्होने अपनी क्वालिफिके ान बढ़ा ली है और जिनकी बहुत बड़ी संख्या भी नही, उनको ंभी यह स्केल मिलना चाहिए। मै वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके बारें में भी सहानुभूतिपूर्ण गौर किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपके द्वार परिवहन मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि डैमोक्रेटिव कंटरीज में अपनी बात मनवाने के लिए अगर ऐम्पलाइज महसूस करते है कि हड़ताल करना जरूरी है तो वह उनका कानूनी अधिकार, संविधान है, में भी ऐसी व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज के कर्मचारियों ने कुछ दिन हुए हड़ताल की थी। उसके फलस्वरूप कुछ कर्मचारी नौकरी से हटा दिए गए थे। बाद में कुछ को तो नौकरी पर ले लिया गया लेकिन कुछ रह गए। तो मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उनकों भी वापिस लेने के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण गौर करे। (विघ्न) इन भाब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मै यह आ ाा करता हूं। कि जो बाते मैने कही है, जो सुझाव मैने दिए है, उन पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान (गुडगांव): उपाध्यक्ष महोदय, दस तारीख को जो बजट हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने पे ा किया, मै उसके समर्थन में खड़ा हुआ हू।

डिप्टी स्पीकर साहब, हम सब जानते है कि हमार प्रांत कृशि प्रधान प्रांत है। और यहां के 80 फीसदी लोग कृशि के काम पर ही गुजारा रकत हैं पिछले तीन साल हमारी स्टेट के लिए बहुत ही ऐबनार्मल पीरियड रहा हैं दो साल लगातार बड़ी भारी बाढ़ प्रांत में आई जिसके कारण लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और बहुत ही नुक्सान लोगों को हुआ। इस साल जो स्टेट में सूखा पड़ा है उसे कारण ीाी हमारे किसाना भाइयों को बड़ा नुक्सान हुआ है लेकिन मै अपने किसान भाईयों और प्रांत के मजदूरों को बंधाई देता हूं कि उन्होने कुदरत के साथ काफी बड़ी लड़ाई लड़ी है। जब मौनसून बिल्कुल फेल हो चुका है, उसे बावजूद पैदावार को बढ़ाने में हमारे किसान भाई जुटे हुए हैं इसके साथ साथ में अपनी सरकार और अपने वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होने इन हालात में भी स्टेअ में कोई नया टैक्स नही लगाया। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते है कि टैक्स लगाने के लिए कोई आधार होता है, कोई बेस होता है जब सूखे के कारण हमारा किसान प्रभावित हुआ है, मजदूर प्रभावित हुआ है, व्यापारी को सैट बैक पहुंच है तो कोई सैक्टर ऐसा नही बचता जिस पर टैक्स लगाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो 31 करोड़ का डैफिसिट है इसके लिए मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि बचत के जरिए या केन्द्रीय सरकार की मदद के जरिए इसकों पूरा करने की कोि ा ाकरे। इस बजट पर मेरे कुछसुझाव भी है जो मै सदन के समाने रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्रौप इं ाोरेन्स के बारै में इस सदन मे मैने एक प्रस्ताव राा था और

उस वक्त के कृशि मंत्री ने इस बात को मान लिया था अेर कहा था कि सरकार इसके बारे में में आव यक उपाय करेगी लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ। मै चाहूंगा कि अगर सरकार तमाम फसलों के इं ाोरैन्स का काम एकदम भाुरू न करे सके तो कुछ फसलों जैसे कि आयल सीड्ज है, का ही इन् ाोरैस कर दे। आयल सीड्ज की इम्पोर्ट पर हमारा कृशि फारेन मनी खर्च होता है। भाुरू में आप इस तरह की क्रौप्स को ही ले लीजिए ताकि हमारी फारेन ऐक्सचेंज भी खराब न हो और किसानों को भी इसका फायदा हो। इससे उत्पादन का डायवसिफिके ान भी हो जाएगा क्योंकि किसान अपनी मर्जी से आयल सीड्ज और दूसरी कमि ायल क्रौप्स पैदा करेगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, इरीगे ान कृशि के लिए एक बहुत जरूरी आइटम है। अब भी हमारे प्रान्त में काफी ऐरिया ऐा है जहां इरीगे ान की फैसिलिटी नही हैं यह तो ठीक है कि एस०वाई०एल० के लिए सरकार प्रयत्न करेगी तथा और पानी हरियाणा में लोन की कोि ा ा करेगी लेकिन कुछसोसिर्ज हमारे यहां ऐसे है जो टैप किए जा सकते है। पिछले साल हमारी सरकार ने साहिबी नदी पर मसानी के स्थान पर एक बहुत बड़ा बैराज बनाने का काम भाुरू किया था। उस परकाम जारी हैं साहिबी का पानी हैक्व क्रिएट करता है। मै चाहूंगा कि उस बैराज को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए और उस पानी को जवारह लाल नेहरू कैनाल के जरिए सिचाई के काम में लया जाए। बावल

के एरिया में जहां सब–स्वायल वाटर नही है वहां तक इस पानी को बढ़ा लिदया जाए। इसी तरह से नजफगढ लेक का पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जासकात हैं दिल्ली सरकार ने धांसा बांध बनाया हुआ है। वहां एक तरफ पानी है और एक तरफ दस पन्द्रह गांव है जैसे बम्बोला, बसई, कालियावास और इकबालपरु आदि। उसके बाद रोहतक के गांव है इन गांवों में ब्लैकि ा वाटर है। एक तरफ पानी भरा होता है जो नुकसान करत है। ूदसरी तरफ जमीन है है जहां बिजार्ह के लिए किसानों को पानी नही मिलता। मै चाहूगा कि नजफगढ़ लेक का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना चहिए। वहां पर अगर पानी लिफ्ट भी करना पड़े तो महंगा नही पड़ेगा। उन गावों की सिचाई के लिए इस तरहै की व्यवस्था करना जरूरी है। इसी तरह से कितनी और नदियां है, जैसे घग्गर, टांगरी आदि उनके पानी को जहां जहां कन्टेन कर सकें कन्टेनकरके सिचाई के लिए इस्तेमल करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, बेरोजगारी तमाम दे ा में है और हमारा प्रांत भी उससे बचा हुआ नही हैं हम देख रहे है कि पढ़े लिखे लड़के लाखों की तादाद में बेरोजगार है। उनका नम्बर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मै चाहूंगा कि हमारी सरकार खास ध्यान दे। पिछली सरकार ने रूरल इंडस्ट्रियालाइजे ान की स्कीम चालू की थी। उस प्रोग्राम में अगर कुछ कमिया है तो उनकों ठीक कर दिया जाए। किसान के पास एक एकड़ या दो एकड़ तक जमीन महदूद हैं उका गुजारा इससे

नही हो सकता। मै चाहूंगा कि किसानों और मजदूरों के लड़कों को जो पढ़े लिखे है, सरकार की तरफ से कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमरे यहां डिप्टी स्पीकर साहब 75 फीसदी लोग सिर्फ जमीन के ऊपर निर्भर करते हैं जमीन पर बड़ा भारी प्रै ार है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। डिवैल्पड कंटरीज में पांच या दस परसैट से ज्यादा लोग जमीन पर निर्भर नही करते। ऐसी हालत मे औरभी जरूरी हा जाता हे कि हमारे लड़के इन्डस्ट्री की तरफ जाये। इसी प्रकार स हामर ीसरकार भी इस काम में बहुत बड़ी मददकर सकती हैं कल चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि गुडगांवा के अन्दर जो बस–बाडी–बिल्डिग वर्क ाप खोली जा रही है उसे अन्दर प्राइवेट बसां की बाडी बानाने की भी छूअ दी जाये। बड़ा अच्छा सुझाव है, उस वर्क ाप में हरियाणा रोडवेज की बसों की ही बाड़ी न बने बल्कि प्राइवेट बसों की भी बाडीज बनायी जाये ताकि सरकार को उससे आमदनी हो सके। इस वर्क ाप को कमि र्यिल बेसिज पर चलाया जाना चाहिए। ऐसा करने से हम दूसरी स्टेट्स की बसों का बाड़ी–बिल्डिग का काम भी कर सकते है।

हमारे स्टेट के अन्दर ट्रैक्टर बनाने और दूसरे एग्रीकल्चरल इम्पीलमेंट्स बनाने का भी कोई कारखाना नही हैं ट्रैक्टर्ज इम्पीमेंट्स की कीमते तो पिछले छः सात साल में बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ी है। इतने मंहगे ट्रैक्टर्ज जो किसानों को मारने वाले हैं यह ठीक है कि उनकों ट्रैक्टर के लिए बैकससक

कर्ज मिल जातै लकिन उस गरीब किसानाको कि ते देनी मुि कल हो जाती है। मै चाहूंगा कि ट्रैक्टर्ज एम्पीमेंट्स का कारखाना गुडगांवा में ही लगाया जाये।

मै आपकी सेवा में बेरोजगारी के सिलसिले मं भी अर्ज करना चाहता हू। हमारी स्टेट में फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, हिसार और दूसरे इन्डस्ट्रियल टाउन के अन्दर पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में बड़े बड़े कारखाने लगे है। इसी प्रकार से गुडगांवा में आई०डी०पी०एल० के नाम से एक दवाइयां का कारखाना में बाहर से लड़कों को भर्ती कर लिया जातहै और वहां के रहने वालो लड़कों को नही लगाया जातौं आज हामरे हरियाणा में कितने ही ऐसे लड़के है जो बेकार फिर रहे है इसलिए जो वहां के रहने वाले उनकेां ही लिया जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब एजूके ान भी एक बहुत ही जरूरी सब्जैक्अ है। पिछले साल और इस साल स्कूलों के अपग्रेड किया गया है। सरकार ने यह बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है हमारे यहा कालेजों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। गवर्नमैंट कालेज तो दस–बीस ही होगे लेकिन प्राइवेट कालेट 120 के करीब होगे। इन प्राइवेट कालेजों की मैनजमैंट बाडी भी है। लेकिन फिर भी उनमें काफी कमिया हैं पिछले दिनो हमारी सरकार ने करीब दस कालेजें को टेक–ओवर किया है। हमारे गुडगांवा के द्रोणाचार्य कालेज को भी टेक–ओवर किया है। बड़ा अच्छा काम किया हैं उस कालेज की दो करोड़ रूपये की जायदाद थी लेकिन वहां के स्टाफ को 25

महीनों तक वेतन नही दिया गय। पिछले साल जब मै अपोजी ान में था तो श्री हीरा नन्द आर्य जी को मैने काफी समझाया था कि आप इस काले को टेक–ओवर कर लो। इस कालेज में दो करोड़ रूपये की जायदार है लेकिन वे नही माने परन्तु हमारी सरकार ने बिना सिफारि ा के ही इस कालेज को टेक– ओवर कर लिया, इसके लिए मै सरकार को धन्यवाद देता हूं। दूसरा कालेज जिसका मै प्रैजिडैन्ट भी था, उसकों भी टेक–ओवर कर लिया है, उसक लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी स्पीकरसाहब काफी स्कूलों को अपग्रेड किया गया है लेकिन अब भी रिमोर्ट औ कन्ट्री प्लेसिज पर पांच–पांच और आठ आठ मील तक हाई स्कूल नही हैं इसलिए जहां पर हाई स्कूल की डिमान्ड है और वह गांव भार्त पूरी करता है। तो वहां पर हाई बना दिया जाना चाहिए। देहातों में लड़कियों की ि ाक्षा की तरफ ज्याद ध्यान नही दिया जा रहा है और इसका कारण यही है कि गांवों में लड़कियों के स्कूल नही है। इसलिए लड़कियों में अधिक एजूके ान को बढ़ावा देने के लिए जहां से भी लड़कियों के स्कूल की डिमान्ड आये उसको पूरा कर दिया जाये तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी सिलसिले में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। कि गुडगांवा के अन्दर पांच साल पहले एक बहुत ही बड़ी बिल्डिग स्कूल के लिए बनायी गई थी। उस पर 10–15 लाख रूपये खर्च हुआ था। वहां पर गवर्नमेंट हायर सैकिन्डरी स्कूल नही खोला गया बल्कि दूसरे दफ्तर खोलकर इसका दुरूपयोग कर रहे है। मै चाहूंगा कि वहां पर हायर सैकिन्डरी स्कूल जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिए

क्योंकि गुडगावां भाहर की आबादी भी एक लाख से ऊपर पहुंच गई है।

श्री उपाध्यक्षः आपका समय केवल दो मिनट बाकी है।

चौधरी प्रताप सिंहः देहातों मं पानी की बड़ी किल्लत हैं जिन गांवों में पीने का पानी नही है वहां पर प्रायरिटी बेसिज पर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाये। हमारे गुड़गावां जिले में वाटर सप्लाई स्कीम का काम बहुत कम एरियाज में हुआ है। मेरे अपने हल्के में केवल एक गांव को ही वाटर सप्लाई स्कीम मिली हैं मेरा सरकारसे अनुरोध है कि जहां पर जमीन में खारा पानी है। वहां पीने के पानी को अव य प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने मेवात बोर्ड बनाया है। यह बहुत ही अच्छा काम किया है। यह इलाका सब से पिछड़ा हुआ है, वहां पर किसी भी सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। इस मेवात बोर्ड के अन्दर दो तहसीलों को कवर किया गया है। आप को भली–भांति पता है कि वह इलाका कितना गरीब है लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि गुड़गावां तहसील को भी बैकवर्ड एरिया करार दिया जाना चाहिए क्योंकि यह तहसील भी बहुत गरीब है। महेन्द्रगढ़ का सारा इलाका बैकवर्ड एरिया में आता है, इसी तरह गुड़गावां को भी बैकवर्ड एरिया करार दिया जाना चाहिए।

इसके साथ साथ जंगलात के बारे में भी जरूर अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां पहाड़ का इलाका है। वहां पर द्रखत लगाने का बड़ा ही भारी स्कोप है। उस एरिया में न तो कैनाल साइड पर और न रोड साइड पर द्रखत लगाये है। वहां पर सड़कों की भी बड़ी खराब हालत है इसलिए सड़कें भी जल्द से जल्द बनायी जानी चाहिएं। गुडगावां के अन्दर कोई मैडिकल कालेज नहीं है और न ही कोई इंजीनियरिंग कालेज है उस पर भी सरकार को वि ोश ध्यान देना चाहिए।

11.00 बजे

डा. मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, कई दिनों से इस हाउस में वर्श 1980–81 के बजट पर विचार चल रहा है। 10 तारीख को हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस सदन में बड़ा बोर करने वाला अभिभाशण पढ़ते समय सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले सदस्यों ने, महानुभवों ने बड़ी थपथपियों से, बड़े ताल के साथ इस बजट का स्वागत किया था, करना भी चाहिए था। बजट अच्छा हो या बुरा हो, सरकार का साथ देना ही चाहिए। इन्होने कहा कि यह बड़ा ही भाानदार, बहुत ही खूबसूरत, लुभावना, मनमोहक और टैक्सलैस बजट हैं यह कहते है कि इस में कोई कर नही लगाया गया है, यह बजट कर रहित है। डिप्टी स्पीकर साहब यह कर–विहीन बजट तो जरूर है लेकिन इस बजट में जो 31.14 करोड़ रूपये का घाटे का बजट नही है बल्कि यह

बजट 50 करोड़ रूपये के घाटे का बजट हैं यह टोटे का बजट है।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान, पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री कहते है कि इस खसारे को मोजू वक्त आने पर पूरा लिया जायेगा यानी ठीक समय पर कमी को पूरा करलिया जायेगा। सभापति जी, एप्रोप्रिएट टाईम पर कुछ आने वाल हैं यह टाईम जुलाई के महीने में आने वाला हैं जब सारी विधान सभाओं के चुनाव हो जाएंगे, उस समय तक हरियाणा में भी चुनाव हो जायेगे। जो मेरे भाई दल बदल कर गए है, उनके बारें में जब ऊपर से कुछ ब्यान आता है तो इनका ब्लड प्रै ार हाई हो जाता है और डाक्टरों के पास भागे रहते है। सभापति महोदय, मै कहना चाहता हूं। कि टैक्स तो लगेके ही रहेगे, बे ाक कांग्रेस आई का लत्ता ओढ लिया हो। हमारे यहां पर एक आदरणीय सदस्य है जो नव–युवक है। वे इन्दिरा जी से अपनी बात आरमी करते है, उनकी ही सराहना करते है और फिर धीरे–धरी यू०एन०ओ० तक पहुंच जाते है, फिर वापस हरियाणा के तो ाम इलाके में आ पहुंचते है।

श्री सभापतिः डा० साहब आप बजट पर बोले।

डा० मंगल सैनः सभापति जी नहले तो इन्होने भाबास ले ली है फिर बाद में टैक्स लगा देगे। यह बजट टैक्स–रहित ही

नही, बल्कि लाइफलैस, डायरैक ानलैस और विजडमलैस भी है। चेयरमैन साहब, मेरे एक दोस्त बीच में टोक रहे है, मै उनकों बताना चाहता हूं। कि वे तो पिछली ही मौसम में पहली बार यहां पर आए है। चेयरमैन साहब, मै आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं। कि यहां पर 7 तारीख को हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एक जवाब में एक बड़ी रोचक बात कही।

श्री सभापतिः इन बातों का बजट से क्या संबंध है?

डा० मंगल सैनः इन बातों का बजट से इसलिए संबंध है कि सारे प्रदे ा के गरीब लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, वेस्ट कर रहे है। सारे हरियाणा के किसानों, मजदूरों और मेहनतक ा करोड़ो रूपया जो टैक्स की भाक्ल में देते है, इस सारे के सारे पैसे को ये अपनी राजनीतिक गठबंधन के लिए पानी की तरह बहा रहे है। (ोम भोम की आवाजे) सभापति महोदय, मै इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होने बड़े साफ भाब्दों में कहा..... .....(ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः आन ए प्वायंअ आफ आर्डर सर। अब डा० साहब मजदूरों, हरिजनों और किसानों की हमदर्दी की बात करते है लेकिन उस वक्त यह याद नही आया जब टेलीफोन का लाखों रूपये का बिल आता था? (ाोर)

डा० मंगल सैनः सभापति महोदय, 7 तारीख को राज्यपाल महोदय के अभिभाशण की बहस की समाप्ति पर बोलते

हुए मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि लोकसभा के चुनावों में जनता ने, श्रीमती गांधी को बहुमत दे दिया है, इसलिए हमने मजबूर हो कर अपना चोला बदल लिया है। चेयरमैन साहब, मै उनसे यह बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ कि उन्होने ऐसा क्यों किया? मुझे कर्मो से घृणा है उनसे नही है। I do not hate the sinner, I hate the sin.

Mr. Chairman: Dr. Sahib, I would request you to please speak on the budget. Your time is running short.

डा० मंगल सैनः चेयरमेन साहब, मै कह रहा था कि उन्होने इस बारें में विचार किया। क्या विचार किया? दिल्ली में 15 जनवरी को जनता पार्टी की मीटिग में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि हम चट्टान की तरह मजबूती से खड़े है लेकिन 22 तारीख को ता ा के पत्ते धरा ाायी हो गए। चेयरमैन साहब, एक और रोचक बात मै इनके बारें में बताना चाहता हूं। 'रविवार अखबार' के पेज 42 पर लिखा हैः—

'' ाायद उसकी समझ में नही आ रहा कि केदार पांडे, रामसुन्दर दास और जगन्नाथ मिश्र के बीच क्या, कहां और कितना फर्क है। जब वही माल मिलना है तो दुकानदार के बदल जाने से क्या होगा। यही भजन लाल आते है और विपणन कला को एक नया आयाम देते है। कहते है—मै दर्पण वही, जाने मुझ क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया—नया। माल वही, दुकानदार वही, साईनबोर्ड बदल लिया। ग्राह फंसेगे ही। भजन लाल मीरा से प्रेरित

है। 'जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मतलब मुकुटधारी से है। मुकुट तले खोपड़ी बदल गई तो पति भी बदल गए। जनता पार्टी वाले मुकुट संभाल कर नही रख पाये पत्नी से हाथ धो बैठे''

चौधरी देस राजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। यह किताब पढ * * कर रहे है। बचपन की बात याद आ गई होगी जब ये * * किया करते थे। यहां भी * * अच्छा कर रहे है।

Mr. Chairman: Dr. Sahib, I will Again request you to please confine yourself to the debate under discussion. Otherwise, I will have to get it expuged.

डा० मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मै कहना चाहता हूं कि सिर्फ 30 परसैट वोट्स इन्दिरा गांधी की कांग्रेस को मिली है। (व्यवधान व भाोर) भाई भाम ोर सिंह जी क्लेम करें फिर तो बात समझ में आती है लेकिन आप इस बात को क्लेम करें, यह बात समझ नह आती क्योंकि श्री भाम ोर सिंह तो कांग्रेस में डटे रहे हालांकि अपोजी ान में थे। मै इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी इस बात को कह सकते है। चौधरी सुरेन्द्र सिंह का क्या कहना। इन्दिरा गांधी जी से भाुरू करेगे और अपने पिता जी पर आकरर खत्म करेगे। इनके पिता की तो हिम्मत नही पड़ी कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने की। इनकों पता था कि हमने लोगों की नसबन्दी की हुई है इसलिये लोग हमारे चुनाव में बन्दी कर देगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की टिकट पर खड़े नही हुए। (व्यवधान) चेयरमेन साहब, मै अपनी बात पर आता हूं। चौधरी

बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि एस०वाई०एल० का मामला इसलिये नही निपटा क्योंकि इसमें भाहरी कुलक के लोग मौजूद थे। वह भाहरी कुलक कौन होते है? आप भी भाहर में रहते है, आपकी भी चेयरमैन साहब भाहर में कोठी है, स्पीकर साहब की भी कोठी है हमारे कई मित्रों की कोठियां भाहरों में है, उनके अपने बुजुर्गो की भी कोठी भाहरों में है। वित्त मंत्री जी का तो बड़ा पुराना बंगला है। मेहम में जन्म लिया। हिसार में गोद लिये हुए है, इसलिए इनके बारें में कोई एतराज वाली बात नही होनी चाहिए। हम तो सब कुलक है लेकिन अब तो केन्द्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी का एकछत्र भाासन है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी का भाासन है और हरियाणा में लत्ता बदली हुई सरकार हैं अब तो यह आपस में बैठकर फैसला कर ले। अब इनकों कौन मना करता है। कि एस०वाई०एल० के मामले को न सुलझाये। अगर चौधरी भजन लाल जी कोई ऐसा निर्णय करें, अगर आंदोलन करना चाहते है तो सारी अपोजी ान उनके साथ सबसे आगे होगी लेकिन हिम्मत तो करो.....(व्यवधान व भाोर)

सिंचाई तथा बिजली उप–मंत्री (श्री देवेन्द्र भार्मा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, डाक्टर साहब, बड़े पुराने सुलझे हुए और सीजन्ड पालियामैटेरियल है। इन्होने अभी यह फरमाया है कि अब तो पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी का राज है केन्द्र में भी है और हरियाणा में भी है, अब तो यह एस०वाई०एल० का फैसला कर ले। यह अपनी बात भूल जाते है है। पहले जब

आप होम मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे उस वक्त हरियाणा में भी जनता पार्टी का राज था, पंजाब में भी जनता पार्टी का राज था और सैंटर में भी जनता पार्टी का ही राज था। अपनी बात यह भूल जाते है अपनी बात क्यों नही कहते? (व्यवधान व भाोर)

डा० मंगल सैनः मेरे ये साथी भी उस वक्त जनता पार्टी मैं ही थी। जय प्रका ा नारायण जी के आ ार्वाद से ये चुनकर आ गये है। अगली बार इनकों जनता मुंह नही लगायेगी। (व्यवधान व भाोर) मियां तुम्हारे लिये भी मै झोली फैला–फैला कर वोट मांगता फिरता था। मुझें यह पता नही था कि आप भी इमान बदल लेगे? सो ि ायों इर्कोनोमिक प्रोग्राम के बारे में यह बताया गया है कि जो प्रोग्राम इन्दिरा गांधी ने निर्धारित किया है, हमने उसी हिसाब से यह बजट बनाया है। जनवरी 22 को तो आपने दल बदला है। जनवरी के 10 दिन फरवरी के 29 दिन और मार्च के 10 दिन, सारे मिलाकर 49 दिन हुए इनकों कांग्रेस (आई) में आए हुए। यह बजट तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी अपने बगीचे में गुलाब के पौधे के साथ कोई दूसरी टहनी लगा दे वैसा है, यानी मिक्सड ब्रीड है। यह बजट भी वैसी ही पैदावार लगती है। चेयरमैन साहब, मै एक बात और कहना चाहता हूं कि सो ि ायों इकोनोमिक प्रोग्राम के बारे में मैने चौधरी भजन लाल जी से पूछ था कि क्या यह 20 सूत्रीय प्रोग्राम है? अगर है तो मुझ कुछ सूत्र तो गिना दीजिए। वह कहने लगे कि यह काम तो खुर ाीद जी का है। मेरा काम यह नही है। इनका तो केवल एक

सूत्रीय प्रोग्राम है–कुर्सी पर कैसे बने रहे। चाहे जनता पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे किसी और पार्टी में जायें, परन्तु कुर्सी पर बने रहे।

मेरे आदरणीय स्वामी जी ने मोम के कोटे कीबात की। वे मोम के कोटे पर बड़ा उछलते हैं स्वामी जी, अगर मोम का कोआ नाजायज इस्तेमाल हुआ हैंतो आप इन्क्वायरी करवालीजिये। स्वमी जी मै आप जेसे आदमियों में से नही हूं। जिस महर्शि दयानन्द के आप चेले बने फिरते है, उसने पत्थर खाये, जहर पी लिया लेकिन आने रास्ते पर से हटे नही। ये अपने आपकों महर्शि दयानन्द जी का चेला बताते है। यह तो उनके नाम परएक कलंक है। महर्शि दयानन्द जी तो एक महान हस्ती थे। भारत के करोड़ो लोग आज भी उनके सामने नतमस्तक होते है। उनकी तरफ से यह दावा करना कि मेवात की डिवैल्मैंट के लिये हमने मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया, हरिजनों के पैसे बढ़ाये, एडहाक कर्मचारियों का रैगुलर किया, हमने इतने तीर मारे, भई उस तीन अन्दाजी में आप भी तो भाामिल थे। मै अकेला नही था। स्वामी जी, आप सब लोग भी उसमें भाामिल थे। उस यात्रा में मै अकेला नही था, आप भी हमारे साथ थे। (व्यवधान व भाोर)

श्री देवेन्द्र भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर! चेयरमैन साहब, हम सारे उस यात्रा में भी भाामिल थे जिसमें डाक्टर साहब ने मन्दिर जाने के बहाने सारा ड्राफ्ट का ड्राफ्ट ही बदल दिया था। हम उस यात्रा में भाामिल थे जिसमें उन्होने

दिल्ली में बैठकर अपना रैजीगने ान भेज दिया और यहां आकर वापिस ले लिया। (व्यवधान व भाोर)

डा० मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मेरे साथ तो हालत यह है–

दस्तूरे जबां बन्दी है कैसी तेरी महफिल में,

यहां तो बात करने को तरसती है जबां मेरी।

मै बोलूं तो ये उछल पड़ते है। मगर जरा सब्र रखे।

चेयरमैन साहब, मार्किटिग बोर्ड में सन् 1979 में जितने आदमी भर्ती किये गये थे उनमें से 294 को निकाल दिया गया है और उनमें एक प्रताप सिंह चौहान नाम का आदमी है जो आज भी मरण व्रत पर बैठा हुआ है.....

Mr. Chairman: I would request the hon. Member not to disuss this matter as it has been ruled out to be sub-judice.

डा० मंगल सैनः बहुत अच्छा जी! इस बात की बजट में चर्चा की गयी है कि कुछ कारपोरे ान्ज में घाटा हो रहा है। उन कुछ नेताओं में मै भी भाामिल था जिनके समय में यह घाटे चलती रही है। लेकिन मै एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो 10–11

कारपोरे ान्ज घाटे की है, जो सिर्फ लायेबिलिटी है, करोड़ो रूपया जिनमें बर्बाद हो गया, ये हमें वास्तव में पुरानी कांग्रेसी राज से विरासत में मिली थी। फरीदाबाद में एक टेलीविजन कम्पनी है उसमें 80 लाख रूपये की पूंजी थी, उसमें से 60 लाख रूपये साफ हो गये। इसी तरह से हिसार में पोली स्टील्ज नाम की कम्पनी थी, पता नही कहां से उसके लिये पार्टर ये लोग उइा लाये थे। उसमें 4 करोड़ में से 3 करोड़ रूपये का नुक्सान हो गया। इसी तरह से जींद मे ंऔद दूसरी जगहों पर ऐसी कुछ कम्पनियाय। थी जिनमें घाटा हो रहा था। मैने बार–बार मुख्य मंत्री महोदय से यह कहा कि इनकों बन्द कर देना चाहिए और इनकों वाइन्ड अप कर देना चाहिए लेकिन वे बन्दी नही की गयी। चेयरमैन साहब, इससे आगे मै कहना चाहता हूं कि यहां पर मारूति लिमिटिड के बारें में एक प्र न आया। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उसका जवाब देने के लिये एक महीने कासमय मांगा है। चेयरमैन साहब, पता नही इस का जवाब देने के लिए क्या कसरत करनी है जिसके लिए इन्होने एक महीने का टाइम मांग लिया है?

स्थानीय भाासक मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): चेयरमैन साहब, इस पर कमी ान बैठा था, और सभी कागजात उस कमि ान के पास है, हमारे पास कोई कागजात नही हैं। जब उनसे सभी कागजात हमारे पास आ जाएंगे तो हम जवाद दे देगे।

डा० मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मै आपकों यह बताना चाहता हूं कि जिन महानुभावों ने मारूति लिमिटिड के लिए जमीन मांगी थी, वे लखूका मालिक है, आज सत्ता में भी है 74 एकड़ के लगभग जमीन मांगी थीऔर हमारेपहले मुख्य मंत्री महोदय ने उन्हें साढ़े चार सौ एकड़ भूमि अलाअ करदी। चेयरमैन साहब, उद्यमी क्या करते है कि जमीन एकवायकर करवाते है, पैसे देते है लेकिन यहां पर सरकार ने ही पैसा दिया और उस पैसे की एक कि त मिली, बाकी 9 कि तों का तोपता नही नही है। अीाी कल ही अखबारों मे पढ़ा है कि मारूति का लाइसेन्स कैन्सिल नही किया गया है। एक भाइ कह रहे थे कि वहां पर बसों की बाडी–बिलिडग का काम भाुरू कियाक जा रहा है, क्योंकि वहां पर बसों की बाडीज बड़ी उमदा बनाई जाती है। चेयरमेन साहब, मुस्झे अन्दे ाा है कि यह करोड़ो रूपयके के घपला वाली बात फिर कही भाुरू न हो जाए। चेयरमेन साहब, मेानी हिल्ज की भी एक कहानी है, उसके मालिक थे एक नवाब, उनके औलाद नही होती थी। (घंटी) चेयरमैन साहब, बस पांच सात मिनट में ही खत्म करूंगा। उस जगह पर हमारे पिछले मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी समर कैपीटल बनाने का प्रयास करते रहे। वहां पर काफी पेड़ लगवाये गये और बाद में उनकों कटवाने के लिए 1 करोड़ 10 लाख रूपये का ठेका दे दिया। चेयरमेन साहब, खैर को तो जड़ से ही कअवा दिया और सरकार के कई नेता है, जिनके उसमें मालकीयत हैं मै आरोप नही लगाता, केवल सरकार से इतना ही कहनाा चाहता हूं कि इसका स्पश्टीकरण कर दें ताकि जो 1 करोड़ 10 लाख रूपये

की रा ि ा इस काम के लिये खर्च आई है उसके बारें में हरियाणा की गरीब जनता को किसी किस्म का भ्रम न रहे।

चेयरमेन साहब, इसी तरह से मै एक और बात के बारें मे कुछ कहनाचाहता हूं। सुबह किसी बात पर यहां हाउस में हंगामा हुआ जिसके कारण भाई गंगा राम जी को हाउस से बाहर जाना पड़ा मजबूरी थी। चेयरमेन साहब, वे अपने जजबातों को सम्भाल ने सके और आने मन की सही बात इस हाउस के साने कह ही दी कि किस तरह से रोहतक के अन्दर एक विधवा हरिजन महिला के साथ एक पुलिस कंसटेबल ने भाराब पीकर रेप किया। वह मामल 7 मार्च का था और 8 मार्च को उस बेचारी की पुत्र–वधू के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। कितना अत्चाचार है? जब वे लोग थाने में रपट लिखवाने गये तो रपट दर्ज नही की गई और जब जनता की तरफ से इस के खिलाफ आवाज उठाई गई तो तो रेप की बजाय मौलेस्टे ान का मुकद्दमा बनाया गय। चेयरमेन साहब, आपकों पता ही है कि मौलेस्टे ान में और रेप में क्या फर्क है। वे बेचारे गरीब आदमी डरते रहे कि कही उनके ऊपर झूठा मुकद्दमा न बना दिया जाए और यहां पर मेरे हरिजन भाईयों ने बोलते हुए कहा था कि हमारे हरियाणा राज्य में हरिजनों के साथ कोई किसी प्रकार का अत्यचार नही हो रहा हे, उनकों किसी प्रकार की कोई तकलीफ नही है। चेयरमेन साहब, मै आपकों और बताना चाहता हूं कि भिवानी में एक जूई कलां का किस्सा है। वहां पर भी हरिजनों को परे ाान किया जा रहा है,

इस मामले को भी सरकार अभी तक हल नही सकी है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः डाक्टर साहब, आपके बोलेते हुए काफी समय हो गया है, अब आप वाइंड–अप करें।

डा० मंगल सैनः चेयर मैन साहब, मै पांच मिनअ में ही अपनी बता कहकर समाप्त करता हूं। अभी मेरे अजीज भाई बीरेन्द्र सिंह जी ने एक बात कही कि हिमाचल के मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि मै नाथपा–झाकड़ी प्रोजैक्ट पर पुनविचार करूंगा। मै कहना चाहता हूं कि वहां पर भी दल बदलुओं की सरकार है। रातों रात वहां पर भी कांग्रेस (आई) की सरकार बना दी गई है। यहां भी दल बदलू हमारे मुख्य मंत्री है, ये दोनों बैठ कर आपस में मामला तय कर लें क्योंकि यह तो हरियाणा की लाईफ लाईन है। यह मामला बड़ा अहम है, इसकी तरफ सरकार को अ वय ध्यान देना चाहिये।

चेयरमैन साहब, इससे आगे यहां पर यह भी बात की गई कि जो स्कूल्ज साम्प्रदायिकता फैलाते है, उनकेां एड न दी जाए, मै इस बात को मानता हूं लेकिन ऐमरजैनसीके दिनों में जिन स्कूलों के विद्यार्थियों और अध्यापकों को जेलों में ठोंसा गया, कम से कम ऐसे स्कूलों को तो सरकार को ध्यान रखन चाहिये। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः सभापति महोदय, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर है, डाक्टर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे है, उन स्कूलों के अध्यापकों और विद्यार्थियों की ऐमनजैन्सी के दिनों में जेलों में नही भेजा गया था (विघ्न)

डा० मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मै उसके ंप्रिसीपल की बात कर ाहू हूं एक बार गये, दूसरी बार फिर गये। चलो चेयरमेन साहब, इस बात पर ही ये आ जाएं, अगर मै गलतप हूंगा तो मै इस्तीफा दे दूंगा, नही तो ये इस्तीफा दे दें। (ाोर व व्यवधान) चेयरमेन साहब, मेरे भाई अभी अमर में कच्चे है.....(ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः डाक्टर साहब, आपकासमय यहो गया है आप अब खत्म करे।

डा० मंगल सैनः बस, चेयरमैन साहब, मै आखरी बात कह कर अपना स्थान लेता हूं। मै वित्त मंत्री महोदय जी को यह कहना चाहता हूं कि हगर वे वास्तव में खर्चे में बचत करना चाहते है तो अपनी मिनिस्टरी की संख्याको कम करें। जहां तक इनका ताल्लुक है, यह एक दफा पार्टी छोड़कर इधर आने लगे थे फिर बाद में पता नही क्या मजबूरी हो गई। इलेक ान के दिनों में तो कांग्रेस पार्टी को यह एक भाख्भी हकूमत बाते ि लेकिन अब खुद उसी हकूमत में भाामिल हो गये हैं इन भाब्दों के साथ ज्यादा न

कहता हुआ, आप भी बार–बार कह रहे है, आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री लछमन सिंह (कालका): चेयरमेन साहब, 10 मार्च, 1980 को, तायल साहब ने जो बजट यहा पे ा यिका है, मै उसकी स्पोर्ट करेने के लिये खड़ा हुआ हूं। लोकदल और जनत पार्टी के भाईयों और बहनो ंने उस परबोलते बोलते अपने क्ष्यालात रखे है। जैन साहब ने अपनी स्पीच में सब सेपहले एक बात की कही..... .....(विघ्न)

चौधरी जय नारायणः चेयरमेन साहब, सरदार लछमन सिंह जी से यह कहा जाए कि वे अपना स्पश्टीकरण दें कि वे किस पार्टी से ताल्लुक रखते है?

श्री लछमन सिंहः चेयरमेन साहब, मै बोल रहा था कि जैन साहब ने सब से पहले अपनी स्पीच पर बोलने हुए, सरकार परयह दोश लगायाथा कि हरियाणा सरकारने रूरल इंडस्ट्रीलाइजे ान की पालिसी को बदल दियाहै और इस सम्बन्ध में उन्होने बजट स्पीच में पेज 22 के कुछ अलफाज भी कोट किये थे। अब मै आपकों व इस सदनको पेज 21 पर जो कुछ लिखा है, वह बतलाने जा रहा हूं। उसके अन्दर लिखा है–

"As further encourgement to the tiny units inthe rural areas, Government is providing the following package of incerntives to them:—

(i) Supply of the feasibility reports free of cost;

(ii) Exemption from electricity duty for a eriod of 7 years and exemption from sales tax and purchase tax for a period of 2 years on a raw msterials etc;

(iii) A 20% price preference and 50% additional allocation of controlled raw materials;

(iv) Interest free loan inlieu of central sales tax for a period of 7 years and also exemptionfrom duty on self generation of power for 7 years."

यह जो पेज नम्बर 22 पर लिखा हे, यह पालिसी मैअर से सम्बन्धित है। चेयरमेन साहब, मै भी यही कहता हूं कि जब तक केन्द्र सरकार हरियाणा के अन्दर कुछेक जगहों को बैकवर्ड डिकलेयर नही करती, जब तक इंडस्ट्रीलाइजे ान नही हो सकती। मै यहां पर बतानाचाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने परवानू के इलाकें को भी बैकवर्ड डिकलेयर किया हैं वहां पर काफी इंडस्ट्रीज लगाई गई है। और लगाई भी जा रही हैं इसके मुकाबले मैं हरियाणा साइड मैं इडस्ट्रीज पनप सकती हैै लकिन हयां पर पोल्यू ान हैं कालका के इलाकें में इंडस्ट्रीज पनप सकती है, अगर केन्द्र सरकार इसकों बैकवार्ड डिकलेयर कर दे और फिर इंडस्ट्रीज लगाने के लिये सबडिी भी दी जाए। मै डाक्टर साहब का आभारी हूं कि उनहोने अपने वक्त में कालका के बारें में लिखा थ परयह स्कीम किन्ही कारणों से सिरे न चढ़ सकी। अगर इस जगह पर सरकार की तरफ से इंडस्ट्रीज की सहूलियतें दी जाएं तो तो ऊपर की इंडस्ट्रीज यानी जो लगो इधरसे ऊपर इंडस्ट्रीज लगाने के लिये

गये है, वे वापिस आ जायेगे और इस तरहै सारी दंडस्ट्री नीचे की तरफ आ सकती है। जैसा कि जैन साहब ने कहां कि हमारे प्रांत में बेराजगारी बहुत है, अगर हमारे हरियाणा के अन्दर इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी तो उससे बेराजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी और लाखो ंबेराजगारों को इससे लाभ होगा। इसलिये हमारी सरकार को इसके लिए प्रयत्न करने चाहिये कि केन्द्र सरकार से इस काम के लिये सबसिडी मिले ताकि हमारे हरियाणा प्रांत में खु ाहाली हो। चेयरमैन साहब, मेरे और बहुत से दोस्तों ने यहां पर बजट के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि यह बजट बड़ा कलरलैस है, टेस्टलैस है और साथ ही डाक्टर साहब ने भी बड़े ड्रामोटिक अन्दाज में बोलते हुए कहा। ये इस हाउस के बड़े तजुबेंकार मैम्बर है लेकिन क्या करें, अरमान मन के अन्दर ही रह गये। इनकौं पता नही था कि तायल साहब इनकों ता दे जाएंगे। इनके अन्दर अरमान था कि यह बजट एंटी किसान होगा औरहम इसकी कापियों फाड़ कर फेकेगे और इस तरह हमारी फोटो अखबारों में आएगी। लेकिन जब बात उल्ट निकली तो यह लाबी मेंचले गये और कहने लगे कि यह इलैक ान बजट है। एक बात और बताना चाहता हूं कि ये दल बदलू की बात पर बहुत जोर दे रहे थे। डा० साहब जनता के दरबार में यह प्वायंअ लेकर अये तौकि दल बदलुओं को सबक सिखा दो। जिनके खिलाफ आप दल बदलुओं का नारा लेकर गये थे वे तो लोक दल के आदमी अच्छे रहे लेकिन आप लोकसभा में 92 थे और आज 12 रहे गये है (ाोर) डा० साहब आप अपने गिरेबान में मुंह डाल कर नही

देखते। जिस चीज को अपन दल बदलू कहते है वह दल बदल नही हैं आप अपनी पार्टी को तो गांग में धुली हुई कहते है और हमें दल बदलू कहते हों हमने दे ा की 65 करोड़ जनता की आवाज को सुना?। वे लाग कहते थे हम दे ा की बागडोर श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में में सौपना चाहते हैं इसलिये हमने तो जनता की भावनाओं पर फूल चढ़ाए है। चेयरमेन साहब, एक तरह तो ये लोग ऐसी बातें करते करते है, लेकिन जब हमें ये प्राइवेटली मिलते है तो कहते है कि आपने हमारी नौकरी बचा दी। यहां हाउस में तो ये लोगों को दिखाने के लिये ऐसी बाते करते है।

डा० मंगल सैनः चेयरमेन साहब, मेरा प्वायंअ आफ आड्डर है। सरदार लछमन सिंह मारे पुराने जानकार है और जेलों में हम इकट्ठे रहे है। ये जेल में श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारें में क्या कहा करते थे जरा वह भी बता दे।

श्री लछमन सिंहः चेयरमैन साहब, जेल के अन्दर मेरे खिलाफ यह इलजाम था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का श्रद्धालु है। ये ईमानदारी से यह बात बात दें कि मैने कभी श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ बोला हो। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं अभी मेरे मित्र ने कहा जब हम इनकों प्राइवेटली मिलते है तो हम कहते है कि हमारी नोक्री बचा दी। यह बिल्कुल गल्त

बात है हमने कभी भी ऐसे नही कहा। चेयरमेन साहब ये भाब्द कार्यवाही से एक्सपंज होने चाहिएं। (ाोर)

डा० मंगल सैनः चेयरमैन साहब, जब से इन्होने दल बदलाा है तब से मेने इनसे कोई बात नही की है। (ाोर)

चौधरी जय नारायणः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायं आफ आर्डर हैं अभी सरदार जी ने कहा कि हमने इनकों कहा कि हमारी नौकरी बचादी। चेयरमैन साहब, यह बिल्कुल गल्त कह रहे है हम इधर से 40 आदमी लिख कर दे देत`है और यह भी लिख दे कि असैम्बली को भंग करवा दो। (ाोर)

श्री लछमन सिंहः चेयरमेन साहब, मै अर्ज कर हा था कि जब इन को बजट में आलोचना करने वाली कोई बात नही मिली तो इन्होने इसकों इलैक ान बजट कह कर अपना पीछा छुडा लिया। जैन साहब, डाक्टर साहब और मेरे बहुत दूसरें दोस्तों नें कहा कि इस बजट में गरीबों के लिये, हरिजनों के लिये, हरिजनों के लिये और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिये कुछ नही है। बजट पढ़ने के बाद अगर गौर से देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के मैनिफैस्टों के मुताबिक इसबाजट में गरीबों के लिये, बे–सहारा लोगों के लिये, बेरोजगारेां के लिय, हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिये सब से ज्यादा प्रायरिटी दी गई है.....

श्री जय नारायण वर्मा: चेयरमैन साहब, ये बजट पर बोल रहे है या मैनिफैस्टो पर? (ाोर)

श्री लछमन सिंह: चेयरमेन याहब, मै कभी किसी को इन्ट्रप्अ नही करता लेकिन समझ में नही आता कि ये लोग मुझे क्यों इन्ट्रप्अ कर रहे है? (ाोर)

श्री सभापति: मै दोनों तरफ के मैम्बर साहिबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे चेयर को ऐड्रैस करें और माननीय सदस्य को आराम से सुनें।

श्री लछमन सिंह: चेयरमैन साहब, डिवैल्पमैंट के जितने भी प्रोग्राम है अगर आप उन पर नजर दोड़ा कर देखे तेा आपकों पता लगेगा कि चारों तरह आज सूखा है। और हर चीज की भाार्टेज है लेकिन इसके बावजूद भी हम एग्रीकल्चर प्रोडयूस 21 लाख टन प्रोक्योर करने जा रहे है जबकि पिछल साल यह 18 लाख टन थी। इसी तरह से आप रोडज के बारे में देखें, कितना बड़ा प्रोग्राम हैं हर गांव को 1980 तक पक्की सड़के से जोडत्र दिया जाएगा। इसके बाद पीने के पानी की बात हजैं इसमें कोई भाक नही कि इस मामले में सब से ज्यादा प्रायरिटी मिलनी चाहिये। मै आपकें एक बात बतानाचाहता हूं कि यह महकमा एक साल चौधरी बीरेन्द्र सिंह के पासरहा था और उस वक्त किसी को यह पता ही नही था कि इस नाम का कोई महकमा भी है ईमानदारी से यहां पर कोई भी आदमी कह दे कि किसी को इस

बारें में पता था। इसके बाद जहां तक इरीगे ान की बहुत4 ज्रूरत है। मै चीफ मिनिस्टर साहब, फाइनैस मिनिस्टर साहब और इरीगे ान मिनिस्टर साहब के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि इस मामले मे ंसबे ज्यादा अम्बाला जिलाक इग्नोर्ड हैं कालका, नारायणगढ, मोरनी औद छछरौली के जो इलाके है, यहां पर इरीगे ान की कोई फैसिलिअी नही हैं इसके बारें में मै एक तजवी जरखना चाहता हूं कि जैसे नाढा साहब के पास सायल कंजरवे ान वाले 72 हजार रूपये की लागत से एक डैम बनाने जा रहे हैं उसी तरह से आप छोटे–छोटे प्राजैक्ट बना कर हाथ में लें। लेकिन हमारे इरीगे ान डिपार्टमैंट वाले सिर्फ करोड़ो रूपये का प्रोजैक्ट बना कर हाथ में ले लें लेकिन हमारे इरीगे ान डिपार्टमैंट वाले सिफ करोड़ों रूपये का प्राजैक्ट ही हाथ में लेते है क्योंकि छोटे–छोटे प्रोजैक्टस से उनका कुछ बनता नही। इसलिये मै इरीगे ान मिनिस्टर से कहूंगा कि जो इलाके मैने बताएं है इनमें इस किस्म के प्रोजैक्ट लग सकते है लेकिन इरीगे ान डिपार्टमैंट उसमें दिलचस्पी नही लेता। मै कहूंगा कि ऐसे प्रोजैक्टस को डिपार्टमैंअ अपने हाथ में लें।

चेयरमैन साहब, इसके अलावा मै एक बात और कहना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर एम०आई०टी० टयूबवैल्ज लगाने का काम करती है और सरकार टयूबवैल्ज लगानेके लिए 25 फीसदी सबसिडी देती है। जब तक कालका के एरिया में 50 फीसदी सबसिडी नही दी जाएगी तब तक उस इलाके का काम अच्छी तरह

से नही चल सकता। एम०आई०टी०सी० वाले कहते है कि हमारे पास इतना पैसा नही है। चेयरमेन साहब, उस इलाके को इस सरकार को इतनी नीची लजरों से नही देखना चाहिए बल्कि उस इलाके की इमदार करनी चाहिए। यदि यह सरकार उस इलाके की इमदार करेगी तो यह इमदार गरीब किसानों की इमदार होगी। चेयरमैन साहब, जहां तक अम्बाला जिले के रेवेन्यू का ताल्लूक है, हरियाणा प्रदे ा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार अम्बाला जिले के रेवेन्यू का ताल्लुक है, हरियाणा प्रदे ा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को अम्बाला जिले से प्राप्त होता है। लेकिन जहां तक अम्बाला जिले में कृशि पर खर्चे का ताल्लुक है, वह सब जिलों से कम होता है। चेयरमैन साहब, यह रिकार्ड की बात हैं मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह अम्बाला जिले का पूरा ध्यान रखे और इस जिले के लिए कुछ साधन जुटाए। चेयरमेन साहब, मै टूरिजम डिपार्टमैंट को मुबारिकबाद दिए बगैर नही रह सकता क्योंकि इस डिपार्टमैंट ने बहुत अच्छा काम करके हिन्दूस्तान में हरियाणा प्रांत का नाम बुलन्द किया हैं इसलिए यहां हाउस में यह कहना कि टूरिज्म डिपार्टमैंट में कोई काम नही हो रहा है, मै समझता हूं यह डा० साहब की तरफ से बडत्री बेइन्साफी होगी। चेयरमैन साहब, यह बात सभी जातने है कि कुछ दिन पहले डा० साअब भी मंत्री की कुर्सी पर विरनाजमान ि और ये पालिसी बनाया करते थे। यह तो हो सकता है कि अब उनकी कसुी खुस गई और डा० साहब को नजर नही आता कि कहां जाऊ। (ाोर एवं विघ्न)..... चेयरमेन साहब, मै आपके द्वारा हाउस को एक बात बातना चाहता

हूं कि डा० साहब ने बजट पर चच्रा करते हुए मोरनी की पहाड़ियों की बात कही थी। डा० साहब, ने कहा कि मोरनी की पहाड़ियों में खैर के द्रखत अप–रूट हुए है। चेयरमैन साहब, आप यू०पी० सरकार को 1960 से लेकर 1970 तक का रिकार्ड मंगवा कर देख ले। यू०पी० सरकार ने खैर के द्रक्षतों को अप–रूट किया है। वहां पर यह कहंडी ान वाईडिग है कि हर खैर के द्रखत को अप–रूट किया है। वहां पर यह कंडी ान बाईडिग है कि हर खैर के द्रखत को अप–रूअ किया जाएगा। चेयरमैन याहब, अप–रूटिग करने के लिए ठेकेदारकोईपैसा नही देता क्योंकि अप–रूटिग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता हैं चेयरमैन साहब, आप हरियाणा फारैस्ट डिपार्टमैंट का रिकार्ड मंगा कर देख ले। एग्रीमैंट में एक क्लाज है। उस क्लाज में यह लिखा हुआ है कि ठेकेदार सरकार का गुलाम नही हैं ठेकेदार तो सिर्फ एग्रीमैंट परकाम करता है। चेयरमैन याहब, हमारा फारेस्ट डिपार्टमैंट बहुत ईमादारहैं इस डिपार्टमैंट के 5 अधिकरियों की एक कमेटी होती है। जब फारैस्ट में आक ान होती है तो उस वक्त यह कमेटी वहां पर मौजूद होती है और आक ान की मंजूरी सरकार देती (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, एग्रीमैंट में यह क्लाज मौजूद हैं कि आक ान करने के बाद ठेकेदार को खैर के द्रखतों को अप–रूटकरना पड़ेगा। आप फारैस्ट इंस्टीच्यूट, देहरादून से किताब मंगवा करदेख ले, उस में लिखा है कि खैर के द्रखत की रूट में एक कीड़ा लगता है जसके कारण खैर का द्रखत जल्दी खत्म हो जाते। इस द्रखत को ज्यादा देर तक खड़े रखने का कोई फायदा

नही है। इसलिए इस द्रखत को अप–रूट किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, डा० ने कहा कि मोरी की पहाडिरूों में खैर के द्रखत अप–रूट हुएहै, यदि इसमें हमारा कोई कंसूर हो तो मै डा० साहब के सामने झुकाने क लिएतैया रहूं और डा० साहब, मेरे कान में कह देत, जो सजा वे देगे वह मुझ मंजूर है। मै एक मिनट भी नही लगाऊगा, मैम्बरी से इस्तीफा दे दूंगा। स्पीकर साहब, यह आज की बात नही हे, यहा हमारा खानदारी पे ाा है। यह बात हाउस के लोग भी जानते है। स्पीकरसाहब, मै दो बार हरियाणा की सरकार मे ंमिनस्टिर रहा हूैं और कसम खा कर कह सकता हूं कि मैने ईमानदारी के साथ काम किया हैं मै आपने विरोधी पक्षक के दोस्तों से कहता हूं कि वे अपने गिरेवान में मुह डाल कर देखे। इनके बारमें मे भी अखबारों की खबरों को सच माल लिया जाये तो पता नही डा० साहब के खिलाफ कितने केसिज होगे। इसलिए अखबारों की तरफ ध्यान न दे। अखबार वालों को तो अपन अखबार बेचना हैं मुझे आप सभी लोग जानते है तै कि करैक्टर का आदमी हू। (ाोर एवं विध्न)

Mr. Speaker: I would request the hoh. Member to please concertrate on the Budget.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मै इस सरकार से अर्ज करना चहाता हूंकि जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार भी उस समय मै उसमें मिनिस्टर था। मैने अपने हल्के के अन्दर नारायणगढ और छछारौली में कुछ स्कूल मंजूर करवाए थे और

चण्डी गढ़ दसे कालका तक सड़क भी मंजूर की थी। यह तो हा सकता है कि चण्डीगढ़ से कालका की रोड रोहतक वालों को फिन न हो लेकिन इसके साथ कालका के इलाके को लोगों का भविश्य जुड़ा हुआ है। यह सड़क बनने से चण्डीगढ के साथ उन लागों के ताल्लुकात बढ़ेगे और लोगो को रोजगार भी मिलेगा। जब चण्डीगढ़ को हम पंजाब को देने के लिए तैयार नही है और हम कहते है कि चण्डीगढत्र हमारा, तो हमें इसके लिए 10–5लाख रूपया खर्च करने मे कोई हिचकिचहाट नही होनी चाहिए। पंजाब ने इसके लिए 55 लाख रूपया खर्च करने के लिए माना हुआ है। लेकिन हरियाणा को तो इसमें केवल 15 लाख रूपया ही लगेगा। यह सड़की सीधी कसौली और िामला को निकल जाएगी। मै सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इन बातों कपर गौर किया जाए। इन भाब्दों के सारूथ मै इस बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

डा० मंगल सैन द्वारा

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अगर इन्होने आप पर कोई एस्प ार्न कास्ट किया हो तो आप कुछ कहना चाहेगे।

डा० मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वैसे तो मेरे ऊपर कोई एस्प ार्न कास्ट नही किया। लेकिन इन्होने जो अखबारों के बारें में कहा उस बारें सिर्फ मै इतना ही कहना

चाहता हूं कि अखबारों में जो आया था उस बारें सरकार स्पश्ट करें कि क्या मामला आया था।

वर्श 1980–81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भले राम (बड़ोदा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, किसी प्रदे ा का बजट अच्छा या बुरा कहे, इससे पहले हमें इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए कि बजट पे ा यिका इसमें किसी प्रकार का कोई न्याया हुआ है या नही। इसमें जो पैसे का बंटवारा है उसकी आईटमवाईज व्यवस्था ठीक या नही, व्यक्तिगत भाोशण को समाप्त करने का ध्यान रखा गया या नही, लोागें पर इसका काई बर्डन तो नही पडत्रा तथा इस प्रदे ा में प्रोडक ान की प्रोग्रैस हुई है या नही इन पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। स्पीकर साहाब, इन बातो ंपर गौर करने के बाद हमे ंसोचना चाहिए कि यह बजट अच्छा है या नही। हमारे फाईनैस मिनिस्अर साहब ने अपनी बजअ स्पीच मे ंएक बात की कि आव यकता पड़ने पर टैक्स लगाया भी जासकते है ंस्पीकर साहब, फाईनैस मिनिस्टर साहब ने यह कह कर लोगों पर बर्डन डाल दिया। इसलिए मै इस बाजट को अच्छा नही कहता जितना यह अच्छा होना चाहिए था उतना नही है।

स्पीकर साहब, सरकार कहती है कि इरीगे ान के लिए नहरों मे ंपानी बढ़ायेगे। सिंचाई क कलिए पहले हलन लोहारू कैनाल, सिवानी कैनाल और जवाहरलाल नेहरू कैनाल बनी हुई हैं

इन नहरो ंमें जो पानी चल रहौ, इसको बढ़ाने के लिए खाल पक्के कर दिए लेकिन असल में खल पक्क नही हुए हैं मंत्री जी तो गांव में जाते ही नही, उन्हें क्य पता कि खाल पक्के है या नही। जो लोग गांवों में रहते है उन से पूछिए, ज्यादातार नहरें आज बन्द पड़ी है और जिन मे ंपानी चल रहा है वहा खल कच्चे है सारी पानी जायाहो जाता है। एक बार मै गांव में एम०आई०टी०सी० टयूबवैल देखने गया। जो पानी उस टयूबवैल से निकल रहा था वह खल कच्चा होने की वजह से जाया हो रहा था। सब जगह खालों की यही हालत है अब रहा सवाल नहरों को पक्का करने का। जनता सरकार के आईम पर लहरे पक्की होने के प्रयास होरहे थे लेकिन इस सरकार के आने से वे बन्द हो गये है क्योंकि इंटों का भाव महंगा, सीमेट नही मिलता, ऐसी हालत मे ंनहरें कहां सक पक्की होगी। जो नहरे पक्की बनी हुई है वहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प ाुओं को पानी पीने के लिए घाट नही बनाये गये। मेरे इलाके में बुटाना डिसिट्रूटूटरी है, उसमें प ाुओं के लिएकोई घाट नही है। मै सरकार से दरखवास्त करूंगा कि नहरों मे प ाुओं के लिए घाट बनाये जाएं ताकि मवे ाी पानी पी सकें।

अब में बिजली के बारें मै कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक ान बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चरल उत्पादन के लिए बिजली का बढ़ना आव यक है ताकि जो प्रोजेक्ट भाुरू किए हुए है वे कामयाब हो सके। लेकिन स्पीकर साहब, कई बार हमारे आफिसरों की लापरवाही से बडत्रे बड़े

नुक्सान हो जाते हैं मेरे नोटिस में आया है कि पानीपत थर्मल प्लांट मे आफिसर्ज की लापरवाही से 4 लाख रूपये पैडल खराब हो गया। यह लापरवाही कैसे हुई? थर्मल प्लांट के एस०डी०ओ० को ट्रांसफर कर दिया और उसकी जगह एक वर्कचार्ज रखा लिया। कर्व चार्ज अैक्नीकल हैड न होने के कारण कुछ नही जानता था। जिसका परिणम यह हुआ कि इतना भारी नुक्सानहो गया। स्पीकर साहब, आप देखे एक तरफ सरकार बिजली बढ़ाना चाहती है और दूसरी तरफ आफिसर्ज की लापरवाही के कारण इतना भारी नुक्सान हो रहा हैं मै सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह जो चार लाख का घाटा हुआ है, जिस आफिसर की लापरवाही से हुआ है, उस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। अब मै फलड के बारें में जिक्र करना चाहता हू। पिछले दिनों स्टेट में सूखा पड़ा और यह सरकार चाहती है कि सूखा पड़ता चला ाजए क्योंकि सरकार फलड की रोकथा के लिए कोई कदम नही उठा रही ह। हर बीमारी काइलाज पहले होना चाहिए। हिन्दूस्तान में मेलरिया खत्म हो गया था लेकिन दोबारा आ गया, इसको रोकने के लिए हमारे पास दवाई होनी चाहिए। इसी तरह फलड भी दोबारा आ गया, इसकी रोकथाम के लिए ड्रेन्ज बनाई जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने सारी ड्रेन्ज बनाई जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने सारी ड्रेन्ज बन्द कर दी और ड्रैन्ज के लिए जितना पैसा रखा गया था वह दूसरी तरफ दूसरें कामों के लिए डाइवर्ट कर दिय। अब सरकार कहती है कि उसके पास ड्रैन्ज खोदने के लिए पैसा नही है। बजट में फलउ के लिए पैसा रखना चाहिए, आज नही तो कल फलड

दोबारा आ सकता हैं इसलिए मै सरकार से गुजारि ा करूंगा कि अधूरी ड्रैन्ज पूरी की जाएं ताक आने वाले फलड के खतरें से बच सके।

ि ाक्षा के बारें मे थोडा सा अर्ज करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, प्रजातन्त्र की सफलता के लिए ि ाक्षा का स्तर ऊंचा होना बड़ा आव यक हैं आज जो डिप्रैस्ड क्लास है, वह ि ाक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं किसी दे ा के नौजवान पढ़े लिखे नही होगे तो वे अच्छे नुमांयदे चुनकर नही भेजंगे, अनपढ़ होने की वजह से डिफैक्टर ही चुनेगे, इसलिए ि ाक्षा की तरफ सराकर वि ोश ध्यान देना चाहिए। स्पीकरसाहब, मै इस बात को मानत हूं कि मेरे इलके में काफी स्कूल अपग्रेड किए गए है। यह बैकवर्ड इलाकें में ज्यादा स्कूल अपग्रेड किएजाए, ज्यादा स्कूल खेले जाए। ये बच्चे भी तो हमारे अपने ही है, अगर सरकार ने इनके लिए स्कूल अपग्रेडकर दिए तो कौन–सी बुरी बात है? जहां तक ि ाक्षा के स्तर का सवाल है, आज स्कूलों में पढ़ाई का भट्ठा बैठा हुआ है स्पीकर साहब, श्रीमती भाान्ति राठी को पता नहै कि आज ि ाक्षा का स्टडर्ड गिरता जा रहा है, खासकर हरिजन क्लास का बुरा हाल है। इस सिलसिले में मै सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। प्राईमरी स्कूलों मे ंपहली से पांचवी क्लास तक.....

श्री अध्यक्षः जब आपने हैडमास्टरी छोड दी तो भट्ठा बैठना ही थी। (हंसी)

चौधरी राम कि ानः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मेरे साथी चौधरी भले राम मेरे मित्र है, मुझे वे क्षमा करेंगे, मै उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब वे हैडमास्टर थे और मैथेमैटिक्स पढ़ाते थे तो मैथेमैटिक्स में इनका जीरों परसैट रिजल्ट आता था। (हंसी)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है।

श्री भले रामः मै छोटी क्लास को नही पढ़ाता था, छोटी क्लास को तो भाान्ति राठी पढ़ाया करती थी और मै हाई स्कूल की क्लासिज को पढ़ाया करता था। (हंसी) स्पीकर साहब, मै सुझाव दे रहा था कि पहली क्लासे से पांचवी क्लास तक एक ही अध्यापक पढ़ाए और लास्ट में इम्तिहान हो। रिजल्ट को जो नार्म सरकार फिक्स करे, अगर उस नार्म से नीचे उस मास्टर का रिजल्ट आता है तो उसकों सजा मिलनी याहिए। एक अध्यापक एक जगह पर आठ सालतक उसी क्लास में रहना चाहिए। इसके इलावा हैडमास्टर को ज्यादा पावर्ज देनी चाहिए ताकि उनके खिलाफ कोई एक ान ले सके। आज हैडमास्टर को पावर्ज देनी चाहिए। ताकि उनके खिलाफ कोई एक ान ले सके। आज हैडमास्टर को पावर्ज ही नही है।सबसे बूरी बात यह है कि हैडमास्टर की बदली सिफारि ा के आधार पर हो जाती है, इसीलिए वे परवाह नही करते, पढ़ाई कैसे करवा सकते है? स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की तहसील गोहाना में एक स्कूल है, इसकी बड़ी खस्ता हालत है। हमने केस तैयार करके ऊपर भेजा हुआ है, फाइल की

मूवमैंट जीर है और मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस स्कूल को टेक–ओवर किया जाए। पता नहीं सरकार ने अब तक क्यों टेक ओवरनहीं किया। स्पीकर साहब, कांग्रसी भाइयों ने हाउस में बड़ी दोहाई दी कि हरिजनों की बड़ी भलाई की जा रही हैं, बड़ी फिगर्ज कोट की हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि पिछले साल के बजट में भाड्यूल्ट कास्ट और बैकवर्ड क्लासिज के लिए 244 लाख रूपये के करीब रखा गया था जिसमें कर्मचारियों की तन्खाहें और एस्टेबलि ामेंट का खर्चा भी आ जाता है। इसमें से 80–90 लाख रूप्या हरिजन कल्याण निगम को दे दिया आध्ैर कुछ बैकवर्ड क्लासिज को भी दिया और कुछ रूपया लैप्स हो गया। स्टेट में हरिजनों की संख्या 20–25 लाख है जिसमें 4 लाख के करीब हरिजन परिवार हैं। मुि कल से इतनी बड़ी संख्या में 66 लाख रूपया खर्च हुआ होगा, बाकी या तो लैप्स हो गया या इधर–उधर चला गया। स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल ने हरिजन चौपालों के लिए 95 लाख रूपया बजट में रखा था, मुझे अच्छी तरह याद हैं। आज वह सारे का सारा पैसा लैप्स हो गया। अगर लैप्स होने के आसार थे तो इस पैसे को हरिजनों की किसी दूसरी स्कीम में क्यों नहीं डाल दिया। गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है, जो स्कीमें जनता सरकार ने बनाई थीं वे सभी बन्द कर दी हैं, पिगरी की स्कीम थी वह भी बन्द कर दी और हरिजनों के लिए दो हजार रूपये हाउसिज बनाने के लिए सरकार ग्रांट देती थी, वह भी घटाकर एक हजार कर दी और कह दिया कि एक हजार सरकार देगी और तीन हजार निगम कर्जा

देगी। स्पीकर साहब, हरियाणा में 1373 गांवों को यह सरकार हाउसिंग ग्रांट देगी जिसमें 11 जिले हैं, एक जिले में 121 गांव। मेरे कहने का मतलब यह है कि 6 गांवों के हिस्से एक मकान की ग्रांट आती है। इस तरह से हरिजनों का कल्याण कैसे होगा ?

12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि हरिजनों की दुहाई देते हैं इसलिए मैं आपके जरिए सरकार को कहूंगा कि अगर आप हरिजनों को ऊपर उठाना चाहते हैं, मांगते तो आने हम बना ही दिए हैं, तो एक हरिजना वैल्फेयर फंड स्थापित किया जाए। अब सवाल यह है कि इसमें पैसे कहां से आएं ? जिस तरह से हम फलड रिलीफ फंड के लिए मांगते फिरते हैं, कोई रजाई दे देता है, कोई अनाज दे देता है, कोई पैसे दे देता है, उसी तरह से इस फंड के लिए भी हम पैसे और चीजें इकट्ठी रकें क्योंकि मांगने वाले आपके पास बाबा जी जैसे बहुत बैठे हैं। (हंसी व भाोर)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सो ाल वैल्फेयर के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे साथी रण सिंह मान जी एक वर्ग की ओल्ड एज पैन ान के लिए हाउस में प्रस्ताव लाए थे लेकिन मैं कहता हूं कि यह पैन ान सबको मिलनी चाहिए, चाहे कोई आई.ए.एस. हो, चाहे आई.पी.एस. हो, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई किसान हो या व्यापारी हो, क्योंकि बुढ़ापा बहुत बुरा होता ळै। कोई नहीं पूछता और छोरे भी डांट मारते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे एक बात याद आ गई जो इस प्रकार है:–

आजकल के छोरे देखे मां बापों पर मारे डांट,

सीधी देकर गाली बोलें सुन ले रे बूढे खुरांट,

तेरा अब खटा ना होगा, घर से बाहर बछा ले खाट। (हंसी)

तो इस प्रकार बूढ़े की हालत होती है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और याद आ गई। एक नौजवान जा रहा था। उसको देखकर एक बुढ़िया रोने लगी। लड़के ने उसे देखा और कहा कि माता जी क्यों रो रही हो ? बुढ़िया सुबक सुबक कर रोने लगी और कहाः–

रोके बुढ़िया बोली रे, बुढ़ापा बैरी खोटा,

घर पर नायन बुलाया करती, पट्टी मांग जमाया करती,

करी कराई खोली रे, बुढ़ापा बैरी।

गलियों में गिरकाया करती,

गूंद पंजीरी खाया करती,

खाली पड़ी बरौली रे, बुढ़ापा बैरी। (विघ्न)

आज न सुनता कोई हमारी,

कभी लाई थी पलंग निवारी,

अब टूटी पड़ी खटौली रे,

बुढ़ापा बैरी खोटा।

बाबा को बुलाया करती,

भूतनी कढ़वाया करती,

रहता था मकड़ौली रे, बुढ़ापा बैरी (हंसी एवं भाोर)

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है इसलिए ओल्ड एज पेन् ान सबको मिलनी चाहिए।

मास्टर ि ाव प्र ााद (अम्बाला भाहर): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में इस दलबदलू सरकार के एक मंत्री ने जब बजट पे ा किया तो ऐसा अहसास हो रहा था कि कोई मरसिया पढ़ रहा है। (ाोर) दुःख इस बात का है कि इस बजट में कौमन मैन के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। मेरे से एक दो दिन पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने, जनता पार्टी के भाासन काल में लोगों को जो राहत मिली, उसका एक एक करके जिक्र यिका लेकिन एक दो बातें मेरे लिए भी छोड़ दीं। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि वाल्मीकियों की तनख्वाह में जो 50 रूपये की बढ़ौतरी की गई थी वह जनता पार्टी की सरकार ने की थी। ये तीस साल तक हरिजनों का नाम लेकर सरकार चलाते रहे लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके वेतन में वृद्धि कर

सकें इसी तरह से पी.डब्लयू.डी. के अन्दर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी जो 6 रूपये से 8 रूपये की गई वह जनता पार्टी के भाासन काल में की गई, इनके भाासन काल में नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी के अखबार में, जिस दिन इस सरकार ने चोला बदला था, एक ब्यान यह था कि हम तो अपने घर में वापिस आ गए, एक ब्यान मे यह था कि हम डैपुटे ान पर गए हुए थे, एक ब्यान यह था कि हम तो बारात में भाामिल हो गए। इन ब्यानों का जिक्र करते हुए मुझे एक बात याद आ गई। किसी लड़की की भाादी हो गई और वह अपने ससुराल में चली गई, अपने पति के घर में चली गई। दस पन्द्रह साल तो उन्होंने आराम से गुजार लिए लेकिन उसके बाद उनकी कुछ अनबन हो गई ओर दोनों पति पत्नी दु:खी रहने लगे। पति ने पत्नी के ऊपर लांछन लगाया और हालात ऐसे पैदा हो गए कि पत्नी अपने पति का घरबार छोड़ गई ओर किसी दूसरी जगह रहना भाुरू कर दिया। दो अढ़ाई साल के बाद जब उसके पति ने दखा कि मेरे पास तो पैसा नहीं लेकिन मेरी पत्नी किसी अमीर के घर में रहने लगी है तो उसने उसे प्रलोभन दिया और अपने घर में ले आया। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि तू यहां कैसे आई, तेरे ऊपर तो इसने लांछन लगाया था ? तो वह कहने लगी कि घर तो मेरा वही है, यहां तो मैं डैपुटे ान पर आई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप बजट पर बोलें।

मास्टर ि ाव प्र ाादः यह बात बजट से सम्बन्धित है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दो तीन दिन पहले क्वै चन अवर में मधुबन के सिपाहियों का जिक्र आया कि उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। उसके उतर में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पुलिस के सिपाहियों में अनु ाासन होना चाहिएं मुझे यह सुन कर खु ाी हुई कि किसी न किसी तरह मुख्य मंत्री जी के दिमाग में अनु ाासन नाम का भाब्द तो आया लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अनु ाासित जीवन जिस व्यक्ति का होता है, उसका जीवन एक आद र्ा होता हैं। जिस समाज में अनु ाासित जीवन वाले लोग होंगे वह समाज उन्नति करता है, जिस दे ा में अनु ाासित जीवन वाले लोग होंगे वह दे ा भी कभी कभी जगत गुरू कहलाने का हकदार बन जाता है। लेकिन क्या मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या केवल पुलिस के सिपाही को ही अनु ाासन में रहना चाहिए ? क्या केवल फौज में लड़ने वाले सिपाही को ही अनु ाासन में रहना चाहिए ? क्या सरकारी कर्मचारी को ही अनु ाास्न में रहना चाहिए ? क्या केवल व्यापारी को ही अनु ाासन में रहना चाहिए और राजनीतिक लोग ऐसे हैं जिन्हें अनु ाासित जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए ? (विघ्न) मैं तो समझता हूं कि अगर आपने दे ा का सुधार करना है, दे ा की उन्नति करनी है तो राजनीतिक लोगों को सबसे पहले अुन ाासन में रहना होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गई किः—

फूल तो दो दिन बहारे जा फिजां दिखला गए,

हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। (प्र ांसा)

इन लोंगों के अन्दर सीजन्ड दल बदलू हैं जिनके जीवन का लक्ष्य ही दल बदल करना है। जिसके हाथ में सरकार हो उसके साथ ही वे हो लेते है। अध्यक्ष महोदय, उन सीजन्ड दल बदलुओं का तो मुझे दुःख नहीं, दुःख तो मुझे उन लोगों का है जिनका राजनीतिक जीवन ही 1977 में जनता पार्टी के मंच से भारू हुआ था। उन बेचारे गुंचों को इन सीजन्ड दल बदलुओं ने अपने स्वार्थ के लिए बिना खिले ही कुचल दिया। (विघ्न) सीजन्ड दल बदलु वे लोग हैं जिनकी अन्तर आत्मा मर चुकी है। मास्टर होने के नाते से मेरा यह फर्ज है कि उस मरी हुई आत्मा को प्रेरणा दे दूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मास्टर जी, आप बजट पर बोलें।

मास्टर ि ाव प्र ादः अध्यक्ष महोदय, मै आज पहली बार सै ान मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अनु ासन कौन पैदा करता है ? अनु ासन पैदा करने का काम केवल ि ाक्ष के क्षेत्र में काम करने वाल अध्यापक के साथ सम्बन्धित है, जिसे ने ानल बिल्डर कहा जाता है।

स्पीकर साहब, अब मैं ि ाक्षा के विशय में भी कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर बजट के

अन्दर अधिक से अधिक पैसा ि ाक्षा क्षेत्र में काम करने वालों पर व्यय किया जाता तो न आपको सड़कें टूटी हुई मिलतीं और न ही वे लोग, जिनके बारे में आप यह कहते हैं कि वे बेईमानी कर गये, वे बेईमान बनते। ि ाक्षा अच्छी होगी तो न चीफ इंजीनियर बेईमानी करेगा और न ही कोई अन्य व्यक्ति करेगा। ि ाक्षक ने अच्छे व्यक्तियों को पैदा करना है। इस सरकार ने ि ाक्षकों के लिए कुछ नहीं यिका, मामूली सी आंसू पूछने वाली बात है। अम्बाला भाहर, अम्बाला छावनी, फरीदाबाद ओर जगाधरी–यमुनानगर और रोहतक में कुछ अलाउंस दिया है यह तो अच्छा किया परन्तु अगर आप को ि ाक्षकों से हमदर्दी थी तो गांवों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी दिया जाना चाहिए। ट्रांसफर के लिए अधिक मात्रा में आप लोगों के पास क्यों आते हैं, सिर्फ इसी हाउस–रेंट के कारण आते हैं। बड़े बड़े अफसर अपने रि तेदारों को कहर में या भाहर के नजदीक आठ किलो मीटर के फासले पर लगवाते हैं ताकि उनको हाउस रेंट मिलता रहे। सभी जगह बारबर हाउस रेंट दे दियसा जाये तो यह दिक्कत न हो। भाहरों में या 5 मील के एरियें में काम करने वालों को मिलता है परन्तु 5 मील के एरिये से बाहर काम करने वालों को हाउस रेंट नहीं मिलता। ट्रांसफर पोलिसी इसीलिए कामयाब नहीं है कि उनको हाउस रेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। गांवों में काम करने वाले अध्यापकों को अधिक पैसा और सुविधायें प्रदान करनी चाहिए। यदि भाहर मे रहने वाला अध्यापक गांवों में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसको दस परसैन्ट गांव अलाउन्स मिलना चाहिए। जो

टीचर गांवों में पढ़ाने जाये उसको बस का पास फ्री मिलना चाहिए। उसको गांवो में जाने के लिए एक दो घंटे लगते हैं, यदि उसको बस का पास फ्री मिल जाये, तो वह गांव में जाने से नहीं हिचकिचायेगा।

स्पीकर साहब, मैं एक बात की ओर डिपार्टमैंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बी.ई.ओ. के पास कहीं पर 50 और कहीं पर 53 स्कूल दिये हुए हैं। उनको वहां पर चैक करने में बड़ी दिक्कत होती है। उनके पास आने जाने के साधन नहीं है जिसके कारण सारे स्कूलों को चैक नहीं कर सकता। एक बी.ई.ओ. के पास ज्यादा से ज्यादा 20 स्कूल होने चाहिएं और बी.ई.ओ. का दफतर उन गांवों के सैन्टर में किसी गांव में बना दिया जाये। ऐसा करने से उनको चैक करने में सुविधा हो जायेगी।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार जब किसी एस.डी.ई.ओ. को डी.ई.ओ. से कोई काम पड़ता है तो वह टेलीफोन न होने से सम्बन्ध्ण स्थापित नही ंकर सकता। उसको या तो किसी दूसरे दफतर में टेलीफोन करने के लिए जाना पड़ता है। या कोई सन्दे ा भेजने के लिए आदमी भेजना पड़ता है। इसलिए वहां पर टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए।

स्पीकर साहब, मैंने अभी तक आपकी सेवा में सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की दिक्कतें रखी है। अब मैं कुछ प्राईवेट स्कूलों के अध्यापकों की दिक्कतें भी रखना चाहता

हूं। अगर सारे हरियाणा के परिणामों में से प्राईवेट स्कूलों के परिणाम निकाल दिये जाये तो गवर्नमैंट स्कूलों का क्या परिणाम होगा यह मुझे बताने की आव यकता नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के अलावा कोई भी एम.एल.ए. या मिनिस्टर या अफसर अपने बच्चों को सराकर स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं है। जब ऐसी पोजी ान हो तो सरकार को उन प्राइवेट स्कूलों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। प्राईवेट स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को कम वेतन मिलता है। सरकार के अलावा उन स्कूलों की मैनेजमैंट कमेटी भी बनी हुई हैं उन अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। यह बात सरकार के नोटिस में भी है। अगर किसी अध्यापक को चार सौ रूपये वेतन देना है तो उसको 250 रूपये दिया जाता है। इसलिए इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज्यादा अच्छा काम करने वालों को ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, ज्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिए, लेकिन यह सरकार अच्छा काम करने वाले, अच्छा रिजल्ट देने वाले को दुतकारती है, उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। इस तरीके से प्राईवेट स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको पूरा वेतन दिलाने की एक ही तरीका है कि उनको खजाने से वेतन दिलाया जाये, चाहे इस बात के लिए गवर्नमैंट को घाटा बरदा त करना पड़े। सबसे ज्यादा जरूरी ि ाक्षा का क्षेत्र है। इन अध्यापकों को न हाउस–रेंट मिलता है और न मैडिकल अलाउन्स मिलता है। कमाने वाले बेटे को माता पिता छाती से लगाते हैं परन्तु यह सरकार ईमानदारी से काम करने वाले अध्यापकों को

दुतकारती है और काम नहीं देती (घंटी)। स्पीकर साहब मैं तो पहली बार असैम्बली में आया हूं। थोड़ी सी समय की कृपा दृश्टि रखें।

स्पीकर साहब, कुछ ला एन्ड आर्डर के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। हरियाणा में ला एंड आर्डर का सत्याना ा हो रहा है। मैं आपकी सेवा में एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अम्बाला भाहर से आगे जो जी.टी. रोड पर पैट्रोल पम्प है, वह किसी कांग्रेसी का ही है। वहां पर गावं में रहने वाले यूथ कांग्रेस के लोगों ने डीजल की डिमान्ड की। उसने कहा कि मेरे पास डीजल खत्म है लेकिन वे कहने लगे कि हमें कुछ नहीं पता, हमें डीजल चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि आप डी.सी. या डी.एफ.ओ. से परमिट ले आओ, आपको डीजल दे दिया जायेगा। वहां जाने की जरूरत नहीं हैं, हमें तो बिना परमिट के डीजल चाहिए। उन यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो भी वहां पर आदमी थे, उनको बुरी तरह से पीटा। अगर वहां पर पुलिस का अमला और डी.एस.पी. न पहुंचता तो कोई बचने वाला नहीं था।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, ये कायदे कानून की बात करते हैं। इनके बारे में हमें पता है। यूथ कांग्रेस वरकर्ज गांव गांव में है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई ब्लैक मार्किटिंग करता हो, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसको जरूर चैक करेंगे। यह गलत बात है कि यूथ कांग्रेस वरकर्ज ही गलत बात करते हैं।

श्री अध्यक्षः अब आपका टाईम हो गया है।

मास्टर ि ाव प्र ाादः यदि आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन मेरी स्पीक के बीच में बोलते हैं, उसका समय भी तो मुझे मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि वहां पर पुलिस ने जाकर उनको बचाया। दोनों पार्टीज के विरूद्ध केस रजिस्टर्ड हुए लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा के .....

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, बिल्कुल निराधार और गलत बात कह रहे हैं। जब उस केस की इन्कवायरी हुई तो यह पाया गया कि पैट्रोल पम्प का मालिक डीजल ब्लैक में बेच रहा था। कांग्रेस वरकर्ज ने कुछ नहीं किया।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी कह रहें हैं कि इन्कवायरी हुई है। आप सदन की एक कमेटी बना दीजिए उससे पता लग जायेगा कि इन्कवायरी हुई थी या नहीं पर कितनी गुंडागर्दी हुई थी।

मास्टर ि ाव प्र ाादः स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ब्लैक माकि।ट करने वालों पर बने हुए केस वापस लेने की किसने इजाजत दी थी ? यूथ कांग्रेस वालों को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप हरियाणा की सारी

पुलिस को घर पर भेज दें और यूथ कांग्रेस के युवकों द्वारा तमाम हरियाणा में ..... होने दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः आर.एस.एस. के युवकों द्वारा वहां पर ..... की गई जबकि नाम यूथ कांग्रेस का लिया गया। (व्यवधान)

सरदार सुखदेव सिंहः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब हर सिटीजन का यह फर्ज है कि वह ब्लैक मार्किट को रोके, चाहे वह आर.एस.एस. से संबंध रखता हो, चाहे जनसंघी हो चाहे किसी और पार्टी से संबंध रखता हो। जो भी गड़बड़ करते हैं उन सब को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार जो प्र ाासन की हालत खराब होती जा रही है उसको और खराब न होने दिया जाये।

श्री अध्यक्षः आपका समय हो गया है। अब आप वाईन्ड अप करें।

मास्टर ि ाव प्र ाादः स्पीकर साहब, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। अम्बाला जिले में अस्पताल के लिए,ख गवर्नर एड्रैस और बजट के अन्दर कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया। जिस हस्पताल के नये भवन का पत्थर 11–2–80 को रखा गया वह जल्दी मुकम्मल होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः आपका समय हो गया है। आपने 18 मिनट ले लिए हैं।

मास्टर ि ाव प्र ाादः स्पीकर साहब, मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं कि अम्बाला जिला एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। अम्बाला जिलें की पहाड़ियों में वर्शा होती है लेकिन उस पानी से अम्बाला जिले के लोगों को कोई फायदा नहीं होता बल्कि लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। गांव बाढ़ आने से तबाह हो जाते हैं, बह जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आने वाले वर्श के अन्दर टांगरी और मारकण्डा, जो बरसाती नदियां हैं, इनका सर्वे करवा कर दो बांध बन्धवायें जायें ताकि अम्बाला जिले की जनता को बाढ़ के पानी का लाभ हो सके। सारे हरियाणा में अम्बाला जिले की धरती सबसे ज्यादा प्यासी है। यहां पर बैकवर्ड लोग निवास करते हैं। अम्लाला जिला की जमीन में ट्यूबवैल नहीं लग सकते जिसके कारण खेती को ट्यूबवैल का पानी भी नहीं मिल पाता। अगर इन बांधों का निर्माण कर दिया जाये तो सूखी जमीन को पानी भी मिल सकेगा और लोग भी बाढ़ से तबाह होने से बच जायेंगे। मेरे साथी सरदार लछमन सिंह जी भी जानते होंगें कि अम्बाला जिले में ऐसे गांव भी हैं जहां पर गांव के लोग पीने के लिए जोहड़ के पानी को इस्तेमाल करते हैं। उस पानी को जानवर, प ाु, पक्षी सभी पीते हैं इसलिए अम्बाला जिला में तड़पती हुई जनता के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाये।

जनता पार्टी की सरकार ने अम्बाला के लिए एम नग्गल लिफ्ट स्कीम की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसलिए मैं जनता

पार्टी द्वारा किए गए इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। स्पीकर साहब, मैं इस दल–बदलू सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नग्गल लिफ्ट स्कीम पर अमल किया जाये और उस स्कीम के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाये ताकि यह स्कीम मुकम्मल हो सके और अम्बाला के लोगों को पानी की राहत मिल सके।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं कम से कम 10–15 मिनट अव य बोलूंगा। स्पीकर साहब, हामरे वित्त मंत्री महोदय ने वर्श 1980–81 का जो बजट यहां हाउस में पे ा किया है, उसका समर्थन करता हूं। वह समर्थन क्यों करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि 50 करोड़ रूपये का घाटा होते हुए भी इस सरकार ने हरियाणा की जनता पर कोई कर नहीं लगाया। यदि कोर्ं कर लगा दिया या होता तो मेरे ख्याल में हरियाणा में हल्ला–गुल्ला हो जाता। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और मुझे आ ाा है कि हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय चौधरी भजन लाल, केन्द्रीय सरकार स अधिक से अधिक मात्रा में रकम ले आएंगे और हरियाणा की गरीब जनता की भलाई हो सकेगी। (ाोर) चेयरमैंन साहब मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, उस समय वह सरकार थी जिसमें डा. मंगल सैन और बहन कमला वर्मा जी भी मंत्री पद पर थे, जब मुझे

फरीदाबाद के अन्दर गिरफ्तार किया गया, मुझ पर केस बनवाए गए और लाठियां चलाई गई, इन्हीं का यह सारा काम था। आज ये लोग गरीबों के नाम से आंसू बहाते हैं। मैं आपके द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय वे कहां गए थे जब फरीदाबाद के अन्दर गोलियां चल रही थी ? उस वक्त डा. मंगल सैन खामो ा रहे। आज ये मेहनतक ाों और गरीब लोगों के हक में कैसी लच्छेदार बातें वि ोशण लगा कर रहे हैं ? मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि हितकारी पोटरीज में आज भी भूख हड़ताल चल रही है। वहां पर हमारे प्रिय नेता श्री संजय गांधी जी आये। (ाोर)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। अभी हमारे आदरणीय मैंबर साहब ने फरमाया है कि हितकारी पोटरीज में भूख हड़ताल चल रही है और वहां पर इनके प्रिय नेता संजय गांधी गए थे। तो मैं आपके द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं कि कब से वे इनके प्रिय नेता बन गए ? (व्यवधान)

श्री दीप चन्द भाटियाः जिस समय चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी तो उस समय डा. मंगल सैन जी कुर्सी के न ो में थे। ये किसी से बात तक नहीं करते थे। (ाोर) जिस समय चौधरी देवी लाल जी की लीडरी में डा. मंगल सैन को हटाया गया तो उस वक्त फरीदाबाद के अन्दर चौधरी भजन लाल ने डा. मंगल सैन को चेलैंज किया था कि मेरे साथ मुकाबला कर लो। लेकिन उस वक्त डा. मंगल सैन जी को चौधरी भजन लाल जी के .....

. (व्यवधान व भाोर) उस वक्त ये कोई और बात नहीं कर सके थे लेकिन आज ये बड़े लच्छेदार भाशण दे रहे थे। बड़ी एक्विंटग कर रहे थे। जब हम बोलने लगते हैं तो यह प्वांयट आफ आर्डर रेज कर देते हैं मगर जब ये बोलते हैं तब हम बिल्कुल भी कोई प्वांयट आफ आर्डर रेज नहीं करते। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) ये लोग आज बदली की बात करते हैं। मैं आपको इनकी बदली की बात बताऊं। इन लोगों को हमारी बदली पर तो दुःख हुआ लेकिन उस वक्त दुःख नहीं हुआ। जब इनको डिप्टी लीडरि ाप और इंडस्ट्रीज मिनिस्टरि ाप मिली थी। क्या इन्होंने मिनिस्टरी और लीडरी के लिए बदली नहीं की ? इनके द्वारा किये हुए ..... भगवान के दरबार में हाजिर किये जायेंगे, तब इनको सजा मिलेगी। (व्यवधान व भाोर)

डा. मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो इन्होंने ... . का भाब्द कहा है, यह रिकार्ड में नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः 'घोटाला' भाब्द कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री दीप चन्द भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ा सीरियस मामला है, इसकी इंकवायरी होनी चाहिए। पता नहीं क्या–क्या इन्होंने किया हुआ हैं। मैं आपको एक रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि जो सच्चाई की बातें हैं, वह रिकार्ड से कटाई नहीं होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे वह दिन याद है जब

दयानन्द कालेज के अन्दर विद्यार्थियों की एक सभा हो रही थी तो इनको कोई काम करने के लिए कहा गया था। उस वक्त इन्होंने यह कहा था कि क्या करूं मेरा एक हाथ तो यहां रहता हैं और दूसरा हाथ कुर्सी पर रहता हैं। बड़ा मु कल है मेरे लिए आपका यह काम करना। यदि इनकों कुर्सी मिली रहे फिर तो ठीक है नहीं ..... (व्यवधान व भाोर)

चौधरी जय नारायणः डिप्टी स्पीकर साहब, पता नहीं भाटिया साहब ने कितनी बाद दल बदले हैं लेकिन फिर भी इनको कुर्सी नहीं मिली। (ाोर व व्यवधान)

श्री दीप चन्द भाटियाः चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा इन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह जो लोग बैठे हुए हैं यह अपने आपको सुपर हिन्दू बोलते हैं। इनको कोई भी दूसरा हिन्दू नजर नहीं आता है। (व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्षः आपके दो मिनट बाकी रहते है। (व्यवधान व भाोर)

श्री बलदेव तायलः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मजाक, नान–सीरियस बातें, पर्सनल एलीगे ान और एक्टिंग ये सारी चीजें भाायद रूल्ज के अन्दर प्रोवाइडिड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनको आपने बोलने की इजाजत दी, यह बोलते रहे। मगर मेरी गुजारि ा यह है कि अब इन्होंने पूरी हिन्दू जाति पर ही आक्षेप लगाना भाुरू कर दिया है .....

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order. Please sit down.

भाटिया साहब, आप दो मिनट में खत्म कीजिए। (व्यवधान)

श्री दीप चन्द भाटियाः बहुत अच्छा जी। डिप्टी स्पीकर साहब, अब चूंकि कई आदमी बहुत दुःखी हो रहे है इसलिए अब मैं इन सच्ची बातों को छोड़ता हूं क्योंकि आपको पता है, सच्चाई कड़वी होती है। कोई भी सच्चाई बर्दा त नहीं कर सकता। अब मैं फरीदाबाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं (व्यवधान व भाोर) ला–एंड–आर्डर आपको नजर नहीं आता। हमारे यहां तो ला एण्ड आर्डर खुद ही देख लो, कितना अच्छा है, लोग कितनी भाान्ति से बैठे हुए हैं। जब आप बोलते हैं तो हम कोई प्वांयट आफ आर्डर रेंज नहीं करते लेकिन जब हम बोलते हैं तो आप लोग बार बार प्वांयट आफ आर्डर रेज करते हो। (व्यवधान व भाोर) बजट के बारे में जैसे मैंने पहले बताया है, 50 करोड़ रूपये का खसारा होने के बावजूद भी चौधरी भजन लाल की हरियाणा सरकार ने जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। यह टैक्स इसलिए नहीं लगाया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन्दिरा गांधी जी की केन्द्रीय सरकार से कुछ न कुछ लेकर आयेंगे। कई लोगों को यह बात समझ नहीं आयी। वे लोग सात्विक लोग नहीं हैं। जब वे मीट–मुर्गे खाकर आते हैं और बोलते हैं तो उनको यह समझ नहीं आत कि इन्होंने क्या बोलना है। जब तक बजट में डैफिसिट नहीं होगा तब तक

हम केन्द्रीय सरकार से कुछ ले नहीं सकते। इन लोगों को डिप्टी स्पीकर साहब, आप जरा समझाये। इन लोगों को आप समझायें ताकि यह लोग असलियत को समझ सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा इस बारे मे न कहता हुआ ब फरीदाबाद के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। यहां पर हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वे पहले चौधरी देवी लाल की सरकार में चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी भी रहे हैं, तब घ्भी उनके पास ट्रांसपोर्ट का महकमा था और आज भी इनके पास वही महकमा है। आज भी जब ये मिनिस्टर बने हुए हैं तो मैं इनके सामने एक दो मांगे रखना चाहता हूं। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद टाउन के अन्दर जो बस स्टैंड है, चाहे उसको हरियाणा सरकार चलाये, चाहे फरीदाबाद न्यू–टाउन ि ाप चलाये, वहां से सीधी बस चंडीगढ़ आनी चाहिए लेकिन कोई बस चंडीगढ़ सीधी नहीं आती। पलवल जो कि एरिये में इससे छोटा है और कम आबादी वाला इलाका है, वहां से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस चलती है लेकिन फरीदाबाद न्यू टाउन ि ाप से, जो कि हरियाणा का एक मिन्नी इंडिया है और करोड़ों रूप्ये का रैवेन्यू हरियाणा को देता है, इसके बावजूद भी वहां से चंडीगढ़ के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है। इसी तरह कई और जगहों के लिये भी सीधी बस सेवा नहीं हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्षः आप सब समाप्त कीजिये।

श्री दीप चन्द भाटिया: मैं जल्दी जल्दी अपनी बातें रख रहा हूं। मेरी मांग यह है कि फरीदाबाद न्यू टाउनि ाप से एक बस जम्मू के लिए एक चंडीगढ़ के लिए और एक हरिद्वार के लिए अव य ही चलायी जायै। (व्यवधान व भाोर)

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अपनी सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो फरीदाबाद कम्पलैक्स है, वह चण्डीगढ से बड़ा है, यहां पर लोकल बसें चलती हैं, लेकिन वहां पर लोकल बसों का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए वहां पर सरकार लोकल बसों का प्रबन्ध करवायें ताकि लोगौं को आने जाने में जो दिक्कतें हैं, वह दूर हो सकें। मुझे पूर्ण आ ाा है कि हमारे मुख्य मंत्री व सम्बन्धित मंत्री, श्री जगन्नाथ जी इस तरफ खास तवज्जो देंगे और वहां पर जल्दी ही लोकल बसें चलाने का हुक्म देंगे।

इससे आगे मेरा निवेदन है कि हमारे फरीदाबाद में बहुत ज्यादा फैक्टरियां हैं, और उन में बहुत सारी लेबर काम करती है लेकिन वहां पर यूनिट्स के हिसाब से डीजल की सप्लाई बहुत कम है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वहां पर डीजल की परसेन्टेज बढ़ाई जाए। इससे अगला प्वांयट मेरा स्कूलों की अप–ग्रेडे ान के बारे में हैं, आर्य जी इसके मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं लेकिन फिर भी एक बात उनके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने अपने हल्के में 13 स्कूल अपग्रेड किये हैं वहां हमारे हल्के में कोई भी स्कूल अप–ग्रेड नहीं किया है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि

वह इस तरफ ध्यान दें आदैर पिछली सरकार के जो काम अधूरे रह गये हैं, उनको पूरा किया जाए, स्कूलों को अप–ग्रेड किया जाए और नये स्कूल भी खोले जाएं। फरीदाबाद के साथ बल्लभगढ़ और पलवल का इलाका लगता है, वहां पर सरकार की तरफ से हर किस्म की सुविधा दी जा रही है लेकिन हमारे फरीदाबाद को इग्नोर किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। हमारे पास फण्डज पड़े हुए हैं, बिल्डिंग फण्डज भी हैं, केवल स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाए बाकी हम स्वयं देख लेंगे। अतः मैं फिर अपने एजुके ान मिनिस्टर साहब से यह रिक्वैस्ट करूंगाकि वे इस तरफ ध्यान दें और जो स्कूल्ज अपग्रेड होने वाले हैं, उनको जल्दी ही अपग्रेड किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे अगला प्वांयट मेरा यह है कि फरीदाबाद में एक ही बी.के. हस्पताल हैं। वह हस्पताल बाद ााह खां के नाम से म ाहूर है, जिसको सरहदी महात्मा गांधी कहा जाता है। वहां पर अगर आप जाकर देखें तो आप को मालूम होगा कि अब उस हस्पताल को बूचर खाना बना दिया गया है। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि उस हस्पताल की जगह एक नये हस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार की हैरानी न हो और सभी लेबर तबका और दूसरे लोग उस हस्पताल का फायदा उठा सकें।

श्री उपाध्यक्षः भाटिया जी, आपका टाइम खत्म हो गया है, आप वाइंड अप करिये।

श्री दीप चन्दी भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, बस एक दो मिनट में ही खत्म करता हूं। अब मैं सड़कों के बारे में भी कहना चाहता हूं। यहां पर सड़कों के महकमें के मिनिस्टर कंवर राम पाल सिंह जी बैठे हैं, उनसे कहता हूं कि देहाती भाईयों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती हैं क्योंकि सभी जगहों पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्षः भाटिया जी, अब आप बैठियें।

श्री दीप चन्दी भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, एक दो मिनट और दे दीजिये, एक दो बड़ी जरूरी बातें कहने के लिए बाकी हैं। मैं ज्यादा न बोलता हुआ केवल एक दो बातों के बारे में ही कहूंगा। मैं इस बजट का तहदिल से समर्थन करता हूं ओर एक बात कहता हुआ अपनी बात खत्म करूंगा कि हम सब भाई यहां पर बैठे हुए हैं, पोटिलीकल बात नहीं कर रहा। मैं भजन लाल जी से ऐसा कहूंगा की गद्दी तो आनी जानी है। हो सकता है जो अब आया है, वह अगली बार एम.एल.ए बनकर भी न आ सके और किसी वक्त भी कोई आदमी जेल में जा सकता है। इसलिये मेरी सभी भाईयों से यह निवेदन है कि वे सभी मिलकर प्रयत्न करें कि जेलों में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मेरी यह सरकार से प्रार्थना है कि वह इस तरफ खास तवज्जो दें और जेलों के अधिकारियसों को इस तरह की हिदायतें होनी चाहिये कि वे सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी को कोई असुविधा न होने पाए। मुझे आ ाा है कि मुख्य मंत्री महादेय, व दूसरे मंत्री जो

इस विभाग से सम्बन्धित हैं, मेरी प्रार्थना पर अव य विचार करेंगे। इन लफ्जों के साथ, मैं डिप्टी स्पीकर साहब, आपका भाुक्रिया अदा करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी हुक्म सिंह (दादरी): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस बजट में तकरीबन 50 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया है और इस बजट में इस बात का कोई इ ारा नहीं कि किस तरह से यह घाटा पूरा किया जाएगा या किसी विकास के कामों पर इस घाटे का पूरा करने के लिए कट लगाई जाएगी या कोई बड़े टैक्स हरियाणा की जनता के ऊपर लगाये जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बजट तो केवल हरियाणा की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाया गया है। महज जनता के साथ एक धोखा है, यह बिल्कुल खोखला बजट प्रस्तुत किया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे ा है और 80 प्रति ात लोग खेती पर निर्भर करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि 1979–80 में खेतीबाड़ी के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से 17.48 करोड़ रूपया रखा गया था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने राज्य में इस को घटाकर 17.40 करोड़ कर दिया है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी राम कि ान, पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, इस

सरकार को चाहिए था कि इस रकम को और बढ़ाया जाए लेकिन बढ़ाने की बजाये इस सरकार ने इस पैसे को और घटा दिया है। आपको पता है कि जब तक खेतीबाड़ी का काम ठीक तरीके से नहीं पनपेगा तब तक कल–कारखानों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। चूंकि हरियाणा प्रदे ा का सारा दारोमदार खेतीबाड़ी पर निर्भर करता है, इसलिए सरकार को इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। इस सरकार का सारा ध्यान भाहरों की तरक्की की तरफ ही है और गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, यह सरकार पर मेरा आरोप है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान, मजदूर विरोधी सरकार है वरना यह सरकार खेती के लिए किसानों की द ाा को सुधारने के लिए सबसे ज्यसादा पैसा इस बजट में रखती लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुद नहीं किया।

चेयरमैन साहब, 1978–79 में 63.54 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ था और 1979–80 में 60.10 लाख टन का लक्ष्य रखा गया। अब कहते हैं कि सूखा पड़ गया। 18.50 लाख टन पैदावार खत्म हो गई। अगर यह सरकार इस तरफ ध्यान देती तो किसानों को कभी नुकसान न होता। कहते हैं कि ओले पड़ गये तभी यह हालात पैदा हो गये। इस सरकार को इस बात का पहले ही ध्यान रखना चाहिये था कि कभी भी भगवान प्रकोप हो सकता है ओर सरकार को हर प्रकोप का सामना करने के लिए `पहले ही तत्पर रहना चाहिए था। अगर कहत का ध्यान इस सरकार ने रखा होता तो अव य ही किसानों को ट्यूबवैल्ज लगाकर देते और इस बात

की कभी कोताही न करते। बल्कि यह किया गया कि लोगों के जो ट्यूबवैल्ज थे, उनको टाइम पर पूरी बिजली भी नहीं दी गई। उनको केवल 5–6 घण्टे बिजली दी जाती थी, और वह भी रात के 11–12 बजे के करीब जो सुबह तक चलती थी और किसान बेचारे कडकती सर्दी में अपने खेतों को पानी देते थे। बहुत से किसानों को तो चेयरमैन साहब, नमूनिया भी हो गया। लेकिन सरकार ने उनकी तकलीफ की कतई परवाह नहीं की। चेयरमैन साहब, सरकार को पहले नम्बर पर खेती के लिए बिजली देनी चाहिए, दूसरे नम्बर पर उद्योगों को देनी चाहिए और तीसरा नम्बर हमारी सुविधाओं के लिये आता है, यानी घरों में हीटर, पंखे वगैरह चलाने के लिए आता है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, किसान को उसकी जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं दी गई, जिसके कारण लोगों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। इसके मुकाबले में सरकार भाहरों में 24 घण्टे बिजली देती रही है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य मेरे साथी हैं और हम जेल में भी इकट्ठे रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसानों को बिजली कम मिली। इनको भाायद याद नहीं कि चौधरी देवी लाल के राज मे .... (ाोर)

चौधरी गंगा राम: चेयरमैन साहब, ये मिनिस्टर हैं और इस तरह से हाउस में ..... कर रहे हैं। मिनिस्टर तो बाद में जवाब दिया करता है..... (ाोर)

चौधरी हुक्म सिंहः चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि उद्योगों को तो सुबह 8 बजे से भााम के 6 बजे तक बिजली दी गई लेकिन ट्यूबवैलों को अगर बिजली दी गई तो वह केवल 6 घंटे दी गई और वह भी आलटरनेटिव डेज पर। इससे हरियाणा की सारी फसल नश्ट हो गई। चेयरमैन साहब, बिजली की कमी की वजह से किसान ने डीजल पर चलने वाले ट्यूबवैल्ज लगाये ताकि वह कहत का मुकाबिला कर सकें लेकिन जो लोहे का चार इंच का पाइप बोरिंग के लिए होता है उसकी कीमत इस सरकार ने 8–9 रूपए से बढ़ाकर 25 रूपये कर दी और इसी तरह से इंजन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अगर इस बारे में सरकार से हम ि ाकायत करते हैं तो यह कहती हैं कि हमारे नोटिस में ऐसी बात नहीं है। इस तरह से किसान को लूटा गया। किसान ने दस दस हजार रूपये ट्यूबवैल पर लगाये लेकिन उसको डीजल नहीं मिला। किसान भाहर में डीजल लेने के लिए अगर किसी पैट्रोल पम्प पर जाता था तो वह वहां पर दो तीन दिन तक पड़ा रहता था। अगर डीजल मिलता था तो ब्लैक में चार रूपये लिटर के हिसाब से मिलता था। नागर साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि किस तरह से हरियाणा मे डीजल के मामले में धांधली हुई। ब्लैक में तो चाहे कोई जितना ले ले लेकिन वैसे नहीं मिला। अगर एक महीने में दस बीस लिटर मिलता था तो उससे सिर्फ एक दो दिन इंजन चलता था। इस तरह से किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई। चेयरमैन साहब, जो स्प्रिंकलर्ज लगाये जाते हैं, पहले सरकार इस पर 25 प्रति ात

सबसिडी देती थी लेकिन अब वह सबसिडी खत्म कर दी गई है। इनको चाहिए तो यह था कि ये किसान को और राहत देते लेकिन इन्होंने पिछली राहत भी खत्म कर दी। ये कहते हैं हमने किसानों को राहत दी। मालिया और आबियाना 6 महीने के लिए मुलतबी किया। जब किसान की सारी फसल ही नश्ट हो जाए तो 6 महीने के लिए मालिया या आबियाना मुलतबी करना कोई राहत नहीं। यह पूंजीपतियों की सरकार है ओर पूंजीपतियों को ही राहत दे रही है। चेयरमैन साहब, 68–69 लाख रूपया 50–60 बड़े बड़े कारखानेदारों को सबसिडी के तौर पर दिया गया लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। ये कहते हैं कि हमने तूड़ी और चारे पर सबसिडी दी। मैं सच्चाई से कहता हूं कि सरकार ने बीस रूपये क्विंटल के हिसाब से चारा सप्लाई किया लेकिन पता नहीं वह ठेका किस के पास था। ऐसा गला सड़ा चारा मिलता था जिसे प ाु खाते नहीं थे। लेकिन चूंकि किसान ने अपने प ाुओं को बचाना था इसलिए वह गला सड़ा चारा लेता रहा। अगर किसी ने इसके बारे मे ि ाकायत की तो ये सिर्फ यह कह देते थे कि हम इसकी इन्क्वायरी करेंगे। लेकिन इन्क्वायरी आज तक नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो इतना गंदा चारा सप्लाई किया गया उसकी जांच करवाई जाए। (विघ्न) जब हम बोलते हैं तो पोहलू भाई खड़े हो जाते हैं ओर कहते हैं कि ठहरो। मैं इनको कहता हूं कि ये चौधरी भजन लाल की फोटो गले में डाल लें। पोहलू साहब, आपका वही हाल होगा जैसे भैंस अपने कटड़े को थोड़ा ... . लात मार देती है। पोहलू साहब का कोई इखलाक नहीं

है, पहले ये कांग्रेस में थे फिर जनता पार्टी में आ गये थे और अब फिर कांग्रेस में चले गये। (ाोर)

श्री सभापतिः यह जो माननीय सदस्य के बारे में 'थन' का लफज कहा गया है इसको एक्सपंज किया जाए।

चौधरी हुकम सिंहः चेयरमैन साहब, मैं आपको बड़े बड़े कारखानों की बात बताऊं। दादरी में एक डालमिया सीमेंट फैक्टरी है। उसको उसके मालिकों ने बन्द कर रखा है। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर और मुख्य मंत्री जी को उस फैक्टरी के मजदूर मिले लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उस फैक्टरी का मालिक न तो सेल्ज टैक्स देता है और न ही चुंगी देता है। कोई भी पैसा हाथ में आए उसे हजम कर लेता है। आज वह फैक्टरी बन्द पड़ी हैं और 20 हजार मजदूर बेकार हुए बैठे हैं। भाहर के दुकानदारों का गुजारा भी उसी फैक्टरी पर है, लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नही ंदे रही। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगरउस फैक्टरी का मालिक उसे नहीं चलाना चाहता तो सरकार उस फैक्टरी को अपने हाथ में ले। चेयरमैन साहब, हमारे मंत्री जी ने बताया कि हम टैक्स की चोरी को बन्द करके बजट के घाटे को पूरा करेंगे। चेयरमैन साहब, आज हरियाणा में सेल्ज टैक्स की 50 प्रति ात चोरी होती है और अब इन्होंने और चोरी करने की छूट दे दी। पहले जहां दुकानदार को इस रूपये की कै ा मीमो काटनी होती थी अब इन्होंने उसे 25 रूपये तक छूट दे दी है। इसी तरह से दो लाख रूपये तक का हिसाब किताब रखने की

दुकानदार को छूट दे दी गई है। चेयरमैन साहब, इससे तो सेल्ज टैक्स की चोरी और भी बढ़ेगी।

चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं भाराब की बात पर आता हूं। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब तो मोरार जी भाई के बड़े नजदीकी आदमी थे। ये चाहते थे कि सारे दे ा में भाराब बन्दी करो लेकिन पता नहीं स्वामी आदित्यवे ा ने क्या सुझाव दिया, क्योंकि स्वामी जी मार्किट तला ा करने में बड़े होि ायार हैं। स्वामी जी ने हो सकता है कह दिया हो कि कोटा बढ़ा दो (ाोर) चेयरमैन साहब, पहले स्वामी जी भाराब के मामले पर बड़ा बोलते थे लेकिन अब पता नहीं क्या जादू हो गया है। मैं स्वामी जी का आद करता हूं ओर इनसे प्रार्थना करता हूं कि अब यह भगवा लिबास छोड़ कर सफेद लिबास पहन लें।

13.00 बजे

अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, इस वक्त हरियाणा में 2400 बसें काम कर रही है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हरियाणा की बसों की हालत ऐसी है कि कोई भी भारीफ आदमी अगर उनमें बैठ जाए तो उसके कपड़े फटे बगैर नहीं रह सकते। इसके अलावा देहातों मे बसों की संख्या कम है। लोग सुबह से भााम तक स अड्डों पर बैठे बसों की इन्तजार करते रहते हैं। जो एक आध बस आती है उसमें बैठने की जगह नहीं होती। इसलिए चेयरमैन

साहब मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो टैम्पू हैं उनका परमिट बनाया जाये ताकि आदमी दो या चार मील उनमें बैठ कर जा सकें क्योंकि लोग सुबह सड़कों पर आकर बैठते हैं और भााम तक बैठ कर अपने घर वापिस चले जाते हैं क्योंकि उनको जहां जाना होता है वहां नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से निवदेन करूंगा कि छोटे–छोटे रूट्स पर लोकल बसें चलाई जाएं ताकि लोगों को आने जाने में ज्यादा दिक्कत न हो।

चेयरमैन साहब, सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी इस बजट में बाते कही गई हैं। उनके बारे में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो बेचारे वर्क चार्ज एम्पलाईज हैं, जिनकी 10–10 और 15–15 साल की सर्विस हो चुकी हैं, वे अभी तक रैगुलर नहीं किए गए हैं और पे–कमी ान की सिफारि ों भी उनके ऊपर लागू नहीं हेाती हैं। चेयरमैन साहब, उन कर्मचारियों को रैगुलर किया जाए जो 5 साल की सर्विस पूरी कर चुका हो, ताकि वे इस पे–कमी ान की सिफारि ाों का फायदा उठा सकें। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि उनके मामले पर ध्यान दिया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

चौधरी गया लाल (हसनपुर–अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, मैं 1980–81 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदन को पता है कि पिछले साल जब बजट

पे ा किया गया था तो उस समय बाबू मूल चन्द जैन जी फाईनैंस मिनिस्टर थे। आज वे विपक्ष में लोकदल के लीडर हैं और जिस वक्त उन्होंने सदन में बजट पे रूा किया था तो उन्हीं की पार्टी के सदस्य चौधरी सतबीर सिंह, ने जो बाबू जी से पहले फाईनैंस मिनिस्टर रह चुके थे, बजट की कापियां फाड़ी थी क्योंकि उस बजट में कई प्रकार के टैक्स लगाए गए थे और किसानों पर टैक्स लगाए गए थे। सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने कापियां फाड़ी थी उन्हीं सदस्यों ने जो आजकल लोकदल के सदस्य हैं, अपने वक्त में किसानों पर टैक्स लगाए थे, जैसे यात्री कर लगाया था और कई प्रकार के टैक्स लगाए थे। सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने जो बजट पे ा कियसा है, यह हमारे वित्त मंत्री जी के प्रयत्नों से और इस विभाग के अधिकारियों के प्रयत्नों से बहुत ही सर्व प्रिय है तथा बहुत ही सुन्दर बजट है। सभापति महोदय, बैकवर्ड क्लासिज की रिजर्वे ान के बारे में कल एक प्रस्ताव सदन में रखा गया ाि तो मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों की ही पार्टी के माननीय सदस्य चौधरी हरस्वरूप बूरा जी ने जो लोकदल पार्टी के अच्छे वक्ता हैं और हमे ाा ही इस हाउस में प्रस्ताव रखते रहते हैं, उन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपने विचारों को हाउस के सामने प्रकट किया। सभापति महोदय, इस दे ा का संविधान मानता है कि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको समानता देने के लिए, बराबरी में लाने के लिए रिजर्वे ान होनी चाहिए। आरक्षण दे कर उनको एक सतह पर लाना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय साथी हरस्वरूप बूरा जी ने यह कहा कि

इस आरक्षण पर एक आग फैल रही है और वह आग एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटेगी। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की बातों को हाउस के सामने भाण्डा फोड रहा हूं जिनकी पार्टी के सदस्य रोजाना यहां हाउस में बैकवर्ड क्लासिज की बात भुरू करके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पता नहीं उनकी बैकवर्ड क्लासिज से कितनी हमदर्दी है। सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब लोक सभा के चुनाव हुए तो मेरे लोकदल के साथियों ने हरिजन भाईयों को वोट नहीं डालने दिए ..... (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः चेयरमैन साहब, चौधरी गया लाल जी यह बात करते हैं कि हरिजनों को वोट नहीं डालने दिए गए तो मैं इनको बिहार, यू.पी., मध्य प्रदे ा और राजस्थान में ऐसे कांग्रेसी बता देता हूं जोकि हरिजनों को अपनी चारपाईयों पर भी नहीं बैठने देते। ये लोकदल की बात करते है।

चौधरी गया लालः सभापति महोदय, लोक दल की तरफ से आज सदन में बातें कही गई इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। यह मैं कोई झूठी बात नहीं कह रहा हूं। सभापति महोदय, बैकवर्ड क्लासिज और भाड्यूल्ड कास्टस में कोई अन्तर नहीं है। जिन लोगों ने बैकवर्ड क्लासिज के लिए प्रस्ताव हाउस में रखा था उन्हीं लोगों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया। सभापति महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको यह आ वासन दिया कि जो बैकवर्ड क्लासिज की रिजर्वे ान 5 से 10 प्रति ात की गई थी

उसको पूरा इम्पलीमेंट करेंगे ओर बैकवर्ड क्लासिज के लिए डिवैल्पममैंट बोर्ड बनायेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि एस.एस.एस. बोर्ड का भी हमने एक सदस्य बैकवर्ड क्लास का बनाया हुआ है। सभापति महोदय, हरिजनों के लिए रिजर्वे ान 32 साल से चली आ रही है ओर अभी तक पुलिस विभाग में 5 प्रति ात भी भाड्यूल्ड कास्टस के लोग नहीं हैं इसीलिए हरिजनों के साथ, बैकवर्ड क्लासिज के साथ ओर आदिवासियों के साथ जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक पुलिस विभाग में इन वर्गों के लोगों का आरक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पुलिस विभाग में अभी तक इन वर्गों से जो आरक्षण के हिसाब से भर्ती पूरी होनी चाहिए चाहे सिपाही की भर्ती है, चाहे हवलदार है, चाहे ए.एस.आई. है और चाहे डी.एस.पी. है आरक्षण अव य पूरा होना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, आरक्षण के हिसाब से इस विभाग में इन लोगों की भर्ती कर दी जाए तो घटनाएं भी कम हो सकती हैं। सभापति महोदय, अब मैं कृशि के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस बजट में 20 करोड़ रूपया, कृशि के लिए, साढ़े 13 करोड़ सिंचाई के खाल पक्के करने के लिए रखा है तथा इसी तरीके से और कामों के लिए काफी पैसा रखा है। इसके अलावा, अगर सरकार की तरफसे बिजली और पानी का प्रबन्ध हो जाए तो मैं समझता हूं किसानों के साथ सरकार का बहुत बड़ा उपकार होगा। किसानों को अब तक जो सुविधायें दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य

पानी का है, चाहे एस.वाई.एल. के द्वारा पानी दो, चाहे एम.आई.टी. सी. के द्वारा पानी दो, लेकिन किसानों के खेतों को पानी मिलना चाहिए। ि ाक्षा के क्षेत्र का जहां तक ताल्लुक है, बजट स्पीच में वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि 151 प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूल और 158 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया है, सरकार का यह सराहनीय कदम है। 12 कालेज टेक ओवर करके भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि ये कालेज फेल हो रहे थे, प्रोफैसरों को तीन तीन, चार चार वर्श तक की तन्खाहें नहीं मिलती थी, प्राइवेट मैनेजमैंट्स ठीक तरह से इन्तजाम करने में असमर्थ थीं, इन हालात को देखते हुए सरकार ने कालेजों को अपने अधीन लेकर बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे हल्के होडल का कालेज भी सरकार ने लिया है, इसके लिए मैं चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूं।

अब मैं ि ाक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। जो हरिजन कर्मचारी लड़के दिन में, कालेजों में ि ाक्षा ग्रहण करते हैं उनसे फीस नहीं ली जाती लेकिन जो सरकारी हरिजन कर्मचारी नाईट कालेजिज में पढ़ते हैं, उनसे फीस ली जाती है, यह ठीक नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि जैसे पंजाब सरकार ने कर रखा है कि जो सरकारी कर्मचारी, चाहे वे दिन में पढ़ते हैं, चाहे रात को पढ़ते हैं, हरिजन कर्मचारियों से फीस नहीं लेते, इसी तरीके से हरियाणा सरकार को भी करना चाहिए ताकि हरिजनों को ि ाक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो।

चेयरमैन साहब, अब मैं थोड़ा सा आरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं। आरक्षण के बारे में वैसे तो पहले भी काफी कुछ कहा जात चुका है, बूरा साहब ने भी कहा है कि हर दस साल के बाद जो आरक्षण का सवाल पैदा होता है, इससे लोगों को बड़ा दु:ख होता है। मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि 32 साल के बाद भी आरक्षण 10 परसैंट से ज्यादा पूरा नहीं हुआ। मैं स्पश्ट कहना चाहता हूं कि बार बार आरक्षण करने की जरूरत नहीं है, अगर सरकार द्वारा 5 साल के अन्दर अन्दर आरक्षण पूरा कर दियसा जाए तो फिर रिजर्वे ान रखने की आव यकता नहीं रहेगी। असल में इसकी इम्पलीमैंटें ान ठीक तरह से नहीं होती। वैसे तो हरिजनों के लिए जो रिजर्वे ान रखी है, इसको पूरा करने के लिए हमारे सी.एम. का पूरा ध्यान है, लेकन इसके साथ ही साथ एक कमेटी गठित कर दी जाए जो कमी रह गई हैं उसको आने वाले समय में पूरा किया जा सके।

श्री सभापतिः आपका समय होने वाला है, एक मिनट रहता है।

चौधरी गया लालः दूसरे मैम्बर साहिबान को आपने 15–15 मिनट दिए हैं, मुझे भी 15 मिनट मिलने चाहिएं। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, हरिजन कल्याण विभाग की तरफ से, प्राईमरी स्कूलों में पढ़ने वाली हरिजन कन्याओं के लिए 10 रूपये प्रति मास छात्रवृति देने का प्रावधान जो सरकार ने बजट में किया हैं, यह बड़ा भाोभनीय काम है। इसी तरह से 9वीं, 10वीं, तक तथा

10वीं से 14वीं तक जो सरकार की तरफ से वजीफा मिलता था उसको 8 रूपये से बढ़ाकर 16 रूपये तथा 15 रूपये से बढ़ा कर 35 रूपये कर दिया है। सरकार ने यह सबसे अच्छा कार्य किया है क्योंकि हरिजन बच्चो को ि ाक्षा हासिल करने में इससे काफी सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार हरिजन कल्याण निगम हरिजनों को कर्जे देती है। चेयरमैन साहब, इसी तरह का निगम पंजाब प्रान्त में भी बना हुआ है लेकिन पंजाब में जो हरिजन निगम से 10 हजार रूपया ऋण लेता है, उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाता यानी 10 हजार तक कोई सूद नहीं लिया जाता। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा और हाउस में मांग करता हूं कि पंजाब गवर्नमैंट के पैट्रन पर हरिजन भाइयों को उद्योग लगाने के लिए, हरिजन कल्याण निगम से जो पैसा मिलता है, उस पर कोई सूद न लिया जाए, बगैर सूद के ऋण दिया जाए ताकि ये गरीब आसानी से उद्योग धंधे लगा सकें। मेवात का एरिया सबसे ज्यादा पिछडा हुआ इलाका है, मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाने के एि मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पिछड़े इलाके में लोगों के लिए बोर्ड बनाया है, गरीबों पर यह बड़े ही उपकार की बात है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज के लिए, पिछड़े वर्ग को दूसरी जातियों के बराबर लाने के लिए जो सी.एम. साहब ने आ वासन दिया है कि बोर्ड बनायेंगे, यह इन पर बड़ा भारी उपकार करेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन साहब, इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

डा. बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी): चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री साहब ने 10 तारीख को बजट पे ा किया और 11 तारीख को अखबारों में खबर आई कि 'नो न्यू टैक्सिज इन हरियाणा'। भाायद हमारे वित्त मंत्री साहब, इस खबर को सुनकर खु ा हुए होंगे, अब भी वे खु ा ही नजर आ रहे हैं। इसके अगले दिन सैन्ट्रल गवर्नमैंट का इन्टैरिम बजट पे ा हुआ जिसकी खबर भी अखबारों में आई, लिखा था 'नो न्यू टैक्सिज इन इन्टैरिम बजट'। जहां यह लिखा हुआ था, वहां हरियाणा के बजट के बारे में यह भी लिखा हुआ था कि बजट में 46 करोड़ रूपये का घाटा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस घाटे को किस तरीके से पूरा करेंगे, कहां से पैसा आयेगा, कैसे बचत करेंगे ? आपने कहा कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट से लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो टैक्स लगायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बजट रखा है यह तो जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात हैं आज हरियाणा के अन्दर जो सबसे बड़ा अहम मसला है, उसके बारे में इस बजट के एक लफ्ज भी नहीं कहा है। अहम मसला है टैक्नोक्रेट्स का जिन्होंने हरियाणा सरकार को यह कह दिया कि अगर उनके साथ न्याय नहीं किया गया, उनके वेतनों में पड़े हुए भेदभाव को ठीक नहीं किया गया तो वे 21 तारीख से सारी स्टेट में स्ट्राईक पर चले जायेंगे। टैक्नोक्रेट्स जो इंजीनियर हैं, डाक्टर हैं, एग्रीकल्चर महकमें के एक्सपर्ट्स हैं, इसी तरह दूसरे डिपार्टमैंट्स में हैं, जो भी हैं, वे टैक्नीकल आदमी हैं और इनकी डिमांड जायज है।

चेयरमैन साहब, टैक्नीकल एक्सपर्ट्स का इस समाज के अन्दर ही नहीं बल्कि वि व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्टरनै ानल लैवल पर दे ा का निर्माण करने में इनका वि ोश योगदान होता है, इनके बिना कोई भी समाज, कोई भी राश्ट्र आगे नहीं बढ़ कसता। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि बजट में इस क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। 1–2–1969 तक टैक्नोक्रेट्स की तन्खाहों और इनके बराबर का स्टेटस रखने वाली दूसरी सर्विसिज की तन्खाहों में कोई फर्क नहीं था। एक ही स्केल हुआ करता था, लेकिन एमरजेंसी के अन्दर 1–1–1977 को फर्क डाल दिया गया और उससे पहले उनके साथ जो इन्साफ होता था वह भी नइसे सहा न गया। पहले उनके ए.सी.आर. डिपार्टमैंट लिखता था लेकिन वह ए.सी.आर. लिखने का काम भी ऐग्जैक्टिव के हाथ में दे दिया गया। मुझे कहते हुए दुख होता है कि टैक्नोक्रेट्स के ए.सी.आर. नोन टैक्नीकल आदमी लिखते हैं। पिछले साल हमारे मुख्य मंत्री जी ने उन इंजीनियर्ज को तो कैटेगराइज कर दिया था लेकिन मैडिकल प्रोफै ान वालों को नहीं किया था। वे भी कैटेगराज होने चाहिएं। अब जो हैरानी की बात है वह यह है कि पे–कमी ान की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तनख्वाह और भी कम हो जाएगी। पंजाब के पे–कमी ान ने ऐसा नहीं किया लेकिन हरियाणा के पे–कमी ान ने उनकी तनख्वाह को कम कर दिया है। इसी कारण से वे 21 तारीख को स्टेट के अन्दर स्ट्राइक करने वाले हैं। मेरी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि वे इस बात को सोचे कि जिनके सहारे हमारी स्टेट ही नहीं, हमारा दे ा ही नहीं

बल्कि सारी दुनिया बड़ी हैं, उनके साथ अगर हम भेदभाव करेंगे तो इस स्टेट का क्या हाल होगा और इस दे ा का क्या हाला होगा ? जो समाज में एक क्रीम माने जाते हैं, जो पढ़ते वक्त मेहनत करते हैं ओर बाद में भी काम करते वक्त सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके साथ अगर भेदभाव हो तो बड़ा दुख होता है। तो मेरी यह प्रार्थना हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए।

चेयरमैन साहब, गवर्नमैंट ऐम्पलाइज के बारे में जो कहा गया है कि बाल्मीकियों का 50 रूपये महीना बढ़ाया गया है और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई है, इसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि पहला आर्डर 31 दिसम्बर तक का था। उसकी ऐक्सटैन् ान का आर्डर कई जगह अभी तक नहीं पहुंचा। जगाधरी में फरवरी के महीने में पहुंचा। (विघ्न) इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि यह तो जनता पार्टी की देन है।

चेयरमैन साहब, सारी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं कि भारतवर्श के 70 से 80 फीसदी तक लोग देहातों में रहते हैं और उनका गुजारा खेती पर या खेती से बाबस्ता चीजों पर है। इरीगे ान के मामले में इन्होंने ज्यादा जोर एस.वाई.एल. पर दिया है। हम तो अढ़ाई साल से एस.वाई.एल. का नाम सुनते आ रहे हैं। अगर अब भी यही हालत रही, जैसा कि कहा गया है कि केस सुप्रीम कोर्ट में है और उसका फैसला होते काफी देर लगेगी, तो मेरी समझ मैं नहीं आता कि इस हरियाणा का क्या बनेगा ? (विघ्न) अम्बाला जिले में इरीगे ान के मुताबिक इन्होंने

बजट में एक भी बात नही कही है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर जितनी भी इरीगे रूान की स्कीम्ज दूसरी जगहों के लिए बनाई जा रही हैं, उनका सारा पानी अम्बाला जिला से जाता है। यह कहां का इन्साफ है कि हमारे ही पानी से हमें महरूम रखा जाए ? बरसात में तो वह पानी हमारे यहां तबाही करता हैं लेकिन बाद में देखने को भी नहीं मिलता। कम से कम कृपा करके टांगरी और मारकंडा नदियों के ऊपर बांध तो लगा दो। उसका हमें भी तो कुछ लाभ उठाने दो। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, पावर के बारे में भी इन्होंने बड़ी बातें कही हैं। आप जानते हैं कि इरीगे ान के लिए भी पावर की जरूरत होती हैं क्योंकि ट्यूबवैल्ज पावर से चलते हैं। मैं अपने तजुर्बे से बताता हूं कि रबी की सारी फसल के दौरान कंटिन्यूअसली पांच घंटे बिजली नहीं आई। अब आप देखें कि जब कंटिन्युअसली ट्यूबवैल को बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे खेती होगी ? यह सही बात है कि जिस गेहूं को पांच पानी मिलने चाहिए उसको एक पानी भी नहीं मिला। ये कहते हैं कि हम गेहूं की फसल काफी मात्रा में लेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि पचास परसैंट से ज्यसादा फसल तो खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए बजट लाए हैं। मैं तो इनसे चाहूंगा कि कम से कम इस बारे में ये अपने महकमें को तो पूछ लें। खासतौर पर हमारे इलाके जगाधरी–यमुनानगर में तो बिजली

का कोई भाड्यल नहीं है। पावर भाार्टेज की वजह से इंडस्ट्रीज की हालत खराब है। यही हालत इरीगे ान के क्षेत्र में हैं। दिन मैं ट्यूबवैल के लिए बिजली नहीं मिलती, रात को मिलती है। आप सोचें बेचारा किसान रात को खेतों में कैसे पानी दे ? गर्मियों में भी पानी देते हुए उसकी बुरी हालत होती है। (विघ्न) इन्होंने कहा है कि यमुनानगर में एक मइकरो हाइडल प्राजैक्ट बना रहे हैं लेकिन मुझे तो पता लगा है कि वह खटाई में पड़ गया है। फिर इन्होंने कहा है कि दो–दो सौ मैगावाट के चार यूनिट्स का थर्मल प्लांट लगाएंगे। पिछले साल भी यह आ वासन दिया गया था और इस बार भी कहा गया है लेकिन हमें तो उसके लगने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मार्किटिंग बोर्ड के बारे में कहा गया है कि 22 नई मंडियां बनाएंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Doctor Sahib, please take your seat. I have to make an announcement.

उपाध्यक्ष द्वारा रूलिंग

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव सम्बन्धी

Mr. Deputy Speaker: Notice of No-Confidence Motion against the Hon. Speaker given by Sh. Mool Chand Jain and other respected members of this House, was received today, the 14th March, 1980 at 9.45 A.M.

As the motion was against the Hon. Speaker himself, he, therefore, considereed it appropriate to refer it to me for taking a decision thereon and, as such, I have examined it thoroughly keeping in view the constitutional and legal aspects thereof. Before a final decision is announced, I would like to refer to Article 179(c) of the Constitution of India, which reads as under:-

"179. Vacation and resignation of and removal from the office of the Speaker..... A member holding office as Speaerk of an Assembly."

(c) May be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly;

Provided that no resolution for the purpose of clause(c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution.

This notice is short of that period. Hence, it cannot be entertained. All the members of the Haryana Vidhan Sabha are fully aware that the House is to adjourn sine-die on 19th or at the most 20th or 21st instant. If they had any idea of giving such a notice then they shou8ld have thought patiently and should have given 14 days notice before the programme set for the session. In addition to it, the notice for removal of the Speaker, rather, they have given notice of no-confidence motion against the Speaker. All the members of the opposition are taking this matter very lightly and giving the notice of this sort and then withdrawing the same. They should not have taken it in such a light manner against such an august office.

It has two/three defects. Hence it is disallowed. (Interruptions.)

The House now stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow, the 15th March, 1980.

13.30 बजे

(The Sabha then adjourned till 9.00 Hours on Saturday, the 15th March, 1980.)